राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

रथ यात्रा में शामिल हुईं नुसरत ने कहा–सभी धर्मों का करती हूं सम्मान
>> 10

वर्ष 3 अंक 25

दैनिक जागरण

मूल्य ₹5.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 5 जुलाई 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

तेज विकास और 'नए भारत' के लिए सुधारों पर जोर

आर्थिक सर्वे 2018-19 ▶ सरकार ने दिखाया पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था का ब्लूप्रिंट

चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रगति की रफ्तार सात फीसद रहने का लगाया गया है अनुमान

हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को दूसरे कार्यकाल में तेज विकास के लिए चौतरफा सुधार संबंधी कदम उठाने होंगे। शुक्रवार को पेश होने वाले आम बजट से पहले गुरुवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले वित्त वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वे की रिपोर्ट से साफ हो गया है कि बजट में 'न्यू इंडिया' के खाका के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डॉलर (वर्तमान भाव पर 375 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंचाने का रोडमैप भी होगा। अर्थव्यवस्था के इस आकार के लिए देश को सालाना आठ विकास दर की दरकार होगी। विकास दर के इस स्तर को सिर्फ बचत, निवेश और निर्यात के 'सद्चक्र' से बनाए रखा जा सकता है। वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 2.75 लाख करोड़ डॉलर है।

सीतारमण आम बजट में सुधारों की दिशा में कदम उठाते हुए बचत, निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपायों का एलान कर सकती हैं। साथ ही वह रोजगार बढ़ाने के लिए एमएसएमई और खासकर नई कंपनियों को प्रोत्साहन और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बजटीय प्रावधान भी कर सकती हैं। बहुप्रतीक्षित श्रम सुधार और विधि सुधारों के क्रियान्वयन का रोडमैप भी इस बजट में पेश होने की उम्मीद है।

'ब्लू स्काई थिंकिंग' यानी नए विचारों पर आधारित आर्थिक सर्वेक्षण, 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था को देखने के परंपरागत एंग्लो-सेक्शन दृष्टिकोण को त्यागकर देश की समस्याओं को व्यावहारिक अर्थशास्त्र के आईने से देखने की कोशिश की गई है। अब तक भारत पश्चिमी देशों के आर्थिक मॉडल का अनुसरण करता रहा है। लेकिन सर्वे में पूर्वी एशियाई देशों से सीखने की जरूरत पर बल दिया गया है।

चालू वित्त वर्ष में देश की विकास दर सात फीसद रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 6.8 फीसद रह गई, जो पिछले पांच वर्षों के न्यूनतम स्तर पर थी। फिलहाल अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र के खस्ताहाल, निवेश की सुस्त रफ्तार, बेरोजगारी और अपेक्षा से कम जीएसटी संग्रह के चलते राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने की चुनौती का सामना कर रही है।

सर्वेक्षण में विकास दर को गति देने के लिए चीन जैसे अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से सीखते हुए बचत, निवेश और निर्यात को बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया गया है। वहीं खाद्य सब्सिडी का बोझ घटाने और चालू खाता घाटे को पाटने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में बदलाव की सिफारिश भी की गई है।

लोकसभा में संसद के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे 2018-19 की रिपोर्ट पटल पर रखी। प्रेट्र

बजट के संकेत

- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए होंगे ज्यादा प्रयास
- बचत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए टैक्स प्रोत्साहन
- नई कंपनियों को मिलेगा बढ़ावा
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं के फोकस में बदलाव

11 बजे पेश होगा बजट

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी। खास बात यह है कि निर्मला देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी 1970 में आम बजट पेश किया था लेकिन वह पूर्णकालिक वित्त मंत्री नहीं थीं बल्कि उनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार था।

लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार को करने होंगे ये उपाय

सर्वे में लघु, मझोले उद्यमों खासकर नई कंपनियों को मदद देने तथा छोटी कंपनियों को बड़ी बनाने के लिए श्रम सुधारों को लागू करने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के कर्ज के दिशा निर्देशों में बदलाव की जरूरत पर बल दिया गया है। भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने के लिए बैटरी और चार्जिंग सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने को कहा गया है। सरकार आम बजट 2019-20 में इस दिशा में उपायों की घोषणा कर सकती है। साथ ही वर्ष 2040 में भारत की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। सर्वे में सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी अधिसूचित करने की वकालत भी सर्वे में की गई है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खासकर कृषि क्षेत्र की स्थिति सुधारने के लिए डेयरी, पशुपालन और मत्स्यपालन की गतिविधियों को बढ़ाने तथा सिंचाई में जल के किफायती इस्तेमाल की जरूरत पर भी सर्वे में जोर दिया गया है। मोदी सरकार की उन योजनाओं में 'बदलाव' की वकालत की गई है जो आम लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए शुरू की गई हैं। इसके तहत 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना का फोकस 'बदलाव' (बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी), 'स्वच्छ भारत' से 'सुंदर भारत' पर हो सकता है। इसी तरह टैक्स देने से बचने की संस्कृति को बदलकर टैक्स नियमों के अनुपालन पर जोर देने का भी सुझाव दिया गया है।

जारी रहे स्वच्छता से स्वास्थ्य और सुंदरता तक की यात्रा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- स्वच्छ भारत से हो रहा है स्वस्थ भारत का निर्माण
- स्वच्छ भारत को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ सुंदर भारत बनाने पर जोर

बीते वित्त वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत मिशन जैसे अभियानों की जमकर तारीफ करते हुए इन्हें जारी रखने के साथ ही और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। इसमें विभिन्न अध्ययन और सर्वेक्षण और रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि किस तरह स्वच्छ भारत मिशन एक स्वस्थ्य भारत के निर्माण में मदद कर रहा है। इसमें पर्यावरण संरक्षण को शामिल कर सुंदर भारत के निर्माण की दिशा में ले जाने की सलाह दी गई है।

2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ स्वच्छता तक सीमित नहीं है। बल्कि स्वस्थ्य भारत का भी निर्माण कर रहा है। गंदगी के कारण बच्चों में दस्त की एक सामान्य बीमारी है। इसके अनुसार स्वच्छ भारत मिशन शुरू होने के पहले 2013 में पांच साल के कम उम्र के 11 फीसदी बच्चों की मौत की वजह गंदगी के कारण होने वाली दस्त की बीमारी थी। मिशन शुरू होने के बाद इसमें लगातार कमी आ रही है। इसी तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने अध्ययन में पाया कि 2014 में जहां गंदगी की वजह से होने वाली दस्त से एक लाख 40 हजार लोगों की मौत हुई थी, वहीं स्वच्छ भारत मिशन के बाद इसमें 2017-18 में 50 हजार की गिरावट आई।

बात सिर्फ गंदगी से होने वाली बीमारियों से मौतों तक सीमित नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन के बाद शिशु मृत्युदर में कमी के साथ-साथ जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों की संख्या में कमी और मृत शिशुओं के जन्मदर में कमी देखी गई है। 2019 में 100 फीसदी कचरा प्रबंधन करने वाले जिलों और इसमें विफल रहने वाले जिलों में स्वास्थ्य मानकों का तुलनात्मक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में पाया गया कि 100 फीसदी कचरा प्रबंधन वाले जिलों में डायरिया के साथ-साथ मलेरिया के मामलों में भी कमी आई है। 2017 में जहां गैर ओडीएफ जिलों में दो साल के कम उम्र के 18.1 प्रतिशत बच्चों और दो साल से पांच साल तक की उम्र के 10.2 प्रतिशत बच्चों को डायरिया हुआ था। वहीं ओडीएफ वाले जिलों में यह आंकड़ा 12.1 और 6.9 प्रतिशत था। इस तरह स्वच्छ भारत मिशन सचमुच में स्वस्थ्य भारत का निर्माण का भी काम कर रहा है।

आर्थिक सर्वेक्षण में स्वच्छ भारत मिशन से होने वाले आर्थिक लाभ का आकलन प्रस्तुत किया गया है। इसमें विश्व बैंक के 2006 के अनुमान का हवाला दिया गया है कि जिसके अनुसार भारत में गंदगी से होने वाली बीमारियों के कारण प्रति व्यक्ति नुकसान 2180 रुपये, यानी औसत प्रति व्यक्ति आमदनी का 6.4 फीसदी था। इसी तरह यूनिसेफ ने भी स्वच्छ भारत मिशन के आर्थिक प्रभावों का अध्ययन किया। शौचालय के प्रयोग करने और हाथ धोने की आदत और नजदीक में शौचालय की उपलब्धता के कारण पहले खुले में शौच करने वाले गांव की तुलना में प्रति परिवार औसतन 50,000 रुपये की सालाना बचत हुई।

स्वच्छ भारत मिशन के बीमारियों के साथ-साथ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान में मदद मिली है। स्कूलों में शौचालयों के निर्माण होने के कारण बालिकाओं के नामांकन अनुपात में बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे भी जारी रखने की जरूरत बताते हुए कहा कि दशकों से देश में जनसंख्या में महिलाओं की संख्या में आ रही गिरावट को रोकने मदद मिली है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन को अब पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर स्वस्थ भारत के साथ-साथ सुंदर भारत की दिशा में भी कदम बढ़ाने को कहा गया है।

सर्वेक्षण का संदेश : युवा भारत को अब बढ़ती उम्र के लिए होना पड़ेगा तैयार पेज>>6

न्यायिक सुधारों पर रहेगा अगले पांच साल में खास जोर पेज>>6

सरोकार

बागली वासियों ने दिया कालीसिंध को नवजीवन

देवास : मध्य प्रदेश के देवास जिले कालीसिंध नदी का बड़ा हिस्सा जल विहीन हो चुका था। ऐसे में जनता ने खुद बीड़ा उठाया। उन्होंने नदी के गहरीकरण के साथ ही उसे सहेजना शुरू किया। आज नदी में भरपूर पानी है। जल संवर्द्धन की प्रेरक कहानी। (पेज-13)

जागरण विशेष

समलैंगिकों की इच्छा, अपना भी हो बच्चा

आगरा : समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिलने के बाद अब ऐसे जोड़े परिवार बढ़ाना चाहते हैं। ये तभी संभव है जब वे बच्चा गोद ले सकें या किराए की कोख से बच्चे को जन्म दे सकें, लेकिन कानून आड़े आ रहा है। इस पहलू पर प्रकाश डालता एक ताजा अध्ययन। (पेज-13)

क्रिकेट महाकुंभ
बांग्लादेश vs पाकिस्तान
दोपहर 3:00 बजे से
स्थान : लंदन
स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

आतंक पर पाकिस्तान की कार्रवाई दिखावा : भारत

- विदेश मंत्रालय ने कहा, सबको पता है दाऊद का ठिकाना
- गृह राज्यमंत्री रेड्डी बोले, आतंकवाद पर कतई गंभीर नहीं पाकिस्तान

नई दिल्ली, प्रेट्र/एएनआइ : पाकिस्तान द्वारा मुंबई हमले के साजिशकर्ता हाफिज सईद और उसके साथियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज किए जाने को भारत ने दिखावा और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करार दिया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, हमें आतंकी समूहों के खिलाफ पाक के दिखावे वाले कदमों के झांसे में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान आतंकी समूहों और आतंकियों पर कार्रवाई को लेकर कितना गंभीर है, इसका फैसला सत्यापन योग्य, विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय कार्रवाई को प्रदर्शित करने की उसकी क्षमता के आधार पर किया जाएगा। पाक को आतंकी समूहों पर ऐसी कार्रवाई करनी होगी जिसे बार-बार बदला न जाए। आधे-अधूरे कदम उठाकर पाक सिर्फ अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आंखों में धूल झोंकता रहा है। हम पाक के साथ आतंकमुक्त माहौल में सामान्य संबंध चाहते हैं। जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया कि क्या भारत ने एफएटीएफ को दाऊद को लेकर भी कोई रिपोर्ट दी है? इस पर उन्होंने कहा, 'दाऊद इब्राहिम की लोकेशन अब कोई रहस्य नहीं है। हम उसे कई बार ऐसे लोगों की लिस्ट सौंप चुके हैं जो पाक में हैं। हम कई बार उनसे ऐसे लोगों को भारत को सौंपने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का दावा करता है, लेकिन जब हम ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने को कहते हैं जो साफ तौर पर आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं तो वह मुकर जाता है। वहीं, दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ये दोहरे मापदंड हैं। जब भी वे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं तो खुद-ब-खुद दुनिया के सामने उजागर हो जाते हैं।'

गृह राज्यमंत्री रेड्डी ने कहा, 'पाकिस्तान जो करता है वह नकली है। वे सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन वे गंभीर नहीं हैं। वे सिर्फ लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वे आतंकवाद के खिलाफ हैं। हम जानते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाक क्या करता है। सेना आतंकियों को प्रशिक्षण देती है। वहां बहुत सारे (आतंकी) शिविर चल रहे हैं। पाक में कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। प्रधानमंत्री इमरान खान सेना की कठपुतली हैं। वह (इमरान खान) वही करते हैं जो सेना उनसे करने के लिए कहती है। उन्होंने आतंकियों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहता है। हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ काम करेंगे।' रेड्डी ने कहा, पाकिस्तान का आतंकवाद के मामले में चेहरा बेनकाब हो गया है। उस पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं है।

पाक में पुलिस ने कहा-गिरफ्तार किए जाएंगे हाफिज सईद और उसके साथी पेज>>11

तिब्बती मुद्दा अब सियासी आजादी के लिए संघर्ष नहीं : दलाई लामा

नई दिल्ली, प्रेट्र : तिब्बतियों के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने कहा है कि तिब्बती मुद्दा अब राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नहीं रहा। लेकिन उन्होंने इसपर जोर दिया कि तिब्बत की सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषायी पहचान के संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत है।

दलाई लामा ने सवाल किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता मुख्य तौर पर लोगों की खुशी के लिए होती है लेकिन क्या वह अकेले खुशी की गारंटी हो सकती है। उन्होंने एक समाचार पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में कहा, 'चीन में शीर्ष नेताओं में यह भावना बढ़ रही है कि उनकी नीतियां तिब्बत मुद्दे को गत 70 वर्षों में हल नहीं कर पायी हैं। इसलिए उन्हें अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यद्यपि तिब्बत एक स्वतंत्र देश था आज चीन का तिब्बत पर राजनीतिक रूप से कब्जा है।'

तिब्बती धर्म गुरु ने कहा, 'वर्तमान परिस्थितियों में मैं कुछ समय से कह रहा हूं कि तिब्बत की सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषायी पहचान के संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत है। अब यह राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नहीं रहा।' उन्होंने इसमें यह भी कहा कि तिब्बती लोग जब तक अपनी हजारों वर्ष पुरानी विरासत, धर्म और पहचान को संरक्षित रख पाएंगे, वह उन्हें आंतरिक शांति और खुशी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, 'मैं इसके लिए भारतीय संघ की उसकी विविधता में एकता की प्रशंसा करता हूं। इसी तरह से तिब्बत की सांस्कृतिक, भाषायी और धार्मिक पहचान को बरकरार रखते हुए चीनी जन गणराज्य और तिब्बत सह अस्तित्व में रह सकते हैं।'

इंजीनियर से बदसलूकी करने वाले कांग्रेस विधायक नीतेश राणे गिरफ्तार

देश में माननीयों की मनमानी व दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी आकाश विजयवर्गीय का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि गुरुवार को मुंबई में कांग्रेस विधायक नितेश नारायण राणे ने अपने समर्थकों के साथ इंजीनियर प्रकाश शेडेकर को कीचड़ से नहला दिया। प्रेट्र

मुंबई, प्रेट्र/एएनआइ : महाराष्ट्र पुलिस ने एक हाईवे इंजीनियर के साथ बदसलूकी के आरोपित कांग्रेस विधायक नीतेश राणे और महाराष्ट्र स्वाभिमान पार्टी (एमएसपी) के पांच कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई-गोवा हाईवे पर गड्ढों के विरोध में राणे और उनके समर्थकों ने गुरुवार सुबह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के डिप्टी इंजीनियर प्रकाश शेडेकर पर कीचड़ डाला था, उन्हें पुल से बांधने की कोशिश भी की थी।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और एमएसपी के अध्यक्ष नारायण राणे के पुत्र नीतेश की यह हरकत कैमरे में कैद हो गई थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पूरे प्रदेश में पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया था। पीड़ित इंजीनियर की शिकायत पर राणे और उनके समर्थकों के खिलाफ सिंधुदुर्ग जिले में सरकारी काम में बाधा डालने, अधिकारी के साथ बदसलूकी और हमला करने से संबंधित आइपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इससे पहले, सिंधुदुर्ग के एसपी दीक्षित गेदाम ने कहा था कि इस मामले में नीतेश राणे को हिरासत में ले लिया गया है। यह घटना तटवर्ती सिंधुदुर्ग जिले के कांकावाली में हुई थी। नीतेश राणे कांकावाली से ही विधायक हैं। समाचार एजेंसी एएनआइ द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में नीतेश राणे और उनके समर्थक शेडेकर पर कीचड़ डालते देखे जा सकते हैं। यह भी कहा गया कि राणे ने शेडेकर को गडनदी के पुल पर बांधकर रखा था।

- मुंबई-गोवा हाईवे पर गड्ढों के विरोध में अधिकारी पर डाला था कीचड़

बेटे की करतूत पर पूर्व सीएम नारायण राणे ने मांगी माफी पेज>>4

मानहानि मामले में राहुल-येचुरी ने खुद को बताया निर्दोष

मुंबई : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके राहुल गांधी और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने गुरुवार को अदालत में स्वयं को निर्दोष बताया। इससे साफ हो गया है कि वे इस मुकदमे का सामना करेंगे। राहुल और येचुरी ने बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के लिए आरएसएस और उसकी विचारधारा को दोषी ठहराया था। दोनों नेताओं के बयान के बाद आरएसएस कार्यकर्ता ध्रुतिमान जोशी ने उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में राहुल गांधी और येचुरी गुरुवार को व्यक्तिगत रूप से मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में पेश हुए। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। (पेज-3)

कृष्णानंद मामले में हाई कोर्ट जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार

लखनऊ: भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में विधायक मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपितों को सीबीआइ की विशेष अदालत से बरी किए जाने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सरकार फैसले का परीक्षण कराएगी और हाई कोर्ट में अपील करेगी। विशेष अदालत से आरोपितों को बरी किए जाने पर जांच एजेंसी से लेकर पैरोकारों की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। गाजीपुर में कृष्णानंद राय और उनके सरकारी अंगरक्षक समेत आधा दर्जन समर्थकों की 29 नवंबर 2005 को हत्या कर दी गई थी। इस मामले में विधायक मुख्तार अंसारी, सांसद अफजाल अंसारी, जेल में मारे गए माफिया मुन्ना बजरंगी समेत 17-18 लोग आरोपित थे। (पेज-5)

प्रोत्साहन के लिए

जिले के 10 सबसे बड़े करदाताओं को दी जा सकती है विशेष प्रकार की सुविधाएं, दशक के सबसे बड़े करदाता के नाम पर रखे जा सकते हैं सड़कों-स्कूलों के नाम

टैक्स भुगतान बढ़ाने के लिए अनोखे सुझाव

नई दिल्ली, प्रेट्र : आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में कर अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ अनोखे सुझाव दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि हर जिले के सबसे बड़े 10 करदाताओं को खास सुविधा देकर उन्हें अलग पहचान दिया जा सकता है। इन सुविधाओं में इमिग्रेशन काउंटर पर राजनयिक जैसी सुविधाएं, हवाई अड्डों पर एक्सप्रेस बोर्डिंग और सड़कों, भवनों तथा स्कूलों का नामकरण उनके नाम पर करना शामिल है।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि चूंकि लोग प्रायः अपने सामाजिक रुतबे को दिखाने के लिए खास उपभोग में शामिल होते हैं। इसलिए जिले के 10 सबसे बड़े करदाताओं के नाम सार्वजनिक किए जा सकते हैं और उन्हें समुचित पहचान दिलाई जा सकती है। इसके तहत जो सुविधाएं ऐसे करदाताओं को दी जा सकती हैं, उनमें अहवाईअड्डों पर तेज बोर्डिंग की सुविधा, सड़क और टोल बूथ पर फास्ट-लेन की सुविधा, इमिग्रेशन काउंटर पर विशेष राजनयिक जैसे लेन, आदि शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा एक दशक के सबसे बड़े करदाता को विशेष पहचान दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भवनों, स्मारकों, सड़कों, रेलगाड़ियों, पहलों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और हवाईअड्डों के नाम उनके नाम पर रखे जा सकते हैं।

करदाताओं का बढ़ना चाहिए भरोसा। फाइल

सर्वेक्षण में कहा गया है कि इसके पीछे की सोच ऐसे क्लब की खास सदस्यता प्रदान करने का है, जिससे न सिर्फ सामाजिक रुतबे का पता चले, बल्कि सम्मान भी मिले। ऐसे कदमों से ऐसी सामाजिक मान्यता को भी बढ़ावा मिलेगा कि ईमानदारी से टैक्स का भुगतान करना सम्मान के योग्य बात है। संसद में पेश किए गए सर्वेक्षण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी सुझाव दिया कि टैक्स का भुगतान करने को सम्मानित काम की पहचान दिलाने के लिए निर्माण परियोजनाओं पर ऐसे साइन बोर्ड लगाने चाहिए, जिन पर लिखा हो कि 'टैक्स के पैसे से काम हो रहा है'। इससे करदाताओं में यह भावना बढ़ेगी कि जो टैक्स वह देते हैं, वह व्यर्थ काम में बर्बाद नहीं होता है।

इसी तरह से अन्य प्रकार के करदाताओं के द्वारा चुकाए गए टैक्स को भी सार्वजनिक किया जा सकता है। ऐसे करदाताओं में स्वरोजगार करने वाले हो सकते हैं। इनके द्वारा चुकाए गए करों को एसएमएस, बिलबोर्ड, आदि के जरिए पंचायतों और जिलों में प्रचारित किया जा सकता है। इससे नौकरी करने वालों के बीच कायम यह भ्रम दूर होगा कि उनसे अधिक कर लिया जा रहा है और दूसरे प्रकार के करदाताओं से कम कर लिया जा रहा है। सरकार चाहती है कि टैक्स का दायरा बढ़े और लोग खुद टैक्स देने के लिए प्रोत्साहित हों।

भ्रष्टाचार रोधी कानून के प्रावधान की वैधता की शीर्ष कोर्ट करेगा जांच

नई दिल्ली, प्रेट्र : आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक धन अर्जित करने से जुड़े मामले में अपने पति के साथ आरोपित पत्नी के प्रकरण की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार रोधी कानून के उस प्रावधान की वैधता की जांच करने का फैसला किया है जिसमें निजी लोगों को लोक सेवकों के साथ आरोपित बनाया जा रहा है।

शीर्ष अदालत भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13 की जांच करेगी, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि यह प्रावधान ऐसे आरोपितों के खिलाफ नहीं लगाया जा सकता जो लोकसेवक नहीं हैं। जब प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ को यह विश्वास हो गया कि शीर्ष अदालत ने इस विषय पर अब तक कोई फैसला नहीं सुनाया है तो पीठ ने इस विषय पर गौर करने पर सहमति जताई। इस मामले में पेश अधिवक्ता शिवाशीष मिश्रा ने पीठ से कहा, उन्हें लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार से निपटने वाली धारा 13 की व्याख्या पर एक भी फैसला नहीं मिला।

इंद्राणी बनेगी सरकारी गवाह चिदंबरम की बढ़ेगी मुसीबत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

इंद्राणी मुखर्जी फाइल फोटो

- पेश होकर औपचारिक सहमति देने पर ही मामले पर सुनवाई करेगी अदालत

आइएनएक्स मीडिया घोटाले में आरोपित इंद्राणी मुखर्जी की सरकारी गवाह बनाए जाने की अर्जी को अदालत ने मंजूर कर लिया है। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि 11 जुलाई को इंद्राणी मुखर्जी को अदालत में पेश होकर औपचारिक तौर पर अपनी सहमति देनी होगी, तभी इस मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी।

अपनी बेटी की हत्या के मामले में मुंबई की जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी आइएनएक्स मीडिया मामले में आरोपित है। वह आइएनएक्स मीडिया कंपनी की पूर्व निदेशिक भी है। इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम भी आरोपित हैं। इंद्राणी ने पिछले साल अदालत में अर्जी दायर सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई थी। आइएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआइ ने 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए मीडिया समूह को दी गई एफआइपीबी मंजूरी में अनियमितताएं हुईं। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल इस संबंध में मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

इस मामले में इंद्राणी मुखर्जी के सरकारी गवाह बनने के बाद पहले से ही कई मामलों में घिरे पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की मुसीबत और बढ़ सकती है, क्योंकि इंद्राणी कई ऐसे राजों का पर्दाफाश कर सकती है, जो अभी तक छिपे हैं।

16 जुलाई को महिपालपुर स्थित सीआइएसएफ मुख्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें सीआइएसएफ के सभी सेक्टरों सहित एनसीआर में रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी अपना दावा पेश कर सकेंगे। यह अदालत सुबह साढ़े नौ बजे शुरू होगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 5 जुलाई 2019

डीयू दाखिला ▶ दूसरे कटऑफ के आधार पर स्नातक में प्रवेश के लिए दूसरे राज्यों से भी पहुंचे विद्यार्थी

दाखिले के लिए सुबह से ही लग गईं कतारें

पसंदीदा कॉलेज और पाठ्यक्रमों के लिए दोबारा ले दाखिला ले रहे छात्र

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जारी दूसरे कटऑफ के आधार पर स्नातक में दाखिले के लिए गुरुवार को काफी संख्या में विद्यार्थी कॉलेजों में पहुंचे। दाखिले के समय (नौ बजे) से पहले ही कॉलेजों के बाहर लंबी कतारें लग गई थीं। बड़ी तादाद में दूसरे राज्यों से भी विद्यार्थी आए। राजस्थान के कोटा से आए सुनील सिंह ने बताया कि वह 27 जून को ही दिल्ली आ गए थे। उन्हें बीकॉम ऑनर्स में दाखिला लेना था। दूसरे कटऑफ में नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेजों में उनका नंबर आ गया है और अब मनपसंद कॉलेज और पाठ्यक्रम में दाखिला लेंगे। पहले को लेकर समस्या का सामना करना पड़ रहा था। समिति के सदस्यों ने बताया कि उनके पास 15 दिन का समय है। इस दौरान वे अपने प्रमाणपत्र ठीक करा सकते हैं। उन छात्रों की संख्या भी काफी ज्यादा थी, जिन्होंने पहले कटऑफ के आधार पर दाखिला ले लिया था, लेकिन दूसरे कटऑफ में उनके मनपसंद पाठ्यक्रम और कॉलेजों में नंबर आ गया है।

श्रीराम कालेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला फार्म भरते विद्यार्थी। ध्रुव कुमार

कुछ कॉलेज ही दे रहे हैं छात्राओं को एक फीसद अंक की छूट : एसोसिएट प्रोफेसर विजय वर्मा ने बताया कि शिकायत निवारण समिति के पास ऐसी भी छात्राएं पहुंचीं, जिन्होंने पहले कटऑफ में एक फीसद छूट पाकर कॉलेज में दाखिला ले लिया था और अब दूसरे कटऑफ में अन्य कॉलेजों में उनका नंबर आ रहा है, लेकिन उन्हें एक फीसद की छूट नहीं दी जा रही है। उन्हें बताया गया कि छात्राओं को एक फीसद अंक की छूट देने का नियम है, लेकिन इस पर फैसला लेने के लिए कॉलेज स्वतंत्र हैं।

भर चुकी हैं 26 हजार से अधिक सीटें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कॉलेजों में दूसरे कटऑफ के पहले दिन कॉलेजों में करीब तीन हजार दाखिले हुए। अब तक डीयू में 26,692 छात्रों के दाखिले हो चुके हैं। गुरुवार को दाखिला रद कराने वाले छात्रों की संख्या भी अधिक रही। उन्होंने पहले कटऑफ के आधार पर हुए दाखिले को रद कराकर मनपसंद कॉलेज में दाखिला लिया।

किरोड़ीमल कॉलेज की बात करें तो यहां गुरुवार को 96 छात्र दाखिला लेने पहुंचे और 20 छात्रों ने दाखिले रद कराए। इस कॉलेज में कुल 1,223 सीटों के लिए 1,133 दाखिले हो गए हैं।

राजधानी कॉलेज में 1050 सीटों में पहले कटऑफ के तहत 244 दाखिले हुए थे। दूसरे कटऑफ के पहले दिन 178 दाखिले हुए और 24 छात्रों ने दाखिला रद कराया। श्री अरबिंदो कॉलेज में 1060 सीटें हैं और यहां अब तक 557 छात्रों के दाखिले हो चुके हैं। साथ ही 12 विद्यार्थियों ने दाखिले रद कराए। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में गुरुवार को 200 से अधिक छात्रों ने दाखिले लिए। यहां अब तक करीब एक हजार सीटें भर चुकी हैं। प्राचार्यों ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में कई

62 हजार सीटें हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में

▶ दूसरे कटऑफ के पहले दिन दाखिला रद कराने भी पहुंचे कई विद्यार्थी

छात्र दाखिले रद कराएंगे, इससे अन्य छात्रों को दाखिले के अवसर मिलेंगे।

एनसीवेब में अतिथि शिक्षकों निकली भर्तियां : डीयू से संबद्ध नॉन कॉलेजिएट वूमेन एजुकेशन बोर्ड (एनसीवेब) की तरफ से अतिथि शिक्षकों की भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। एनसीवेब को अपने 26 केंद्र में अतिथि शिक्षकों की जरूरत है। इसके लिए शिक्षक एनसीवेब की वेबसाइट में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई है।

दाखिला रद कराते समय रखें इस बात का ध्यान : छात्रों को दूसरे कटऑफ के तहत मनपसंद पाठ्यक्रमों में दाखिले की उम्मीद है। इस बार हर कटऑफ में एक हजार रुपये शुल्क देकर सिर्फ एक बार ही दाखिला रद कराने का नियम बनाया गया है। छात्र दाखिला रद कराने से पहले यह जरूर सुनिश्चित कर लें, जिस कॉलेज में वे दाखिला लेना चाहते हैं वहां उनका नंबर आ रहा है कि नहीं।

सीलिंग के लिए दिल्ली सरकार, डीडीए व निगम जिम्मेदार : भूरेलाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मानिटरिंग कमेटी के चेयरमैन भूरेलाल ने सीलिंग के लिए दिल्ली सरकार, डीडीए और स्थानीय नगर निगमों को जिम्मेदार ठहराया है। हाल ही में दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कमेटी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि यह गैर कानूनी तरीके से सीलिंग कर रही है। इन आरोपों को निराधार बताते हुए भूरेलाल ने कहा कि जो कुछ हो रहा है, वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हो रहा है। कमेटी किसी सरकार की बनाई हुई नहीं है। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण को रोकने का काम स्थानीय निकायों का का है। हमें अवैध निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है तो हम जांच करने के बाद कार्रवाई करते हैं।

50 बसों पर किया जाएगा हाइड्रो सीएनजी का परीक्षण : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर परीक्षण के स्थापित किए जा रहे हाइड्रो सीएनजी पंप से पायलट प्रोजक्ट के तहत सार्वजनिक परिवहन की 50 बसों पर परीक्षण किया जाएगा। छह माह के परीक्षण के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। यह ईंधन इंडियन आयल कारपोरेशन के फरीदाबाद स्थित रिसर्च एंड डेवलमेंट सेंटर द्वारा विकसित किया गया है, जिसका पेंटेंट भी कराया गया है। इसके लिए व्यापक तैयारी के साथ राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंजूरियां भी ली गई हैं। आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने परीक्षण में पाया कि हाइड्रो सीएनजी में प्रचलित सीएनजी की तुलना में 70 फीसद कम कार्बन

राजघाट बस डिपो में एचसीएनजी स्टेशन की आधारशिला कार्यक्रम में उपस्थित ईपीसीए के अध्यक्ष डॉ. भूरे लाल। जागरण

मोनोआक्साइड और 25 फीसद कम हाइड्रो कार्बन का उत्सर्जन होता है। वहीं, सीएनजी के मुकाबले लागत में 30 फीसद किफायती भी होगी। अगर यह परीक्षण सफल रहा तो दिल्ली के वाहनों के लिए हाइड्रो सीएनजी का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। वैसे, इसके लिए वाहनों में कोई विशेष बदलाव नहीं करने होंगे।

एक हजार इलेक्ट्रिक बसें उतारेगी डीटीसी : डीटीसी के चेयरमैन मनोज कुमार ने बताया कि दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही 1000 इलेक्ट्रिक बसें उतारी जाएंगी। इनमें से 900 बसें दिल्ली में तथा 100 बसें अंतरराज्यीय मार्ग पर चलेंगी। उन्होंने बताया कि इसके बारे में गुरुवार को ही केंद्र सरकार को विस्तृत जानकारी दी गई है।

न्यूज गैलरी

केजरीवाल के खिलाफ समन जारी करने पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली : आपराधिक मानहानि के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ समन जारी करने पर राउज एवेन्यू अदालत ने फैसला 22 जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया है। भाजपा नेता करन सिंह ने अरविंद केजरीवाल, विधायक अमानत उल्लाह खान, सुरेंद्र सिंह और दिलीप पांडे के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था। करन सिंह ने कहा कि आप नेताओं ने एनडीएमसी के अधिकारी एमएम खान की हत्या में उन पर गलत आरोप लगाया था। आरोप है कि आप नेताओं ने मीडिया में बयान दिया था कि खान की हत्या में करन सिंह ने साजिश रची है। इस आरोप से उनकी छवि खराब हुई है। (जासं)

वन क्षेत्र में अवैध निर्माण पर एनजीटी ने जताई नाराजगी

नई दिल्ली : दक्षिण दिल्ली के वन क्षेत्र में अवैध निर्माण पर नाराजगी जताते हुए एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। जौनापुर और डेरा मंडी वन क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर एनजीटी में याचिका दायर की गई थी। इस पर एनजीटी ने अवैध निर्माण और कब्जे हटाने का आदेश दिया था। इसका पालना नहीं किया गया। वहीं, महरौली के एसडीएम की तरफ से एनजीटी में रिपोर्ट दाखिल कर बताया गया कि तीन हजार से ज्यादा अवैध निर्माण व कब्जे हैं और कार्रवाई करने में दिक्कत आ रही है। एनजीटी ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि याचिका पर पैरवी करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कोई अधिवक्ता हाजिर नहीं हुए। मामले की सुनवाई चार अगस्त के लिए तय की गई है। (जासं)

यलो लाइन पर डेढ़ घंटे मेट्रो का परिचालन रहा प्रभावित

नई दिल्ली : सिग्नल में खराबी के कारण गुरुवार को यलो लाइन पर दोपहर में डेढ़ घंटे तक मेट्रो का परिचालन प्रभावित रहा, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम का कहना है कि सिग्नल ठीक होने पर दोपहर 3:25 बजे परिचालन सामान्य हो गया। डीएमआरसी के अनुसार दोपहर 1:55 बजे हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास अचानक सिग्नल में खराबी आ गई। मेट्रो का संपर्क केंद्रीय कंट्रोल रूम से कट गया, जिससे मेट्रो की रफ्तार धीमी पड़ गई और मैनुअल तरीके से परिचालन करना पड़ा। इस वजह से यलो लाइन के पूरे कॉरिडोर पर मेट्रो की रफ्तार धीमी हो गई। मेट्रो स्टेशनों पर देर तक रुक-रुककर कर चल रही थीं। (जासं)

मॉड्यूलर ओटी और आइसीयू बनाने में करोड़ों का घोटाला

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली

▶ तीन बार टेंडर निकाले और तीनों बार किसी न किसी बहाने किए रद

▶ दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से जांच करने की मांग

शाहदरा स्थित दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर, आइसीयू व बोनमैरो ट्रांसप्लांट सूट बनाने में करोड़ों रुपये का घोटाला किए जाने का मामला सामने आया है। ये बनाने के लिए पहले तीन बार टेंडर निकाले गए, लेकिन तीनों ही बार किसी न किसी बहाने से टेंडर रद कर दिए गए। चौथी बार टेंडर निकालकर एक कंपनी को इन्हें बनाने का ठेका दे दिया गया। पहली बार टेंडर निकाले जाने के दौरान इन्हें बनाने की लागत दो करोड़ रुपये थी। चौथी बार टेंडर फाइनल होने तक यह लागत छह गुना बढ़कर 12 करोड़ तक पहुंच गई। लिहाजा घोटाले की आशंका के मद्देनजर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने पहले खुद ही जांच की। बाद में जांच रिपोर्ट दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) को सौंप केस दर्ज कर जांच करने की मांग की।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के उपसचिव, विजिलेंस अमित कुमार पामसी की शिकायत पर एसीबी ने केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में एसीबी ने दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के निदेशक को नोटिस जारी कर टेंडर व लागत संबंधी फाइलें मंगा ली हैं।

एसीबी सूत्रों के मुताबिक, फाइलों की जांच तेज कर दी गई है। घोटाले में जिन डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों व अन्य की संलिप्तता पाई जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायत में कहा गया है कि जब पहली बार तीनों चीजों को बनाने के लिए टेंडर निकाला गया, तब लागत महज दो करोड़ रुपये थी, लेकिन टेंडर किसी को क्यों नहीं दिया गया। दूसरी व तीसरी बार भी टेंडर निकाले गए, लेकिन किसी को टेंडर नहीं दिया गया। किसी न किसी बहाने तीन बार टेंडर रद कर दिए गए। शिकायत में कहा गया है कि टेंडर देने में जानबूझ कर विलंब किया गया ताकि लागत की राशि बढ़ जाए। चौथी बार टेंडर निकालने पर चार कंपनियों ने आवेदन किया। इनमें दो को सूचीबद्ध किया गया। उनमें गुरुग्राम की एक कंपनी को 12 करोड़ रुपये में टेंडर दे दिया गया। टेंडर प्रक्रिया में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की गाइड लाइन को ताक पर रखा गया। इसलिए जो प्रोजेक्ट दो करोड़ का था, वह 12 करोड़ तक पहुंच गया। उक्त बजट से सरकार को भारी नुकसान पहुंचा है।

मंदिर में तोड़फोड़ मामला

सीसीटीवी फुटेज से 20 आरोपितों की हुई पहचान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : हौज काजी के लालकुआं स्थित दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ करने के मामले में मध्य जिला पुलिस ने गुरुवार को दो अन्य आरोपितों को दबोच लिया। नौ आरोपितों को पुलिस पहले दबोच चुकी है। अब तक कुल 11 आरोपित पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। इनमें सात बालिग व चार नाबालिग हैं। सभी एक ही समुदाय विशेष के हैं। ये लोग हौज काजी व आसपास के रहने वाले हैं। पुलिस अधिकारी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज देखकर 20 आरोपितों की पहचान कर ली गई है। अन्य की पहचान करने का सिलसिला जारी है।

हौज काजी इलाके से नहीं गुजरने दी जगन्नाथ यात्रा : मध्य जिला पुलिस अधिकारी का कहना है कि मंदिर में तोड़फोड़ कर धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाले किसी भी आरोपित को बख्शा नहीं जाएगा। अब इलाके में किसी भी तरह का तनाव नहीं है फिर भी एहतियात के तौर पर अभी पुलिसकर्मियों की तैनाती रखी गई है। पुलिस अधिकारी लगातार इलाके पर नजर बनाए हुए हैं।

उधर, गुरुवार को सुरक्षा कारणों से जगन्नाथ यात्रा को हौज काजी इलाके से नहीं गुजरने दिया गया। यात्रा में करीब 200 लोग शामिल थे। इनकी सुरक्षा में करीब 600 पुलिसकर्मी लगाए थे। इस बीच हौज काजी के स्टील टूल्स व हार्डवेयर के व्यापारी दुर्गा मंदिर की मरम्मत के लिए आगे आए हैं।

एक तीर्थ यात्रा जरूर करवाऊंगा : सीएम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में 12 जुलाई को स्वर्ण मंदिर एवं वाघा बॉर्डर और 20 जुलाई को वैष्णो देवी जाने वाले बुजुर्गों के साथ दिल्ली सचिवालय सभागार में संवाद किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के बुजुर्गों को मैं कहना चाहता हूं कि आपका यह बेटा कोशिश करेगा कि आपकी जिंदगी में आपको एक तीर्थ यात्रा जरूर करवाऊं। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने पिछले साढ़े चार साल के अभी तक के कार्यकाल में विकास से जुड़े बहुत से कार्य किए, लेकिन आज बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजने से दिल को सुकून मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मां वैष्णो देवी यात्रा पर वह खुद और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी सपरिवार 20 जुलाई को रवाना होने वाली ट्रेन से यात्रा करेंगे।

उन्होंने कहा कि बुजुर्गों का कर्ज कभी भी नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन यदि उनको तीर्थ यात्रा करवा दी जाए तो कुछ पुण्य जरूर मिल जाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को भी पुण्य मिलेगा क्योंकि उनके दिए हुए टैक्स से आप तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उसी में थोड़ा पुण्य हमको भी मिल जाएगा। इस यात्रा पर भी विरोधियों ने राजनीति करने की कोशिश की।

केजरीवाल ने अपने विरोधियों को जवाब दिया कि तीर्थ यात्रा में बुजुर्गों पर पैसे लुटाने का कार्य मैं लगातार करता रहूंगा। कार्यक्रम में

दिल्ली सचिवालय में आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुर्जुगों के साथ मुलाकात की। साथ में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। ध्रुव कुमार

मौजूद वरिष्ठ नागरिकों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा भी अगले साल से शुरू करने पर विचार किया जाएगा।

सिसोदिया ने कहा कि पहले इस योजना में स्लीपर क्लास में ले जाने का प्रस्ताव था। बाद में मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों को एसी क्लास में ले जाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में सभी धर्मों का बराबर का सम्मान है। इस योजना में सभी धर्मों के तीर्थ स्थलों को शामिल किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कमेटी के चेयरमैन कमल बंसल ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान एक बुजुर्ग जेपी रावल ने मुख्यमंत्री को श्रवण कुमार की उपाधि दी। इस दौरान उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत, सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद थे।

एयरपोर्ट पर नहीं होगा डिस्पोजेबल प्लास्टिक का प्रयोग

संतोष शर्मा, नई दिल्ली

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इस वर्ष के अंत तक डिस्पोजेबल प्लास्टिक का प्रयोग बंद कर दिया जाएगा। पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वर्तमान में एयरपोर्ट पर स्टोर और खाने-पीने की चीजों की दुकानों में प्लास्टिक की जगह पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ चीजों का प्रयोग किया जा रहा है। इनमें कागज, बांस, पत्तों और मिट्टी से बने सामान शामिल हैं। एयरपोर्ट पर प्लास्टिक को हतोत्साहित करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसका खासा असर देखने को मिल रहा है।

एयरपोर्ट संचालक कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) के मुताबिक दिसंबर 2019 तक एयरपोर्ट को डिस्पोजेबल (एकल उपयोग) प्लास्टिक से मुक्त कर दिया जाएगा। वर्ष 2022 तक यहां किसी भी तरह की प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एयरपोर्ट पर प्लास्टिक के सामान का प्रयोग कम से कम हो, इस योजना पर काम चल रहा है। भोजन और पेय पदार्थों की पैकिंग सहित खुदरा खरीद-बिक्री के लिए भी पर्यावरण अनुकूल बैग का इस्तेमाल किया जा रहा है।

आइजीआइ एयरपोर्ट स्थित खाने-पीने की दुकान पर प्लास्टिक प्रतिबंध होने के बाद पर्यावरण अनुकूल सामग्री से बने चम्मच और अन्य सामान। जागरण

आइजीआइ के तीनों टर्मिनल, बाहर और एयर साइड एरिया में दर्जनों स्टोर और खाने-पीने की दुकानें हैं। प्लास्टिक से बनी प्लेट में नाश्ता परोसने के साथ ही पैकेजिंग में भी प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता था। पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर इसके कुप्रभाव को देखते हुए प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट कार्यक्रम शुरू किया गया। डायल प्रवक्ता ने बताया कि एयरपोर्ट पर ऐसे तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण स्वच्छ रहे। इसके लिए वहां दो तरह के डस्टबिन रखे गए हैं, ताकि बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकिल योग्य कचरे को अलग किया जा सके। प्लास्टिक से बनी चीजों पर प्रतिबंध से पर्यावरण संरक्षण का प्रयास और मजबूत होगा।

डिस्पोजेबल प्लास्टिक : आमतौर पर इस प्लास्टिक का प्रयोग पैकेजिंग के लिए किया जाता है। इसका केवल एक बार ही उपयोग किया जाता है। इसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। इसका प्रयोग प्रमुख रूप से किराने की थैली, खाने के सामान की पैकेजिंग, बोतलें, कंटेनर, कप और कटलरी के लिए किया जाता है।

नहीं आई कैट्स एंबुलेंस घर में हुए प्रसव

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : एंबुलेंस नहीं मिलने से एक गर्भवती महिला अस्पताल नहीं पहुंच पाई। एंबुलेंस का इंतजार करते हुए आखिर घर पर ही प्रसव हो गया। पिछले चार दिन में ऐसे कितने ही वाकये घटित हो चुके हैं।

इसी तरह रोहिणी सेक्टर-पांच में रहने वाले संजीव ने बताया कि कैट्स एंबुलेंस को कॉल कर बताया कि प्रसव के लिए गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना है। जवाब मिला कि सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, इसलिए निजी एंबुलेंस से ले जाओ। महावीर एंक्लेव के रहने वाले विनोद ने बताया कि प्रसव पीड़ा के कारण पत्नी को अस्पताल ले जाना था। एंबुलेंस नहीं आई और आखिर में पत्नी को अस्पताल नहीं ले जा सके। इसी तरह एक अन्य गर्भवती महिला को एंबुलेंस की सुविधा नहीं मिलने पर परिजन ऑटो से लेकर सफदरजंग अस्पताल पहुंचे। एक तरफ सरकार सुरक्षित मातृत्व के लिए तमाम योजनाएं और सुविधाएं देने के दावे और प्रचार कर रही है, वहीं हकीकत यह है कि कैट्स के इमरजेंसी नंबर (102) पर कॉल करने पर कर्मचारियों की हड़ताल होने की दलील देकर एंबुलेंस भेजने से इन्कार कर दिया गया।

आप विधायक सोमदत्त को छह माह की कैद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान एक शख्स से मारपीट करने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमदत्त को छह माह कैद और दो लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। इसमें एक लाख रुपये पीड़ित को देने होंगे। फैसले को चुनौती देने की बात पर अदालत ने 10 हजार रुपये के व्यक्तिगत बांड पर 5 अगस्त 2019 तक के लिए जमानत दे दी। गत 29 जून को विधायक को दोषी करार दिया गया था।

विधायक सोमदत्त

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दिल्ली के सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र से विधायक सोमदत्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (किसी को गंभीर चोट पहुंचाने), धारा 147 (दंगा) और धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत दोषी ठहराया था। अभियोग के मुताबिक, 10 जनवरी 2015 को रात करीब आठ बजे सोमदत्त अपने 50 समर्थकों के साथ भवन संख्या 13 में पहुंचे थे। वहां शिकायतकर्ता संजीव राणा मौजूद थे। सोमदत्त और उनके समर्थकों ने संजीव राणा के साथ मारपीट की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई थीं।

सोमदत्त के खिलाफ पंजाबी बाग थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अभियोजक पक्ष का आरोप था कि विधायक ने बेसबॉल बल्ले से शिकायतकर्ता संजीव राणा के पैर में मारा था, जबकि उनके समर्थक संजीव को घसीटकर सड़क पर लाए और पिटाई की थी। सोमदत्त के वकील ने दलील दी थी कि सोमदत्त व उनके समर्थक शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने ही उनके साथ झगड़ा शुरू किया था। इस पर एक क्रॉस एफआइआर भी संजीव राणा के खिलाफ दर्ज हुई थी।

महिला सशक्तीकरण

दिल्ली से पहली बार आठ महिलाएं बिना किसी पुरुष सदस्य (मेहरम) के हज यात्रा पर जाएंगी

हज के लिए अकेले आसमां छुएंगी महिलाएं

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली

ऐसा पहली बार होगा, जब हज यात्रा पर जाने वाले दिल्ली के दल में आठ ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं, जो परिवार के किसी पुरुष सदस्य (मेहरम) के बिना हज पर जा रही हैं। इन महिलाओं की यह यात्रा मोदी सरकार की महिला सशक्तीकरण की मुहिम के साकार होने के संकेत दे रही है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की रजामंदी से बिना मेहरम हज करने वाली महिलाओं के लिए रास्ता खोला था। 2018 में पहली बार बिना मेहरम के महिलाओं का एक जत्था हज पर गया था। लेकिन उस जत्थे में दिल्ली से कोई महिला नहीं थी, जबकि इस बार आठ महिलाओं को मंजूरी दी गई है। यह दल 14 जुलाई को दिल्ली से मदीना की उड़ान भरेगा। दिल्ली हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी अशफाक अहमद अर्फी ने कहा कि यह अच्छा कदम है। आने वाले वर्षों में बिना मेहरम के हज पर जाने वाली महिलाओं की तादाद बढ़ेगी। हालांकि इसमें 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को ही अनुमति है और साथ में कुल चार महिलाएं होना जरूरी है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष हाफिज साबरीन ने कहा कि इससे वे महिलाएं भी हज यात्रा पर जा सकती हैं, जिनके खून के रिश्तेदार (भाई, पति, पिता व बेटा) नहीं हैं।

तुर्कमान गेट स्थित हज हाउस में मॉडल से काबा के बारे में हज यात्रियों को दी जा रही जानकारी। जागरण

दिल्ली से 23 हजार हज यात्री भरेंगे उड़ान : बुधवार को हज यात्रियों ने पहली उड़ान भरी। यहां से 17 जुलाई तक मदीना के लिए 75 उड़ानें होंगी, जिनसे तकरीबन 23 हजार यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। इनमें दिल्ली के करीब ढाई हजार लोग शामिल होंगे। पिछले वर्ष दिल्ली के रास्ते 19 हजार यात्री हज पर गए थे। इस वर्ष कोटा बढ़ाया है। खास बात यह है कि इस बार हज यात्री अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के टर्मिनल-तीन से उड़ान भर रहे हैं। वहां इनके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा हज हाउस में दस्तावेजों की जांच, टीकाकरण व मार्गदर्शन की जानकारियां दी जा रही हैं।

'ज्ञानवृत्ति' फेलोशिप के लिए आवेदन की तिथि 31 तक बढ़ी

जेएनएन, नई दिल्ली

दैनिक जागरण की 'हिंदी हैं हम' पहल के तहत आने वाली 'ज्ञानवृत्ति' फेलोशिप के दूसरे संस्करण लिए आवेदन करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।

मौलिक शोध और मूल लेखन में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए इस कार्यक्रम के तहत दैनिक जागरण संस्थान की तरफ से शोधार्थियों को 75,000 रुपये प्रति माह का वित्तीय अनुदान दिया जाता है।

संस्थान ने कहा है कि 'ज्ञानवृत्ति किसी शोधार्थी को कम से कम छह महीने और अधिकतम नौ महीने के लिए दी जाती है।' फेलोशिप के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु एक जनवरी 2019 तक 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए।

इस फेलोशिप का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को संबंधित विषयों पर हजार शब्दों में सार भेजना होगा जिसके आधार पर जूरी विषय और शोधार्थी का चयन करेगी।

जूरी के सदस्यों में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एसएन चौधरी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के राजनीतिशास्त्र के प्रोफेसर डॉ. दरवेश गोपाल और दैनिक जागरण की संपादकीय टीम शामिल है।

दैनिक जागरण
ज्ञानवृत्ति
• अध्ययन • चिंतन • शोध

सिसोदिया और जैन के खिलाफ भाजपा ने दी लोकायुक्त को शिकायत

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कमरे निर्माण पर कथित दो हजार करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर प्रदेश भाजपा ने अब लोकायुक्त से शिकायत की है। गुरुवार को भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने लोकायुक्त को शिकायत देकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और लोक निर्माण विभाग मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच की मांग की है।

दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता हरीश खुराना ने शिकायत देने के बाद कहा कि सरकार में बैठे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने स्कूलों में नए कमरों के निर्माण में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ठेकेदारों से मोटी रकम वसूली है। स्कूलों के कमरे बनवाने के ठेके साठगांठ करके आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं को दिए गए। खुराना ने कहा कि जब तक दोनों को सजा नहीं हो जाती, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। दिल्ली सरकार द्वारा 8800 रुपये प्रति वर्ग फुट की राशि पर कमरों के निर्माण का ठेका दिया गया। यह बाजार भाव से पांच गुना अधिक है।

20 जुलाई को मतदान होगा ओडिशा की पाटकुरा विधानसभा सीट के लिए। इस वर्ष हुए विधानसभा चुनाव के दौरान यहां से बीजू जनता दल के उम्मीदवार वेद प्रकाश अग्रवाल के देहांत के बाद चुनाव आयोग ने इस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया था।

मानहानि मामले में राहुल ने खुद को बताया निर्दोष

कोर्ट में सफाई ▶ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के लिए आरएसएस व उसकी विचारधारा को बताया था दोषी

माकपा नेता सीताराम येचुरी ने भी खुद को बेगुनाह बताया, दोनों नेता करेंगे मुकदमें का सामना

राज्य ब्यूरो, मुंबई

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके राहुल गांधी और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने गुरुवार को अदालत में स्वयं को निर्दोष बताया। इससे साफ हो गया है कि वे इस मुकदमे का सामना करेंगे। राहुल और येचुरी ने बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के लिए आरएसएस और उसकी विचारधारा को दोषी ठहराया था।

दोनों नेताओं के बयान के बाद आरएसएस कार्यकर्ता ध्रुतिमान जोशी ने उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में राहुल गांधी और येचुरी गुरुवार को व्यक्तिगत रूप से मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में पेश हुए। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। राहुल की जमानत मुंबई से कांग्रेस के पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ ने ली। इससे पहले कोर्ट में पेशी के लिए राहुल गुरुवार सुबह करीब 10.15 बजे मुंबई पहुंचे। विमानतल से कोर्ट तक उनके स्वागत में कांग्रेस के झंडे लगाए गए थे। शिवड़ी कोर्ट के बाहर भी कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ थी। मालूम हो कि राहुल गांधी पर मानहानि का एक और मुकदमा ठाणे के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। यह मुकदमा भी आरएसएस को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराने पर एक संघ के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर किया गया था।

आक्रमण हो रहा है, मजा आ रहा है : राहुल

राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा, 'मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा हूं। किसानों, मजदूरों और गरीबों के साथ खड़ा हूं। आक्रमण हो रहा है, मजा रहा है।' अदालत परिसर से बाहर निकलते वक्त पत्रकारों ने जब राहुल से पूछा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उन पर पार्टी अध्यक्ष पद नहीं छोड़ने का दबाव डाला जा रहा है, क्या वह मानेंगे? इस पर उन्होंने साफ कहा कि उन्हें जो कहना था, वह बुधवार को अपने नोट में कह चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी और जोरों से चलेगी। उन्होंने कहा, जिस तरह पिछले पांच साल में लड़ा हूं, उससे 10 गुना ज्यादा जोश से लड़ूंगा।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को मानहानि मामले में भारी सुरक्षा के बीच मुंबई के मझगांव-शिवड़ी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता धृतिमान जोशी ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में संघ का नाम जोड़े जाने पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। प्रेट्र

कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश रावत ने दिया इस्तीफा

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- फेसबुक पोस्ट के जरिए पूर्व सीएम ने दी अपने इस्तीफे की जानकारी
- केवल राहुल गांधी में ही है कांग्रेस को प्रेरणा देने की क्षमता

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, असम के प्रभारी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पद से इस्तीफा दे दिया है। फेसबुक पोस्ट के जरिये उन्होंने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार एवं संगठनात्मक कमजोरी के लिए हम पदाधिकारीगण उत्तरदायी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी को प्रेरणा देने वाले नेता की आवश्यकता है। यह क्षमता केवल राहुल गांधी में है।

फेसबुक पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि असम में पार्टी के अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न कर पाने के लिए बतौर प्रभारी वह उत्तरदायी हैं। अपनी कमी को स्वीकार कारते हुए अपने महामंत्री के पद से पहले ही त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने कहा कि काम करने के लिए मुझे किसी पद की आवश्यक नहीं हैं। लेकिन प्रेरणा देने वाले नेता जरूरी हैं और प्रेरणा देने की क्षमता केवल राहुल गांधी में है। राहुल गांधी के हाथ में बागडोर रहे तो यह संभव है कि हम 2022 में राज्यों में हो रहे चुनाव में वर्तमान स्थिति को बदल सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल के हाथों पार्टी की बागडोर रहने पर 2024 में भाजपा और नरेंद्र मोदी को परास्त कर सकते हैं। ज्ञातव्य है कि हरीश रावत ने नैनीताल सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गए।

हरीश रावत फाइल फोटो

संसद प्रश्नोत्तर

16 भ्रष्ट आइएएस अफसरों पर अभियोजन की दी गई अनुमति

- सरकार ने राज्यसभा में कहा, 36 सीबीआइ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज की गई

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 16 आइएएस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। कार्मिक मंत्रालय के राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में दिए गए लिखित जवाब में बताया कि 36 सीबीआइ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें भी दर्ज की गई हैं।

राज्यमंत्री ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्तता के कारण दो आइएएस अधिकारियों को ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-2019 के बीच दो आइपीएस व 15 आइएफएस अधिकारियों के खिलाफ भी अभियोजन की अनुमति दी गई।

एक अन्य सवाल के जवाब में जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को बताया, 'सीबीआइ के पास अपने अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों एवं आंतरिक सतर्कता मामलों के निपटारे के लिए मजबूत तंत्र है। 2016 से 31 मई 2019 के बीच 36 अधिकारियों एवं अन्य के खिलाफ 10 प्राथमिक जांच एवं 20 नियमित मामले दर्ज किए गए हैं।'

उन्होंने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2016 से दो जुलाई 2019 के बीच छह अधिकारियों (दो शिकायतों में सीबीआइ अधिकारी के नामों का उल्लेख नहीं) की संलिप्तता वाली सात शिकायतों का संज्ञान लिया गया। सीवीसी ने इन शिकायतों को सीबीआइ के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीसी) के पास जांच एवं रिपोर्ट के लिए भेज दिया है।

13 भाषाओं में भी होगी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भर्ती परीक्षा

नई दिल्ली, प्रेट्र : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में स्केल-1 अधिकारी और कार्यालय सहायक की सीधी भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाएं अब अंग्रेजी एवं हिंदी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं (जिन 13 भाषाओं में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उनमें असमी, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू व उर्दू) में भी आयोजित की जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में स्वतः दिए बयान में कहा, इससे क्षेत्रीय भाषाओं में दक्ष लोगों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नौकरी पाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, 'स्थानीय युवकों के लिए समान अवसर मुहैया कराने और रोजगार का दायरा बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

मुलाकात : गुरुवार को बजट सत्र में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता मोती लाल वोरा से संसद परिसर में बातचीत करती केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री व अमेठी से भाजपा सांसद स्मृति ईरानी। प्रेट्र

गांधी परिवार के बिना होगी इस बार कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक!

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे को मंजूर करने और नया अध्यक्ष चुनने के लिए इस बार कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बिना गांधी परिवार के होने की संभावना है।

कार्यसमिति बैठक की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन इसके अगले हफ्ते होने की संभावना है। इस बीच, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी मेडिकल चेकअप के लिए अगले कुछ दिनों में विदेश जा रही हैं। उनके पुत्र राहुल गांधी के भी उनके साथ जाने की पूरी संभावना है। राहुल की बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहले से विदेश में हैं और उनके जल्द लौटने की कोई संभावना नहीं है। लिहाजा कार्यसमिति की बैठक में गांधी परिवार के किसी भी सदस्य के मौजूद रहने की संभावना नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि पार्टी के अगले अध्यक्ष को लेकर कोई भी फैसला उनकी सहमति के बिना नहीं लिया जाएगा। ध्यान रहे राहुल गांधी ने बुधवार को अपने इस्तीफे को सार्वजनिक करते हुए कहा था कि वह चाहते हैं कि पार्टी की कमान अब नए हाथों में जाए। इस मामले में किसी भी दबाव से मुक्ति के लिए वह नए प्रमुख की चयन प्रक्रिया से दूर रहेंगे।

'कठपुतली' नहीं, बल्कि 'सेनापति' सरीखा अध्यक्ष तलाश रही कांग्रेस

संजय मिश्र, नई दिल्ली

- बदले सामाजिक-राजनीतिक हालात के मद्देनजर संगठन से जुड़े मुखर हिंदी भाषी चेहरे को नेतृत्व देने पर गंभीर मंत्रणा

राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में नए पार्टी अध्यक्ष की तलाश पर वरिष्ठ नेताओं के बीच अनौपचारिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। चुनावी हार के बाद राहुल के इस्तीफे को पार्टी के इतिहास का सबसे गंभीर संकट मान रहे कांग्रेस दिग्गजों का मानना है कि इस हालात में कार्यकर्ताओं में भरोसा पैदा करने के साथ ही जनता से तार जोड़ने वाले चेहरे का नेतृत्व अपरिहार्य हो गया है। पार्टी में इस पर दो राय नहीं है कि मौजूदा हालात में पार्टी को 'वार टाइम जनरल' (युद्ध में मोर्चा संभालने वाला सेनापति) की जरूरत है और कठपुतली अध्यक्ष बनाए जाने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। पार्टी में इस बात पर भी दो राय नहीं कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक पराक्रम को चुनौती देने के लिए मुखर ही नहीं, हिंदी भाषी चेहरा होना भी बेहद जरूरी है। तभी उत्तर से लेकर पश्चिम और मध्य से लेकर पूर्वी भारत में भाजपा के एकतरफा संवाद को चुनौती दी जा सकेगी।

सूत्रों ने बताया कि नए अध्यक्ष के लिए जिन चेहरों के नाम चर्चा में हैं, उनके अलावा कुछ दूसरे नामों को संभावित दावेदारों की सूची में शामिल कर चिंतन-मनन किया जाएगा। इसी वजह से कार्यसमिति बैठक की तारीख तय नहीं हुई है। मगर यह लगभग तय है कि अगले हफ्ते कार्यसमिति की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें राहुल का इस्तीफा मंजूर कर नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा।

संगठन से जुड़े चेहरे को नया अध्यक्ष बनाने पर हो रहे मंथन पर वरिष्ठ सूत्र ने कहा कि ऐसा व्यक्ति संगठन के साथ-साथ कार्यकर्ताओं और नेताओं के मिजाज को समझते हुए बेहतर समन्वय कर सकेगा। गांधी परिवार से बाहर के अध्यक्ष बने व्यक्ति के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं का भरोसा अर्जित करना कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में संगठन का अनुभव उसके लिए कारगर होगा। लोकसभा चुनाव में 17 राज्यों में खाता भी नहीं खुलने की स्थिति को अब कांग्रेस में अस्तित्व की बड़ी लड़ाई माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों ने कहा, इसीलिए किसी रीढ़विहीन व्यक्ति को अध्यक्ष बनाए जाने की न कोई गुंजाइश है और न हालात। बेशक कांग्रेस का नया अध्यक्ष गांधी परिवार का भरोसेमंद होगा मगर कठपुतली नहीं। दक्षिण भारत से ताल्लुक रखने वाले पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में नेतृत्व के सबसे बेहतर चेहरे को कमान देने की संभावना इसीलिए भी ज्यादा है कि उत्तराधिकारी तय करने में राहुल गांधी का नजरिया सबसे प्रभावी भूमिका निभाएगा। इस वक्त सोनिया गांधी के लिए भी अड़चन की गुंजाइश खोजना आसान नहीं होगा। नए अध्यक्ष के चयन में कांग्रेस देश के बदले सामाजिक-राजनीतिक समीकरण की अनदेखी भी नहीं करना चाहती। इसीलिए चाहे सुशील कुमार शिंदे और मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी पर विचार किया जा रहा हो, मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा और अशोक गहलोत जैसे नेताओं के नाम भी चर्चा की दौड़ से बाहर नहीं माने जा रहे।

बिजली की खपत नहीं बढ़ातीं कांच की इमारतें

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने स्पष्ट किया है कि इमारतों के आगे के हिस्से में कांच के प्रयोग से बिजली की खपत बढ़ने का कोई प्रमाण नहीं है। बल्कि सही तरीके से डिजाइन किया जाए, तो ऐसी इमारतें फायदेमंद साबित हो सकती हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी दी। वह इस प्रश्न पर जानकारी दे रहे थे कि क्या ऊर्जा संरक्षण से जुड़े लोगों ने इमारतों में कांच के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताई है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है।

मंत्री ने कहा, 'हमारा प्रयास यही है कि ऐसी इमारतें बनें जो पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ और बेहतर हों। ऐसा कोई भी प्रमाण सामने आया कि कांच के इस्तेमाल से ऊर्जा की खपत बढ़ती है, तो उस पर विचार होगा।' अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि वह अमेरिका में पांच साल ट्रंप टावर में रहे हैं। यह पूरी इमारत शीशे की बनी है। उन्होंने ऐसी जानकारी होने से इन्कार किया कि किसी ने कांच के प्रयोग पर नियंत्रण की दिशा में कदम उठाने का कोई सुझाव दिया है। मंत्री ने कहा, 'इमारत का अगला हिस्सा दक्षिण की ओर खुलता हो, तो कांच के इस्तेमाल से ऊर्जा की खपत बढ़ती है। उत्तर की ओर हो, तो खपत कम हो जाती है। पूरब और पश्चिम के मामले में खपत पर कोई असर नहीं पड़ता।'

राज्यसभा में उठा खरबूजे को इंजेक्शन लगाकर मीठा बनाने का मामला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राज्यसभा में खाद्य उत्पादों में मिलावट का मुद्दा जोरशोर से उठाया गया। भाजपा सदस्य विजयपाल सिंह तोमर ने शून्यकाल में सदन को खरबूजे को मीठा बनाने वाले इंजेक्शन की जानकारी दी। उन्होंने कहा, इस लाइलाज हो रही गैर वाजिक गतिविधि पर अंकुश की सख्त जरूरत है। तोमर ने कहा, खरबूजे के खेत में महिलाओं व बच्चों को उन्होंने ऐसा करते हुए पाया।

तोमर ने कहा, बच्चों के खाद्य उत्पादों से लेकर हर छोटी बड़ी चीजों पर मिलावटखोरों की नजर है। पहले यह समस्या आमतौर पर शहरों तक सीमित थी, लेकिन अब इसका प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो गया है। दूध में न जाने क्या कुछ मिला दिया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होता है। नकली मावा से बाजार पटा हुआ है। मसालों व दालों में मिलावट हो रही है। दवाइयां नकली आने लगी हैं। आटा में सेलखड़ी का पाउडर, पिसी हुई हल्दी में पीली मिट्टी, कालीमिर्च में पपीते का बीज तथा कटी हुई सुपारी में कटे हुए छुआरे की गुठलियां मिलाना तो आम हो गया है। सदन के ज्यादातर सदस्यों ने तोमर के उठाए इस मुद्दे से खुद को संबद्ध किया।

12 पायलटों की विमान उड़ाने की अनुमति रद, मांगा जवाब

नई दिल्ली, प्रेट्र : डीजीसीए ने हाल ही में रनवे और टैक्सीवे से विमानों के फिसलने के छह मामलों में कड़ी कार्रवाई की है। उसने 12 पायलटों की विमान उड़ाने की अनुमति को रद करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

स्पाइसजेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस और गोएयर के क्रमशः तीन, दो व एक विमान हाल के दिनों में रनवे और टैक्सीवे से फिसल गए थे। इसी सिलसिले में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 12 पायलटों के खिलाफ कार्रवाई की है।

उल्लेखनीय है कि जयपुर से मुंबई जा रहा स्पाइसजेट का विमान सोमवार को भारी बारिश के कारण लैंडिंग के समय रनवे से फिसलकर पास की घास में फंस गया था। इस वजह से मुख्य रनवे को बंद करना पड़ा था। 30 जून को भोपाल से आ रहा स्पाइसजेट का एक अन्य विमान भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण सूरत हवाईअड्डे पर रनवे से नीचे उतर गया था। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बताया कि इन घटनाओं में शामिल दोनों विमानों के पायलटों को डीजीसीए के निर्देशानुसार निलंबित कर दिया गया है।

- डीजीसीए ने रनवे और टैक्सीवे से छह विमानों के फिसलने के मामलों में की कार्रवाई
- स्पाइसजेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस और गोएयर के विमान लैंडिंग के दौरान हुए थे हादसे के शिकार

दो जुलाई को भी स्पाइसजेट का एक विमान कोलकाता हवाईअड्डे पर लैंडिंग के समय रनवे से फिसल गया था। इससे चार लाइटें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। उसी दिन एअर इंडिया एक्सप्रेस का दम्माम (सऊदी अरब) से आ रहा विमान कालीकट हवाईअड्डे पर लैंडिंग के समय क्षतिग्रस्त हो गया था। उसकी पूंछ (पीछे का हिस्सा) टकरा गई थी। 30 जून को एअर इंडिया एक्सप्रेस का एक अन्य विमान मेंगलुरु हवाईअड्डे पर लैंडिंग के बाद टैक्सीवे से फिसलते हुए जमीन में धंस गया था। उसी दिन गोएयर का बेंगलुरु से आ रहा विमान रांची हवाईअड्डे पर लैंडिंग के समय क्षतिग्रस्त हो गया था। उसकी भी पूंछ टकरा गई थी। एअर इंडिया एक्सप्रेस व गोएयर की डीजीसीए की कार्रवाई पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है।

लौह अयस्क खनन के पट्टों पर केंद्र से जवाब तलब

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने लौह अयस्क के 358 खनन पट्टों को रद करने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन खदानों का नए सिरे से मूल्यांकन कराए बिना ही इनमें खनन के लिए कंपनियों के पट्टे की अवधि बढ़ा दी गई है या नए आवंटन किए गए हैं।

जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस बीआर गवई की पीठ के सामने केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएनएस नाडकर्णी ने दलील दी कि दुर्भावना के साथ यह याचिका दायर की गई है और जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया। पीठ ने चार हफ्ते का समय देते हुए कहा कि इस मामले पर विस्तार से सुनवाई की आवश्यकता है।

याचिका दायर करने वाले वकील एमएल शर्मा ने आरोप लगाया है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही इन खनन पट्टों की अवधि बढ़ाई गई है या पट्टे आवंटित किए गए हैं। शीर्ष अदालत ने 16 अप्रैल को केंद्र से कहा था कि वह शर्मा की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे। इस याचिका में शर्मा ने सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अदालत की मदद करने के लिए वरिष्ठ वकील पीएस नरसिम्हा को न्याय मित्र नियुक्त किया है।

शर्मा ने याचिका में आरोप लगाया है कि इस साल फरवरी में उन्हें जानकारी मिली कि राजनीतिक दलों को 'चंदे में बड़ी रकम' देने के बदले में 288 खनन पट्टों की अवधि बढ़ा दी गई है। याचिका के अनुसार इससे सरकारी खजाने को चार लाख करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ है। याचिका में खदानों से निकाले गए खनिज के बाजार मूल्य की वसूली का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। साथ ही इस प्रकरण की न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की मांग भी की गई है।

- सुप्रीम कोर्ट से की गई है 358 खनन पट्टे रद करने की मांग
- नियमों का उल्लंघन कर पट्टे देने या अवधि बढ़ाने का आरोप

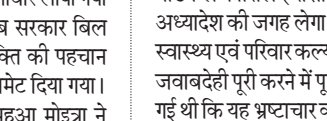

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

हाई कोर्ट में स्वीकृत पदों के मुताबिक न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए शीर्ष अदालत में याचिका

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाई कोर्ट में स्वीकृत पदों के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति में तेजी लाने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इससे न्याय मिलने में देरी से परेशान वादियों की जरूरत पूरी हो सकेगी। यह याचिका उत्तराखंड के वकीलों के समूह यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दायर की है।

याचिका दायर करने वाले समूह ने कहा है कि विभिन्न हाई कोर्ट के साथ ही साथ शीर्ष कोर्ट में कुछ नियुक्तियां हुई हैं। लेकिन एक जून 2019 तक हाई कोर्टों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों में से करीब 39 फीसद खाली थे। कानून मंत्रालय की पिछले साल की रिपोर्ट में कहा गया था कि अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 22,474 है और हाई कोर्ट में स्वीकृत पदों की संख्या 1,079 है। वकीलों के संगठन ने कहा है कि राज्य और उसके अधिकारी संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत भारतीय नागरिकों के प्रदत्त बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं।

उन्मादी भीड़ की हिंसा पर तुरंत सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एएनआइ : सुप्रीम कोर्ट ने उन्मादी भीड़ (मॉब लिंचिंग) की हिंसा को लेकर दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से इन्कार कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इसपर उचित तरीके से ही सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने तुरंत सुनवाई का आग्रह किया गया था।

याचिका में उल्लेख किया गया है कि उन्मादी भीड़ की हिंसा पर पिछले वर्ष जुलाई में शीर्ष कोर्ट के दिए गए फैसले का अनुपालन नहीं किया गया है। कोर्ट ने तब कहा था कि उन्मादी भीड़ के भयावह कारनामे को देश के कानून को कुचलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने उन्मादी भीड़ हिंसा और कथित गोरक्षकों से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।

टिक टॉक पर पाबंदी के मामले मद्रास हाई कोर्ट से स्थानांतरित करने से इन्कार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने चीन के सोशल मीडिया एप टिक टॉक पर पाबंदी से संबंधित मामले मद्रास हाई कोर्ट से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने से गुरुवार को इन्कार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ चीन की कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के इस तर्क से सहमत नहीं थी कि मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ में लंबित टिक टॉक से संबंधित सारे मामले तेजी से निपटारे के लिए शीर्ष अदालत में स्थानांतरित कर दिए जाएं। पीठ ने कहा, 'हम स्थानांतरण याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।' शीर्ष कोर्ट ने कहा, कंपनी अपनी बात संबंधित हाई कोर्ट में रख सकती है। इसके बाद चीनी कंपनी ने याचिका वापस ले ली। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि अंतरिम राहत के रूप में टिक टॉक पर लगाया गया प्रतिबंध हटाने के आवेदन पर वह 24 अप्रैल तक फैसला करे। हाई कोर्ट ने 24 अप्रैल को इस एप पर लगाया गया प्रतिबंध इस शर्त के साथ हटा दिया था कि इस पर अश्लील वीडियो नहीं दिखाए जाएंगे।

आश्वासन

लोकसभा से पारित हुआ आधार संशोधन विधेयक, विपक्षी दलों ने की डाटा संरक्षण पर विधेयक की मांग, सरकार बोली- डाटा हासिल करने की इजाजत नहीं है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सजा भुगतनी पड़ेगी

आधार न होने पर कोई सेवा से वंचित नहीं होगा : रविशंकर प्रसाद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लोकसभा ने गुरुवार को 'आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक 2019' को मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें बैंक में खाता खोलने, मोबाइल फोन का सिम लेने के लिए आधार को स्वैच्छिक बनाया गया है। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आधार को सुरक्षित बताते हुए आश्वासन दिया कि सरकार जल्द ही डाटा संरक्षण विधेयक लाएगी और इसकी प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि आधार संशोधन विधेयक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में लाया गया है। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी के पास आधार नहीं होने की स्थिति में उसे सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता।

केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि निजी कंपनी को आधार का कोर डाटा हासिल करने की इजाजत नहीं है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि आधार संप्रग सरकार के समय जरूर आरंभ हुआ था, लेकिन उस वक्त वह निराधार था और मोदी सरकार ने इसे कानून बनाया है। प्रसाद ने कहा कि देश की 130 करोड़ की आबादी में 123.8 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड हैं। देश में 69 करोड़ मोबाइल फोन कनेक्शन आधार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आधार को सुरक्षित करार देते हुए कहा कि देश की जनता ने आधार की उपयोगिता को स्वीकार किया है।

कानून मंत्री के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियां आधार का इस्तेमाल ग्राहकों की सहमति पर ही कर सकती हैं। साथ ही धारकों को वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है, जिसमें वे पासपोर्ट, राशन कार्ड की कॉपी दे सकते हैं। रविशंकर ने आधार के फायदे बताते हुए कहा कि आधार के जरिये सरकार के 1.41 लाख करोड़ रुपये बचे हैं और लोगों तक सरकारी सेवाएं आसानी से पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि जब देश में ईमानदार सरकार होगी तब कुछ लोगों को परेशानी होगी।

विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार बार-बार अध्यादेश का रास्ता अपना रही है जो लोकतंत्र कमजोर करने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने आधार को संप्रग सरकार से उधार लिया है, लेकिन वह श्रेय नहीं देना चाहती। कांग्रेस के ही सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि किसी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार लाया गया था। लेकिन 2016 में जब सरकार बिल लेकर आई तो उसमें व्यक्ति की पहचान को सिर्फ एक नंबर तक समेट दिया गया।

तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने आधार के साथ ही डाटा संरक्षण के लिए भी कदम उठाने की जरूरत बताई। बीजद के पिनाकी मिश्रा ने आधार कानून को महत्वपूर्ण और अच्छा बताते हुए साथ में डाटा संरक्षण विधेयक भी लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि डाटा संरक्षण नहीं होने के कारण इसमें कई चुनौतियां हैं। मिश्रा ने कहा कि कुछ एजेंसियां हैं जो अपने फायदे के लिए लोगों के निजी आंकड़ों का इस्तेमाल कर रही हैं।

एमसीआइ संशोधन विधेयक पर संसद ने लगाई मुहर

नई दिल्ली, प्रेट्र : संसद ने मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया (एमसीआइ) सितंबर 2020 तक दो साल के लिए शक्ति छीनने वाले विधेयक को पारित कर दिया। राज्यसभा में गुरुवार को ध्वनिमत से यह विधेयक पारित हो गया। मंगलवार को ही लोकसभा ने विधेयक पर मुहर लगा दी थी। इंडियन मेडिकल कौंसिल (संशोधन) विधेयक 2019, 21 फरवरी को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि मेडिकल कौंसिल जवाबदेही पूरी करने में पूरी तरह विफल रहा और देश में व्यापक धारणा बन गई थी कि यह भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन गया है। उन्होंने कहा कि गणमान्य डॉक्टरों को बोर्ड आफ गवर्नर्स (बीओजी) के रूप में जवाबदेही निभाने की शक्ति प्रदान की गई है और यह प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'हम (सरकार) उनके काम में दखल नहीं दे रहे हैं लेकिन हम उनके कामकाज पर गहरी नजर रख रहे हैं।' बोर्ड आफ गवर्नर्स के विभिन्न कदमों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जहां 2018-19 के दौरान कुल 21 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई थी वहीं 2019-20 में यह संख्या बढ़कर 27 हो गई है। उन्होंने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या भी वर्तमान वर्ष में बढ़कर 35,327 हो गई है। 2018-19 में सीटों की संख्या 33,422 थी। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए करीब 59 लोग प्रणाली से हटाए गए हैं।

कह के रहेंगे माधव जोशी

1000 वर्गफुट के मकानों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना जरूरी होगा झारखंड की राजधानी रांची में। नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे निगम बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 5 जुलाई 2019

सांसदों को शाह की सलाह, निर्भीक रूप से रखें पार्टी की विचारधारा

नए सांसदों को दिया प्रभावी बनने का मंत्र, सांसद निधि को लेकर भी किया नए सदस्यों को आगाह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने नए सांसदों से संसद की गरिमा को मजबूत करने के लिए काम करने की सलाह दी है। उन्होंने सांसदों को जहां निर्भीक होकर अपनी पार्टी की विचारधारा को रखने के लिए उत्साहित किया है वहीं सांसद निधि के सही उपयोग को लेकर भी आगाह किया। शाह ने कहा कि सांसद निधि के कारण कई सांसद बदनाम हो चुके हैं, ऐसे में नियम कायदे से बाहर जाकर सांसद निधि का उपयोग न करें।

लोकसभा के लिए चुनकर आए नए सांसदों के लिए लोकसभा सचिवालय की ओर से प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें एक सत्र सांसदों के प्रभावी बनने के लिए गुर सिखाने से संबंधित था। शाह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस सत्र को संबोधित किया। शाह ने परोक्ष रूप से भाजपा के विरोधियों पर तंज भी किया और सांसदों को आगाह भी। उन्होंने कहा कि संसद राजनीतिक आरोपों का मंच नहीं है। लेकिन एक बड़ा कालखंड ऐसा रहा है जब अच्छी बातों को भी स्वीकार करने से पहले यह देखा जाता था कि वह बात कहां से आई है। जाहिर तौर पर उनका इशारा भाजपा की विचारधारा के प्रति दूसरे दलों के व्यवहार की तरफ था। उन्होंने कहा कि संसद के प्रवेश द्वार पर ही धर्म की बात लिखी है लेकिन वह धर्म कर्तव्य और दायित्व है। अगर धर्म के साथ सरकार चलाने की बात होती है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए।

संसद में खुलकर विवेक के साथ अपनी और अपनी पार्टी की विचारधारा के अनुरूप बात रखने की सलाह देते हुए शाह ने कहा कि महाभारत सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि राज दरबार के सदस्यों ने निर्भीक होकर अपनी बात नहीं रखी और राजा की हर बात मानते गए। शाह ने कहा कि यह वक्त है कि सांसद अपना प्रभाव दिखाएं वरना विधायिका पर दूसरे क्षेत्रों का हस्तक्षेप बढ़ना तय है। शाह ने बताया कि संसद में मौजूद तौर तरीकों से हम देश की दिशा तय कर सकते हैं। इसी क्रम में उन्होंने यह भी बताया कि 1991 में केएच मुनियप्पा ने प्रश्न उठाया था कि क्या केरल के कुछ स्कूलों में वंदे मातरम नहीं गया जाता है? तब भाजपा सांसद राम नाइक ने उसी सवाल के माध्यम से आधे घंटे की चर्चा की मांग की और सुझाव दिया कि जन गण मन व वंदे मातरम संसद के अंदर गाया जाएगा तो नीचे तक प्रेरणा मिलेगी। 1991 के बाद से ही संसद में जन गण मन गाया जाता है।

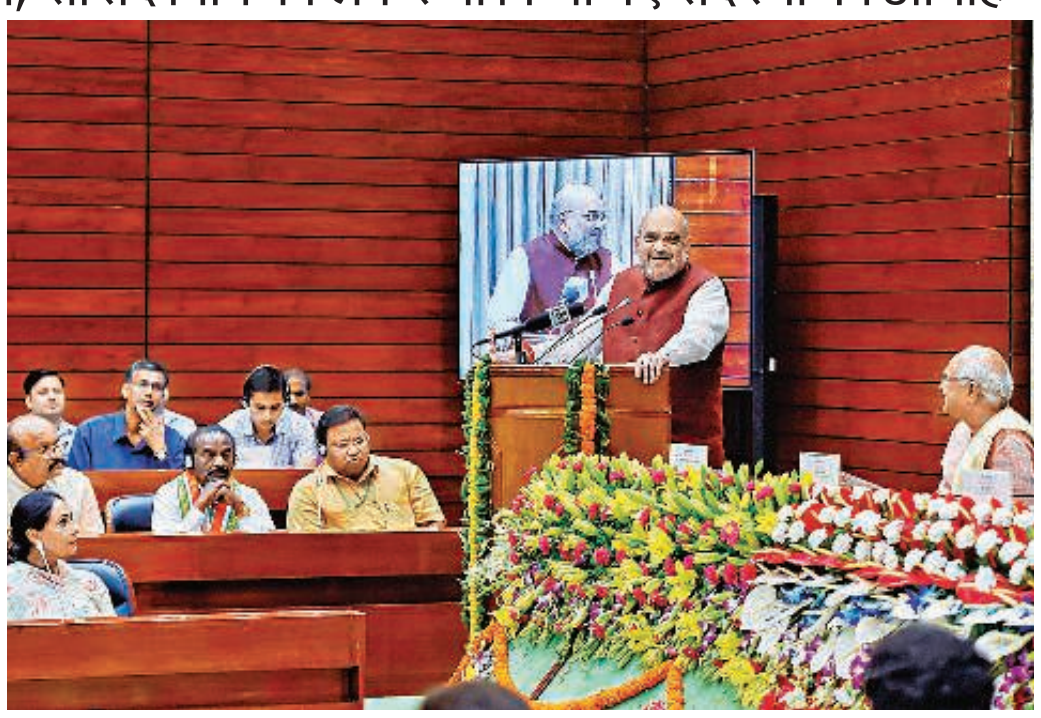

नई दिल्ली में प्रशिक्षण कार्यशाला में गृहमंत्री अमित शाह ने 17वीं लोकसभा के लिए चुनकर आए भाजपा के सांसदों को कामकाज को लेकर सलाह दी। प्रेट्र

'शिकायतों का समाधान न करने वालों की होगी छुट्टी'

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

आम जनता की शिकायतों का समाधान समय से हो, इसके लिए गुरुवार से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू हुई। इसके लिए 1076 नंबर पर डायल करना होगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने समस्याओं का निदान न हो पाने पर नाराजगी जताते हुए लापरवाह अधिकारियों की छुट्टी करने की चेतावनी भी दी।

लोकभवन में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का शुभारंभ करते हुए योगी ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात भी कही। उनका कहना था कि सीएम हेल्पलाइन दो काम अवश्य करेगी। एक तो व्यवस्था को संवेदनशील बनाएगी, दूसरा इसे एसीआर (वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि) से जोड़ा जाएगा। योगी ने सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत तब बंद होगी जब शिकायतकर्ता खुद ही न कह दे कि समस्या का समाधान हो गया। अगर शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं तो उच्चाधिकारियों को मामला सौंपा जाएगा और जवाबदेही भी तय होगी।

योगी आदित्यनाथ फाइल फोटो

24 घंटे होगी सुनवाई : मुख्यमंत्री हेल्पलाइन -1076 पर किसी प्रकार की शिकायत 24 घंटे में किसी भी समय दर्ज कराई जा सकती है। इस कालसेंटर में 500 सीटों की व्यवस्था है जिसे एक हजार तक बढ़ाया जा सकता है। विभूति खंड गोमतीनगर में साइबर टावर पर पांचवें व छठें तल पर बनाए गए इस काल सेंटर की प्रतिदिन 80 हजार इन कमिंग व 55 हजार आउट गोइंग काल्स की क्षमता है। मुख्यमंत्री हेल्प लाइन पर सूचना का अधिकार, राज्य कर्मियों की सेवा संबंधित मामले और न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण व राज्य एवं केंद्र सरकारों के खिलाफ दर्ज परिवाद से जुड़ी शिकायतें दर्ज नहीं की जाएंगी।

उम्र संबंधी छूट लेने वाले आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशी को सामान्य सीट नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चयन प्रक्रिया में उम्र संबंधी छूट का लाभ लेने वाला आरक्षित श्रेणी का प्रत्याशी बाद के चरण में सामान्य श्रेणी की सीट पर स्थानांतरित करने का दावा नहीं कर सकता है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को कहा कि संविधान का अनुच्छेद 16(4) सरकार को ऐसे किसी भी पिछड़े वर्ग को नियुक्तियों में आरक्षण देने की शक्ति देता है जिन्हें उसकी राय में सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने गुजरात हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि किसी आरक्षित श्रेणी में होने के कारण उम्र संबंधी छूट का लाभ उठाने वाले प्रत्याशी सामान्य श्रेणी के लिए विचार किए जाने के हकदार नहीं हैं। उनके मामलों पर केवल आरक्षित श्रेणी के लिए ही विचार किया जा सकता है। शीर्ष कोर्ट ने यह फैसला हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाले नीरव कुमार दिलीपभाई मकवाना नाम के प्रत्याशी की याचिका पर आया है जिसमें गुजरात लोकसेवा आयोग की चयन प्रक्रिया को बरकरार रखा गया था। पीठ ने कहा, 'राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब लिखित परीक्षा में प्रयासों की संख्या की अनुमति, आयु सीमा, अनुभव, योग्यता आदि में एससी, एसटी और एसईबीसी श्रेणी के लिए किसी उम्मीदवार के चयन में कोई छूट संबंधी मानक लागू होता है तो इस तरह से चयनित इस श्रेणी के उम्मीदवार पर केवल आरक्षित सीट के लिए ही विचार किया जा सकता है। इस तरह के उम्मीदवार को अनारक्षित सीट पर विचार के लिए अनुपलब्ध माना जाएगा।'

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 साल

राहत ▶ प्रदेश में अभी 35 साल तय थी उम्र, जिसका किया जा रहा था विरोध

दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी मिलेगा लाभ

नईदुनिया, भोपाल

कमलनाथ सरकार ने आखिरकार सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा नए सिरे से तय कर दी है। अब अन्य राज्यों सहित प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा एक समान 40 वर्ष रखी गई है। गत 11 जून को प्रदेश सरकार ने अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष कर दी थी। इससे अनारक्षित वर्ग के मध्य प्रदेश के निवासियों को पांच साल का नुकसान हो रहा था। अब मप्र के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नगर सैनिक, महिला और निगम, मंडल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को पांच साल की छूट दी जाएगी। यह निर्णय गुरुवार से प्रभावी हो गया।

सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट जबलपुर के निर्णय के मद्देनजर सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा को 28 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष की थी। यह फैसला मप्र सहित अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए लागू हुआ था, लेकिन इससे प्रदेश के अनारक्षित वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच साल का नुकसान हो रहा था। पहले प्रदेश के अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा सरकारी नौकरियों के लिए 40 साल थी। नए प्रावधानों से हो रहे नुकसान के चलते हो रहे विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सामान्य प्रशासन विभाग को पूरे मामले का परीक्षण करने के निर्देश दिए थे। विभाग ने मुख्यमंत्री को बताया कि वर्ष 2016 तक अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष ही थी। 12 मई 2017 को संशोधित कर अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष की गई। मप्र के मूल निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट दी गई थी। इसमें अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को पांच साल की अतिरिक्त छूट दी गई थी।

कमलनाथ फाइल फोटो

हाई कोर्ट के आदेश पर किया था आयु सीमा में बदलाव : उच्च शिक्षा विभाग के सहायक प्राध्यापकों की भर्ती में इस प्रावधान को लेकर हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की गई। इस पर हाई कोर्ट ने सात मार्च 2018 आदेश दिया कि यह प्रावधान संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और इसे निरस्त कर दिया। उच्च शिक्षा विभाग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन सुनवाई से पहले याचिका वापस ले ली गई। तत्कालीन शिवराज सरकार ने विधानसभा चुनाव के कारण इस पर कोई फैसला नहीं किया। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के चलते कमलनाथ सरकार भी इस पर फैसला नहीं ले सकी। आचार संहिता समाप्त होने के बाद नियुक्तियों पर पड़ रहे असर को देखते हुए विधि विभाग की सलाह पर अधिकतम आयुसीमा को 28 से बढ़ाकर 35 वर्ष करने का कैबिनेट में प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूरी मिल गई। इससे प्रदेश के अनारक्षित वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच साल का नुकसान हो रहा था। चौतरफा विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुनः परीक्षण करने के निर्देश दिए थे।

अब ये होंगे प्रावधान

- **राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजपत्रित और कार्यपालिक पदों के लिए होने वाली भर्ती में न्यूनतम आयु सीमा 21 और अधिकतम 40 वर्ष रहेगी। वहीं, राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होगी।**
- **अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय, निगम, मंडल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, नगर सैनिक, नि :शक्तजन एवं महिलाओं (आरक्षित-अनारक्षित) के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट रहेगी, यानी 45 साल तक शासकीय सेवा में आने का मौका मिलेगा।**

रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अनिवार्य : प्रदेश सरकार ने आयु सीमा बढ़ाने के साथ सभी के लिए रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। इससे अन्य राज्यों के वे अभ्यर्थी ही नियुक्ति के पात्र होंगे, जिनका रोजगार कार्यालय में पंजीयन होगा।

योगी सरकार से प्रियंका की ट्विटर पर छिड़ी जंग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

सोशल मीडिया अब राजनीति का बड़ा मंच बनता जा रहा है। कांग्रेस की तो 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी इसी पर नजर आ रही है। संगठन मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पूर्वी उप्र प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर पर ही मोर्चा खोल रखा है।

आम चुनाव में मिली हार के बाद से कांग्रेस पूरी तरह बिखरी-बिखरी नजर आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इस्तीफा दे चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और सभी जिला कमेटियां भंग की जा चुकी हैं। लिहाजा, सड़क पर कहीं भी कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहीं प्रियंका गांधी वाड्रा अकेले ही सरकार से टक्कर ले रही हैं। इसके लिए उन्होंने ट्विटर को माध्यम बनाया है। अलीगढ़ में मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद से हर दूसरे-तीसरे दिन प्रदेश में घट रही बड़ी वारदात पर वह सरकार की घेराबंदी का प्रयास कर रही हैं। जन समस्याओं पर भी वह नजर जमाए हुए हैं।

खास बात यह है कि प्रियंका के ट्वीट को सरकार भी नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं है। पिछले दिनों उन्होंने सूबे में बढ़ते अपराध पर टिप्पणी की तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध के आंकड़े पेशकर ट्विटर पर सफाई दी। इसी तरह बिजली संकट को लेकर प्रियंका के ट्वीट का भी जवाब बुधवार को ऊर्जा मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बयान जारी कर दिया।

प्रियंका गांधी वाड्रा फाइल फोटो

मुजफ्फरनगर की घटना पर ताजा ट्वीट : पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में दारोगा को गोली मारकर अपराधी को हिरासत से छुड़ाने के मामले पर प्रियंका ने ताजा ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, 'उप्र सरकार के नेता प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराध पर मेरे ट्वीट का कुछ भी झूठ-मूठ जवाब दे दें, मगर पुरानी कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े-लिखे को फारसी क्या। उप्र में अपराधियों के कारनामे चरम पर हैं और जनता पूछ रही है कि ऐसा क्यों?'

धर्मेंद्र ने दी सनी देयोल को नसीहत-भगवंत मान से सीखो

सुमित मलिक, जालंधर

गुरदासपुर से पहली बार सांसद बने सनी देयोल किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब उनके पिता व पूर्व भाजपा सांसद धर्मेंद्र ने सनी को आप सांसद भगवंत मान से सीखने की नसीहत दे दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सांसद मान भारत माता की सेवा कर रहे हैं और उन्हें उन पर बहुत मान है। उनके इस ट्वीट के बाद जहां लोग सनी के काम पर सवाल उठाने लगे, वहीं उन्होंने धर्मेंद्र की बतौर भाजपा नेता किसी विपक्ष के नेता की तारीफ करने को भी सराहा।

कुछ यूजर्स खुलकर सनी के हक में भी आए। एक ने तो धर्मेंद्र से भी पूछा कि आखिर भगवंत मान ने ऐसा क्या किया है जो सनी नहीं कर पाए? इस पर धर्मेंद्र ने जवाब दिया कि मान ने अपना करोड़ों का फिल्मी कॅरियर त्याग दिया है। इसी सराहना और आलोचना के बीच धर्मेंद्र ने दोनों ट्वीट हटा दिए। दरअसल, एक यूजर ने सनी देयोल की मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आते की एक फोटो ट्विटर पर शेयर कर उसमें सनी के डैशिंग (प्रभावशाली) लुक का जिक्र किया

कुछ ने की सराहना, तो कुछ ने जताई आपत्ति, बाद में धर्मेंद्र ने हटाया ट्वीट

था। इसी तस्वीर का जवाब देते हुए धर्मेंद्र ने सनी को सलाह दी कि वे मान से कुछ सीखें। धर्मेंद्र ने ट्वीट किया, 'सनी, मेरे बेटे, कोशिश करो कि संगरूर के सांसद भगवंत सिंह मान जो कि मेरे बेटे जैसा है, उससे कुछ सीखो। भारत मां की सेवा करने के लिए क्या त्याग किया है.. जीते रहो...मान। बहुत-बहुत मान है मुझे आप पर...।'

सुबह करीब साढ़े छह बजे किए गए इस ट्वीट को दोपहर तक सैकड़ों लोगों ने शेयर किया और एक आप नेता के प्रति भाजपा के पूर्व सांसद की सोच को भी सराहा। आम आदमी पार्टी के वालंटियरों ने भी उनकी इस पोस्ट को खूब री-ट्वीट किया। साथ ही लिखा-चलो भाजपा में कोई तो है जो मान के कामों की तारीफ कर रहा है।

यूजर ने पूछा, 'क्या त्याग किया है मान ने?': इसी बीच एक यूजर ने ट्वीट कर पूछा, 'क्या त्याग किया है मान ने?' इस पर धर्मेंद्र ने भी तुरंत जवाब दिया 'अपना करोड़ों का पेशा, अपना फिल्मी कॅरियर'।

एक फाइल ने कमजोर की 17 जातियों के आरक्षण की जंग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

सिर्फ एक फाइल ने 17 जातियों की किस्मत को सियासी दांवपेच में उलझा दिया है। अति पिछड़ी से अनुसूचित श्रेणी में शामिल होने को बेताब इन जातियों के झंडाबरदार मानते हैं कि कांग्रेस शासनकाल में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 की फाइल साजिशन गायब कराई गई, क्योंकि वह होती तो मामला तुरंत निपट जाता।

उप्र की अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने को प्रयासरत दलित शोषित पिछड़ा वर्ग अधिकार दल के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव नीरज प्रजापति ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मुकुल वासनिक और कुमारी शैलजा के खिलाफ नई दिल्ली के संसद मार्ग थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इसके लिए वादी ने दलित शोषित वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतराम प्रजापति को सूचना के अधिकार के तहत मिले जवाब को आधार बनाया है। उसमें मंत्रालय द्वारा ही स्वीकार किया गया है कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 की फाइल मिल नहीं रही है।

इस मुद्दे पर 2003 से आंदोलनरत संतराम प्रजापति का कहना है कि उस फाइल में 1931 की रिपोर्ट लगी है, जिसमें सभी 66 जातियों और उपजातियों के पेशे व प्रदेश में स्थानवार मौजूदगी का उल्लेख है। उन्होंने बताया कि पहली बार इन सभी जातियों को 1935 में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। उसके बाद 1949 में वही रिपोर्ट भेजी गई, जिसके आधार पर संविधान सभा ने आदेश पारित किया और प्रस्तावना में इन जातियों के मानकों का उल्लेख करते हुए अनुसूचित जाति में शामिल किया। संविधान सभा द्वारा 10 अगस्त 1950 को जारी आदेश के बाद से सभी जातियों के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र बनने लगे।

राहुल की तरह इस्तीफा नहीं देंगे तेजस्वी : राजद

पार्टी ने खारिज की कांग्रेस की सलाह, कहा-हम नेता प्रतिपक्ष के साथ

राज्य ब्यूरो, पटना

'अज्ञातवास' से पांच हफ्ते बाद लौटे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए महागठबंधन के सहयोगी दलों की ओर से सुकून भरी खबर नहीं है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की तरह नैतिकता के आधार पर तेजस्वी को इस्तीफा देने की सलाह दी है। हालांकि राजद ने कांग्रेस की सलाह को मजबूती से खारिज कर दिया है। कांग्रेस की सलाह के बाद राजद पूरी मजबूती से तेजस्वी यादव के साथ खड़ा हो गया। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे नेता ने इस्तीफा दिया तो हम सभी विधायक भी सामूहिक इस्तीफा देंगे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में राजद के खराब प्रदर्शन के बावजूद पार्टी तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार करती है।

आखिरकार सदन पहुंचे तेजस्वी : विधानमंडल के मानसून सत्र में गुरुवार को शिरकत करने पहुंचे तेजस्वी को कांग्रेस के दो विधायक अजीत शर्मा एवं राजेश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष पद से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की अगर जीत होती तो अभी सब मिलकर जश्न मना रहे होते। इसी तरह पराजय के लिए भी सामूहिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तेजस्वी यादव को भी राहुल गांधी का अनुकरण करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे आम जनता में तेजस्वी का सम्मान बढ़ सकता है। कांग्रेस विधायक राजेश कुमार ने भी इशारों में तेजस्वी से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि हार की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष की तरह गठबंधन के अन्य साथी दलों को भी साहसिक फैसला लेने पर विचार करना चाहिए। राजेश का इशारा तेजस्वी की तरफ था। कांग्रेस की मांग का भाजपा ने भी समर्थन किया है।

विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद बाहर निकलते नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। जागरण

असमंजस

दिनभर चलती रही इंदौर विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी करने की अफवाह, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, संगठन महामंत्री रामलाल से भी की बात

आकाश पर कार्रवाई को लेकर नहीं हो सका फैसला

नईदुनिया, भोपाल

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर विधानसभा क्रमांक तीन से विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला दिल्ली और भोपाल के बीच झूल रहा है। सदस्यता अभियान की तैयारी के लिए भोपाल आए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह ने गुरुवार को सदस्यता अभियान की बैठकों के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, संगठन महामंत्री रामलाल से फोन पर बातचीत की। इसके बाद उनकी कैलाश विजयवर्गीय से भी मोबाइल पर बात हुई। इस कवायद को भी आकाश के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है।

तीन दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में कहा था कि ऐसे अमर्यादित आचरण करने वाले को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, चाहे वह किसी का भी बेटा हो। गौरतलब है कि जर्जर मकान तोड़ने गए इंदौर नगर निगम के अफसर के साथ विधायक आकाश विजयवर्गीय ने क्रिकेट के बल्ले से मारपीट की थी। इसका वीडियो देशभर में वायरल हुआ और भाजपा को चारों तरफ से आलोचना झेलना पड़ी थी।

आकाश विजयवर्गीय फाइल फोटो

भाजपा कार्यालय में गुरुवार को दिनभर गहमा-गहमी रही। दरअसल, दोपहर 12 बजे के करीब प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह के प्रदेश कार्यालय में पहुंचने के साथ ही मीडिया ने उन्हें घेर लिया। आकाश पर कार्रवाई को लेकर कई सवाल हुए, लेकिन वह सिर्फ सदस्यता अभियान पर अपनी बात कहकर निकल गए। इसके बाद न्यूज चैनलों पर विधायक आकाश को नोटिस देने की खबरें चलने लगीं। भारी दबाव के बाद पौने चार बजे के करीब सिंह मीडिया के सामने आए और मात्र 20 सेकंड में सफाई दी कि अभी पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

कैलाश विजयवर्गीय के दबाव में लाचार हुआ संगठन : ओझा

कांग्रेस के मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने गुरुवार को जारी बयान में कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय के दबाव में केंद्र और राज्य संगठन आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ फैसला नहीं ले पा रहा है। दोनों ही स्तर पर संगठन लाचार है। आश्चर्य की बात यह भी है कि विधायक ने प्रधानमंत्री की इच्छा साफ होने के बाद भी अब तक त्यागपत्र नहीं दिया है।

अभी हमारे द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पार्टी की कार्यपद्धति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। निर्णय से आपको अवगत कराया जाएगा।

- राकेश सिंह, प्रदेशाध्यक्ष, मप्र भाजपा

बेटे की करतूत पर राणे ने मांगी माफी

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने अपने विधायक बेटे नितेश राणे की करतूत पर माफी मांगी है। नारायण राणे भाजपा से राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने कहा, 'अपने बेटे द्वारा सरकारी अधिकारी पर कीचड़ डालने की घटना के लिए मैं माफी मांगता हूं। विरोध (राजमार्ग की खराब हालत के खिलाफ) स्थानीय लोगों के लिए था।'

क्या था मामला : दरअसल, नीतेश राणे अपने विधानसभा क्षेत्र कांकावाली में शेडेकर के साथ मुंबई-गोवा हाईवे का मुआयना कर रहे थे। हाईवे पर काफी गड्ढे हैं जिसे भरा नहीं जा रहा था। लोग कीचड़ में सफर कर रहे थे। इसी बात से नाराज नितेश राणे और उनके समर्थकों ने इस घटना को अंजाम दिया। बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने नगर निगम के एक अधिकारी को बल्ले से पीटा था। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश के इस बर्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सख्त नाराजगी जताई थी। पीएम मोदी ने इस घटना पर कार्रवाई करने की ओर इशारा करते हुए मंगलवार को कहा था कि 'बेटा किसी का भी हो, ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा'।

छत्तीसगढ़ में अच्छे प्रदर्शन पर ही बचेगी मंत्रियों की कुर्सी

नईदुनिया, रायपुर

- **पहले प्रदेश प्रभारी और अब मुख्यमंत्री ने भी काम में कसावट लाने का दिया निर्देश**
- **एक साल पूरा होने पर बनेगा रिपोर्ट कार्ड, हाईकमान को सौंपा जाएगा**

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों की कुर्सी उनके अच्छे प्रदर्शन से ही बच सकेगी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के बाद अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मंत्रियों को साफ कह दिया है कि वे अपने कामकाज और विभागों में कसावट लाएं। सरकार के एक साल पूरा होने पर मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, जो दिल्ली तक जाएगा।

पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की ताजपोशी और अमरजीत भगत के मंत्री बनने पर प्रदेश प्रभारी पुनिया आए थे, तभी उन्होंने साफ कह दिया था कि मंत्रियों को काम करके दिखाना है। एक साल में एक-एक मंत्री के काम की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद बुधवार रात को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट की बैठक ली, तो उन्होंने मंत्रियों से कहा कि सभी अपने विभागों में प्रशासनिक कसावट लाएं। जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ दूर करें। सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ हितग्राहियों को मिलना चाहिए। हर मंत्री को अपने विभाग के प्रशासनिक कामकाज की गंभीरता के साथ मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने भी संकेत दिया है कि मंत्री की कुर्सी मिली है, तो काम करके दिखाना होगा। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों की मानें तो अभी सरकार को छह माह पूरा होने पर ही कुछ मंत्रियों को बदले जाने का विचार हुआ था, लेकिन उसके बाद यह तय हुआ कि छह माह का समय और दिया जाए।

सीएम के पास विकल्प की कमी नहीं : मुख्यमंत्री के पास मंत्री बनाने के लिए विकल्प की कमी नहीं है। 90 में से 68 विधायक कांग्रेस के हैं, जिसमें से लगभग आधे विधायक पुराने हैं। इसमें से पांच विधायक सत्यनारायण शर्मा, रामपुकार सिंह, धनेंद्र साहू, अमितेष शुक्ल और मनोज मंडावी को मंत्री पद का अनुभव है।

4,551 स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, होटल, कोचिंग सेंटर, सिनेमा घर, हॉस्टल के अलावा मल्टी स्टोरी भवनों का सर्वे किया था दमकल विभाग ने बीते एक माह में हरियाणा में। इनमें से 809 भवनों में बड़ी खामियां मिली हैं। इन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

रोहतक सामूहिक दुष्कर्म, हत्या मामले में सात दोषियों की फांसी पर रोक

बड़ा मामला ▶ शीर्ष अदालत सजा के खिलाफ दोषियों की अपील पर सुनवाई के लिए भी हुई राजी

2015 में नेपाली महिला की दुष्कर्म के बाद की गई थी हत्या

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने रोहतक में मानसिक रूप से विक्षिप्त नेपाली महिला की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सात दोषियों की फांसी की सजा पर गुरुवार को रोक लगा दी। शीर्ष अदालत सजा के खिलाफ दोषियों की अपील पर सुनवाई के लिए भी राजी हो गई है।

प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार करते हुए मौत की सजा पर रोक लगा दी। यह जघन्य घटना पहली फरवरी, 2015 को हुई थी। निचली अदालत ने उसी साल 21 दिसंबर को सात दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए जुर्माने की रकम को 50 हजार से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया था। हाई कोर्ट ने इस अपराध को 'बर्बर', 'क्रूर' और 'हिंसक' करार देते हुए हत्या के लिए सातों दोषियों पदम उर्फ प्रमोद, पवन, सरवर उर्फ बिल्लू, मनबीर उर्फ मन्नी, राजेश उर्फ घोचरू, सुनील (मादा) और सुनील (शीला) की मौत की सजा को बरकरार रखा था। साथ ही सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में आठवां आरोपित सोमबीर फरार था और उसने बाद में दिल्ली के बवाना में जहर खाकर खुदकशी कर ली थी।

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

तब कोर्ट ने की थी टिप्पणी : औरत न तो बेबस है और न ही उपयोग की वस्तु

जासं, रोहतक : फरवरी, 2015 में सामूहिक दुष्कर्म के बाद नेपाली युवती की हत्या के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सातों दोषियों की फांसी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। इससे पहले 21 दिसंबर, 2015 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा सिंघल की कोर्ट ने उक्त सभी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। 256 पन्ने के फैसले में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि औरत न तो बेबस है और न ही उपयोग की वस्तु, ऐसे अभियुक्तों के लिए मौत की सजा भी कम है। साथ ही कहा था कि यह माफी के लायक नहीं है। बता दें कि नेपाल निवासी दिव्यांग युवती रोहतक के चिन्योट कॉलोनी में अपनी बड़ी बहन के घर आई हुई थी। 1 फरवरी, 2015 को वह घर से निकलकर रास्ता भटककर हिसार रोड पर पहुंच गई थी। यहां से नौ लोग उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ बहुअकबरपुर के खेतों में ले गए थे। वहां पर आरोपितों ने शराब पी और सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी। हाई कोर्ट के आदेश पर इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई।

क्या था मामला? : दोषियों ने पहली फरवरी, 2015 को हरियाणा के रोहतक के गड्डी खेरी गांव में मानसिक रूप से विक्षिप्त नेपाली महिला की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। महिला का शव गांव के ही खेत में मिला था। पोस्टमार्टम के दौरान महिला के पेट से कंकड़ और ब्लेड के टुकड़े मिले थे, जिससे दोषियों की हैवानियत का पता चला था। इस मामले ने 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया कांड की याद दिला दी थी। पैरामेडिकल की छात्रा निर्भया के साथ भी सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

उप्र में शिया-सुन्नी वक्फ बोर्ड में हुए घोटाले की होगी सीबीआइ जांच

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उप्र सरकार शिया व सुन्नी वक्फ बोर्ड में हुए घोटाले की सीबीआइ जांच कराने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद मुस्लिम वक्फ राज्यमंत्री मोहसिन रजा ने गुरुवार को दावा किया कि सरकार बहुत जल्द सीबीआइ जांच की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने औपचारिकता पूरी करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, 2017 में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी तो उस समय भी शिया व सुन्नी वक्फ बोर्ड पर घोटाले का आरोप लगाकर सीबीआइ जांच कराने की घोषणा हुई थी, लेकिन न जरूरी औपचारिकताएं पूरी की गईं और न ही दोनों बोर्ड के अध्यक्षों को आरोप पत्र दिए गए। बस कारण बताओ नोटिस की फाइल इधर से उधर घूमती रही। इसके बाद सरकार ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल से दोनों वक्फ बोर्ड पर लगे आरोपों की जांच रिपोर्ट मंगाई।

इन बिंदुओं को आरोप पत्र में शामिल करने की बात कही गई। इसके बावजूद आरोप पत्र फाइनल नहीं हो सके। अब फिर सरकार ने सीबीआइ जांच कराने की बात कही है। मोहसिन रजा ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर शिया-सुन्नी वक्फ बोर्ड के घोटाले पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सीबीआइ जांच कराने का आश्वासन दिया है।

प्रतीकात्मक

> यह बात सही है कि पहले भी सीबीआइ जांच की घोषणा हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से फाइल ठंडे बस्ते में चली गई थी। इन सभी बातों को मैंने मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने मामले की सीबीआइ जांच कराने को मंजूरी दे दी है।
> **-मोहसिन रजा, मुस्लिम वक्फ राज्यमंत्री**

एसआइटी जांच भी ठंडे बस्ते में : जब सीबीआइ जांच की औपचारिकताएं पूरी नहीं हो सकीं तो सरकार ने बीते वर्ष नवंबर में शिया-सुन्नी वक्फ बोर्ड की एसआइटी जांच कराने के निर्देश दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

बोर्ड भंग करने में भी विफल : मुस्लिम वक्फ राज्यमंत्री मोहसिन रजा ने सरकार बनने के बाद दोनों वक्फ बोर्ड भंग करने की बात कही थी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकी। शुरुआत में सरकार ने बगैर कागजी कार्यवाही पूरी किए शिया व सुन्नी वक्फ बोर्ड के कई सदस्यों को हटा दिया था। बाद में ये सदस्य हाई कोर्ट गए और उन्हें राहत मिल गई। सरकार को सभी सदस्यों को बहाल करना पड़ा। आज भी यह सदस्य इन बोर्ड में तैनात हैं।

जांच हुई तो कई बड़े भी आएंगे लपेटे में : वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ी की सीबीआइ जांच हुई तो इसमें कई बड़े भी लपेटे में आएंगे। पिछले 10 साल में जो गड़बड़ियां हुई हैं, उसमें कई पूर्व मंत्री व अफसर भी फंस सकते हैं। सरकार को जो शिकायतें मिली हैं, उनमें ज्यादातर वक्फ संपत्तियों को बेचने की हैं। कई जगह वक्फ संपत्तियां कौड़ियों के भाव दे दी गईं।

न्यूज गैलरी

पीसीएस-जे भर्ती की सीबीआइ जांच की याचिका खारिज

प्रयागराज : पीसीएस-जे 2018 भर्ती परीक्षा प्रक्रिया की सीबीआइ जांच कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज हो गई है। याचिका में परीक्षा प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए उसे निरस्त करने की मांग की गई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की पीठ ने दिया। अनुराग त्रिपाठी व 141 अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि पीसीएस-जे 2018 की परीक्षा में धांधली हुई है। ऐसे में इसको निरस्त कर अनियमितता की जांच कराई जानी चाहिए। इस पर राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अजित कुमार सिंह का कहना था कि संभावनाओं के आधार पर याचिका पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी मात्र से परीक्षा की शुचिता पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। कोर्ट ने याचिका में कोई ठोस तथ्य न पाते हुए हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया। (जासं)

ताजमहल में अमेरिकी पर्यटक के साथ बदसुलूकी

आगरा : ताजमहल में कमीशनखोरी के खेल से गुरुवार को ताजनगरी शर्मसार हो गई। अमेरिकी पर्यटक ने फोटोग्राफरों द्वारा स्मारक में बदसुलूकी करने की शिकायत पर्यटन पुलिस से की। वहीं, फोटोग्राफरों ने गाइड द्वारा कमीशन की मांग और झूठी शिकायत कराने का ज्ञापन सौंपा। बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। अमेरिकी पर्यटक मेजर क्रिस्टोफर जेन परिवार के साथ गुरुवार सुबह 7:30 बजे ताजमहल पहुंचे थे। उन्होंने सीओ ताज सुरक्षा मोहसिन खान से फोटोग्राफरों द्वारा बदसुलूकी करने की लिखित शिकायत की। इंस्पेक्टर पर्यटन दिनेश कुमार ने बताया कि पर्यटक से बदसुलूकी नहीं हुई थी। गाइड और फोटोग्राफर में कहासुनी हुई थी। (जासं)

बीरभूम में बमबाजी से चार भाजपा कार्यकर्ता जख्मी

जागरण संवाददाता, कोलकाता

▶ **बंगाल में सियासी हिंसा का दौर जारी, भाजपा ने तृणमूल पर आरोप लगाया**

बंगाल के बीरभूम जिले के दूबराजपुर में भीषण बमबाजी से पूरा इलाका दहल उठा। इस घटना में चार भाजपा कार्यकर्ता जख्मी हो गए हैं। वहीं, इस घटना के लिए भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि तृणमूल समर्थकों ने भाजपा पार्टी ऑफिस को केंद्र कर बमबाजी की है, जिससे चार कार्यकर्ता जख्मी हो गए। तृणमूल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।

तृणमूल का कहना है कि एक सभा के दौरान भाजपा समर्थकों ने उन पर हमला बोल दिया। इस दौरान उन्होंने एक तृणमूल नेता के घर में तोड़फोड़ भी की। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर शाम भाजपा द्वारा निकाली गई में एक कार्यकर्ता ने तृणमूल कार्यकर्ता को जय श्रीराम कहते हुए पार्टी में शामिल होने की बात कही। इससे नाराज तृणमूल समर्थक ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। इससे विवाद बढ़ गया और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। आशंका है कि इसी घटना को केंद्र कर मंगलवार देर रात भीषण बमबाजी की गई।

लाभपुर के स्वास्थ्य केंद्र में हुआ भीषण विस्फोट

बीरभूम जिले के लाभपुर में बुधवार देर रात एक बंद पड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुए भीषण विस्फोट से पूरा इलाका दहल उठा। धमाके की तीव्रता अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वहां स्थित दो घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए। वहीं विस्फोट की आवाज से आसपास के इलाके में दहशत व्याप्त हो गया है। बताया जा रहा है कि जिस जगह यह धमाका हुआ है वहां से कुछ ही दूरी पर पुलिस कैंप मौजूद है। इस घटना के बाद भाजपा-तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा ने एनआइए से घटना की जांच कराने की मांग की है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही बीरभूम के मल्लारपुर रेलवे स्टेशन के निकट स्थित मेघदूत क्लब में विस्फोट हुआ था।

इतना आसान नहीं मुख्तार अंसारी का जेल से छूटना

कृष्णानंद हत्याकांड

अविनाश सिंह, गाजीपुर

पूर्वांचल की जरायम की दुनिया में एक-दूसरे की अदावत ने कई लोगों की जान ले ली, लेकिन आज तक किसी भी मामले में आरोपितों को सजा नहीं हो सकी है। कहीं सुबूत नहीं था, तो कई मामले गवाहों के पलट जाने से आरोपित बरी होते आए हैं। बुधवार को बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी ऐसा ही निर्णय आया। मुख्तार अंसारी सहित सभी आरोपित पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए गए। मुख्तार इस मामले में कोर्ट से भले ही बरी हो गए हों, लेकिन वाराणसी के दबंग अवधेश राय और मऊ के ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड अभी भी उनके गले की फांस हैं। ऐसे में फिलहाल मुख्तार अंसारी का जेल बाहर आना इतना आसान नहीं लगता।

वाराणसी के दबंग अवधेश राय की तीन अगस्त, 1991 को लहुराबीर स्थित उनके घर के सामने ही गोली मारकर हत्या दी गई थी। अवधेश पूर्व विधायक अजय राय के बड़े भाई थे। अजय इसमें मुख्य गवाह भी हैं। उनके अनुसार मामले में उनकी गवाही हो चुकी है। इसमें भी साजिशकर्ता के रूप में मुख्तार अंसारी आरोपित हैं। वहीं, मऊ में गाजीपुर तिराहे के पास

मुख्तार अंसारी फाइल फोटो

- **अवधेश राय व मन्ना सिंह हत्याकांड अभी भी गले की फांस**
- **एमपी, एमएलए कोर्ट प्रयागराज में चल रहा है ट्रायल, अवधेश के भाई अजय राय की हो चुकी है गवाही**

29 अगस्त, 2009 को ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह के चर्चित हत्याकांड में भी मुख्तार अंसारी सहित 11 आरोपित बनाए गए थे। इस मामले का भी अभी प्रयागराज के एमपी, एमएलए कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। कानून के जानकारों की मानें तो फिलहाल इन मामलों में आसानी से जमानत मिलने वाली नहीं है।

कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस की बढ़ी चौकसी : कृष्णानंद समेत उनके छह सहयोगियों की हत्या में सीबीआइ कोर्ट के फैसले के बाद जिले में पुलिस चौकसी बरत रही है। जगह-जगह चेकिंग करने के आदेश के साथ ही मुहम्मदाबाद क्षेत्र में आने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है।

हाई कोर्ट जाएगी उप्र सरकार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

▶ **मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की पहल**

भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में विधायक मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपितों को सीबीआइ की विशेष अदालत से बरी किये जाने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सरकार इस फैसले का परीक्षण कराएगी और हाई कोर्ट में अपील करेगी। सीबीआइ की विशेष अदालत से आरोपितों को बरी किये जाने पर जांच एजेंसी से लेकर पैरोकारों की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं।

गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद क्षेत्र के भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और उनके सरकारी अंगरक्षक समेत आधा दर्जन समर्थकों की 29 नवंबर 2005 को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में विधायक मुख्तार अंसारी, सांसद अफजाल अंसारी, जेल में मारे गये माफिया मुन्ना बजरंगी समेत 17-18 लोग आरोपित थे। दिल्ली की विशेष सीबीआइ अदालत के फैसले ने इस पर नई बहस शुरू कर दी। विधायक की हत्या के बाद राजनाथ सिंह ने वाराणसी पहुंचकर अनशन किया था। तब वाराणसी से लखनऊ तक न्याय यात्रा निकाली गई, जिसको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हरी झंडी दिखाई थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस बहुचर्चित हत्याकांड को लेकर भाजपा ने लगातार आंदोलन किया। अब केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार रहने के बावजूद इस मामले के आरोपितों के बरी होने से लचर पैरवी के आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री मामले में गंभीरता दिखा कर यह संदेश भी देना चाहते हैं कि वह पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे और संघर्षरत रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी संबल प्रदान करेंगे। दरअसल, सोशल मीडिया से लेकर चौतरफा यह बात उठ रही है कि जांच एजेंसी ने साक्ष्य जुटाने और पैरवी करने में चूक कर दी। भले ही बहुत से गवाह गवाही से मुकर गये लेकिन, परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी ठीक से प्रस्तुत नहीं किये गए। नहीं तो उनसे सजा दिलाने में मदद मिली होती।

जनमत

मुद्दा

क्या हर व्यक्ति/संस्था की खपत के अनुसार पानी सहेजने के नियम को अनिवार्य किया जाना चाहिए?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **MUDDA** लिखें, स्पेस देकर **YES** या **NO** लिखकर 57272 पर भेजें।

facebook.com/muddajagran

mudda@jagran.com

रोहतक आइआइएम ने जीता बेटियों का भरोसा

ओपी वशिष्ठ, रोहतक

▶ **जाट हिंसा के बाद कम छात्राएं ही ले रही थीं दाखिला**

▶ **2016-17 बैच में थीं सिर्फ नौ छात्राएं, अब संख्या पहुंची 123**

यहां स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम) बेटियों का विश्वास वापस हासिल करने में कामयाब हो रहा है। इसका उदाहरण दो दिन पहले शुरू हुए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (पीजीपी) के दसवें बैच में देखने को मिला। इस बैच में कुल 245 विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या 123 हैं, जो 50 फीसद बनता है। वर्ष 2016-17 में सिर्फ नौ छात्राएं रह गई थीं।

वर्ष 2016 में जाट आरक्षण दंगों के बाद 2016-17 के बैच में यहां कुल डेढ़ सौ विद्यार्थी थे, जिसमें छात्राओं की संख्या नौ थी। इसका कारण रोहतक में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा को भी माता है क्योंकि उस वक्त महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कैंपस में ही आइआइएम चल रहा था। वर्ष 2017-18 के बैच में भी 250 विद्यार्थियों में 23 छात्राओं ने ही यहां दाखिला लिया, लेकिन बाद में यह सुनारिया गांव स्थित नए कैंपस में शिफ्ट हो गया। पिछले दो बैच से छात्राओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई और छात्र-छात्रा अनुपात 50 फीसद हो गया।

2016 से 2020 के बैच का लिंगानुपात

वर्ष	कुल विद्यार्थी	छात्राएं
2016-17	150	09
2017-18	250	23
2018-19	241	121
2019-20	245	123

विद्यार्थियों को सौ फीसद प्लेसमेंट मिलना बड़ी उपलब्धि

इन चार प्रयास से जीता बेटियों का विश्वास

1. प्राध्यापक व पूर्व छात्राओं की कमेटियों ने देश के विभिन्न राज्यों में 4500 विद्यार्थियों से फोन पर संपर्क किया। उनको आइआइएम रोहतक में शिक्षा सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव का भरोसा दिलाया गया।

2. दाखिल लेने के इच्छुक करीब 200 विद्यार्थी व उनके अभिभावकों को संस्थान में विजिट करने के लिए आमंत्रित किया गया। देश के अन्य राज्यों से अभिभावकों को थ्री-एसी ट्रेन का किराया दिया। 100 से अधिक अभिभावक अपने बच्चों के साथ संस्थान का विजिट करने पहुंचे।

3. दिल्ली, मुंबई व चंडीगढ़ में संस्थान की तरफ से आउटरीच प्रोग्राम किए गए, जिसमें आइआइएम के निदेशक प्रो. धीरज शर्मा खुद पहुंचे।

4. संस्थान में ही विद्यार्थियों को एजुकेशन लोन दिलाया गया। करीब 14 करोड़ रुपये के एजुकेशन लोन कैंपस में ही विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए।

> आइआइएम रोहतक एनसीआर में एकमात्र संस्थान है। संस्थान में सौ फीसद प्लेसमेंट, जिसमें नौवें बैच के प्लेसमेंट में औसतन 12 लाख रुपये का पैकेज विद्यार्थियों को मिला। अधिकतर पैकेज 31 लाख रहा। 241 विद्यार्थियों को सौ फीसद प्लेसमेंट मिलना बड़ी उपलब्धि है। संस्थान की उपलब्धियों को देखते हुए देश के 10 आइआइएम में छात्राओं ने रोहतक को पहला विकल्प चुना है। यह संस्थान लिए गर्व की बात है। 50 फीसद छात्राओं की संख्या बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ मुहिम को सार्थक साबित कर रही है। **-प्रो. धीरज शर्मा, निदेशक, आइआइएम, रोहतक**

शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन में तोड़फोड़, 40 पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : जम्मू से वाया मुजफ्फरनगर-मेरठ दिल्ली जा रही शालीमार एक्सप्रेस में गुरुवार को कुछ लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि दैनिक यात्रियों ने आरक्षित डिब्बों में घुसकर सीट कब्जाने के लिए दबंगई दिखाई। विरोध करने पर तोड़फोड़ की। इससे ट्रेन में सवार अन्य यात्री दहशत में आ गए। सुबह के करीब साढ़े नौ बजे नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका गया। इस मामले में सीटीटीआइ ने एक व्यक्ति को नामजद करते हुए चालीस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जीआरपी ने जीरो में दर्ज एफआइआर मेरठ को स्थानांतरित की है।

सीटीआइ अजय बिरला ने बताया कि मुरादनगर से असद खान नाम का व्यक्ति गाजियाबाद के लिए ट्रेन में सवार हुआ। दो-तीन अन्य लोग भी उसके साथ एसी कोच में सवार हुए। टिकट की जांच करने पर असद खान ने सेकंड क्लास का एमएसटी दिखाया। इस पर सीटीआइ ने सेकंड क्लास में जाने के लिए कहा। सीटीआइ के मुताबिक, खुद को वकील बताते हुए असद खान ने जमकर अभद्रता की और कोच-बी से कोच-ए में चला गया। यहां पर जब उसका चालान करने की बात सीटीआइ ने कही तो वह उनसे मारपीट पर उतारू हो गया। आरोप है कि असद ने नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर अपने साथियों को बुला लिया। उन लोगों ने ट्रेन के रवाना होने पर चेन खींच कर रोक लिया।

भाजपा सांसद के आदेश पर पुलिस तलाश रही बकरी

मृगेंद्र पाण्डेय, रायपुर

▶ **छत्तीसगढ़ में आदिवासी युवक की बकरी को लेकर पुलिस परेशान**

▶ **भाजपा सांसद संतोष पांडेय थाने में फोन कर लेते हैं प्रगति की जानकारी**

उत्तर प्रदेश में तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार में कद्दावर मंत्री रहे आजम खान की चोरी गई भैंस की तलाश में पुलिस के हलकान होने का मामला सुर्खियों में आया था। अब छत्तीसगढ़ पुलिस एक बकरी की तलाश में हलकान है। आदिवासी युवक की इस बकरी के लिए भाजपा सांसद संतोष पांडेय रोज थाने में फोन कर प्रगति की जानकारी ले रहे हैं।

दरअसल, राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र के इंदरवानी गांव निवासी आदिवासी युवक कुशल धनकर की बकरी चोरी हो गई। उसने पहले थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। बात नहीं बनी तो पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। ऐसा करने में एक महीने का समय बीत गया, लेकिन बकरी नहीं मिली। आखिर उसने राजनांदगांव से भाजपा सांसद संतोष पांडेय को फोन कर बकरी की तलाश कराने की फरियाद की। सांसद भी क्या करते।

युवक रोज सुबह पांच बजे उनको फोन करता और बकरी नहीं मिलने पर तकादा करता है। सांसद ने थाने में फोन करके थानेदार को बकरी चोरी की रिपोर्ट लिखने और खोजने का आदेश दिया। थानेदार की नींद उड़ी हुई है। युवक रोज सांसद को फोन करता है और वह थानेदार को। बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान संतोष पांडेय की बकरी के मालिक कुशल धनकर से मुलाकात हुई थी। पांडेय ने उनको अपना मोबाइल नंबर दे दिया। इस बीच लोकसभा चुनाव का परिणाम आया और संतोष पांडेय सांसद चुन लिए गए। संसद में जब संतोष पांडेय को शपथ लेते कुशल धनकर ने देखा तो उसकी उम्मीद जगी।

आठ हजार की है बकरी

गुम हुई बकरी की कीमत आठ हजार रुपये बताई जा रही है। इसको खोजने के लिए थाने का स्टाफ लगा है। युवक के गांव के आसपास एक एसआइ और दो सिपाही ने पांच से आठ दिन तक पूछताछ की, लेकिन बकरी का पता नहीं चला। सांसद संतोष पांडेय ने बताया कि अब पीड़ित युवक बकरी नहीं मिलने पर कुछ मुआवजे की मांग कर रहा है। पुलिस को बकरी की तलाश जारी रखने को कहा गया है।

तलाशी राह

आइआइटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने बनाया दस किलो कीटनाशक ले जाने वाला ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा यंत्र रिमोट से भी चलेगा

हेलीकॉप्टर ड्रोन करेगा कीटनाशक का छिड़काव

विक्सन सिकरोड़िया, कानपुर

फसलों को कीट और रोगों से बचाने के लिए किसान अब न सिर्फ ड्रोन के जरिये निगरानी कर सकेंगे, बल्कि रोग और कीट प्रभावित हिस्से पर कीटनाशक का छिड़काव भी ड्रोन की मदद से ही कर सकेंगे। प्रेसीजर एग्रीकल्चर के लिए आइआइटी के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग ने एग्रो हेलीकॉप्टर ड्रोन बनाया है, जिसमें मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे हैं। इनके जरिये फसलों के स्वास्थ्य का जायजा लेकर रोग, कीट व फसलों के उत्पादन का पता लगाया जा सकता है। यह ड्रोन दस किलो कीटनाशक लेकर उड़ सकता है।

आइआइटी के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग ने ड्रोन पर रंग प्रतिबिंब देख सकने वाला हाईटेक कैमरा लगाकर एग्रीकल्चर सर्वे का स्वरूप बदल दिया है। यह दस से 15 फीट ऊपर से खेतों की फोटोग्राफी करके उसकी कंपोजिट (कई पिक्चर को जोड़कर बड़ी तस्वीर) इमेज बनाता है। इससे यह पता चलता है कि खेत के किस हिस्से में कीट या रोग का प्रकोप है और कौन सा भाग स्वस्थ है। इसमें पांच लीटर का पेट्रोल टैंक लगाया गया है। इस ईंधन से यह दो घंटे उड़कर इमेज बनाने के साथ कीटनाशक का छिड़काव कर सकता है। पहले खेतों की ऐसी इमेज बनाने का काम सेटेलाइट से ही संभव था और इस्तेमाल करने में कई चुनौतियां भी आती थीं, जबकि छह गुणा चार गुणा तीन फुट के बॉक्स में आने वाले ड्रोन ने कृषि तकनीक के क्षेत्र में स्मार्ट वर्क करने के कई नए आयाम खोल दिए हैं।

आइआइटी कानपुर के वैज्ञानिकों की सफलता। फाइल

4.4 किलोवाट का इंजन

इसमें 4.4 किलोवाट का इंजन लगाया गया है। मोटर के जरिये ड्रोन में लगे ब्लेड उसे हवा में संतुलित रखते हैं। एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अभिषेक ने बताया कि इस तकनीक से फसल नुकसान कम करके किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, इससे यह केवल उस जगह ही छिड़काव करेगा जहां कीट व रोग होंगे। यह रंग व आकार से रोग व कीट की पहचान करेगा। वैसे जरूरत पड़ने पर पूरे खेत में भी इसके जरिये छिड़काव किया जा सकता है। यह रिमोट व कंप्यूटर दोनों से उड़ाया जा सकता है।

मॉडल से आइआइटी में सफल परीक्षण : आइआइटी कानपुर में एग्रो हेलीकॉप्टर ड्रोन के मॉडल से परीक्षण सफल रहा। अब सरकार की मांग व कृषि विभाग की जरूरत पर इस तकनीक पर आगे काम किया जाएगा।

सांसद डॉ. जितेंद्र सिंह ने नन्ही अदीबा को लिया गोद

राज्य ब्यूरो, जम्मू

▶ **किश्तवाड़ सड़क हादसे में अदीबा ने खोए थे माता-पिता और भाई**

प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री एवं जम्मू-कश्मीर स्थित ऊधमपुर-डोडा के सांसद डॉ. जितेंद्र सिंह ने तीन साल की अदीबा को गोद ले लिया है। सांसद ने बच्ची के पालन-पोषण और शिक्षा के खर्चा उठाने की जिम्मेदारी उठाई है। अदीबा ने एक जुलाई को किश्तवाड़ के केशवान इलाके में हुए सड़क हादसे में अपने मां-बाप और भाई को खो दिया था। इस हादसे में अदीबा के परिजनों समेत 35 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 16 लोग घायल हुए थे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बच्ची को गोद लेने के फैसले के संबंध में जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर संजीव वर्मा को सूचित कर दिया है। डॉ. जितेंद्र अदीबा के इलाज के साथ-साथ उसकी शिक्षा का खर्चा भी उठाएंगे। राज्य सरकार भी अदीबा को 15 साल के होने तक प्रति माह 1200 रुपये आर्थिक सहायता देगी। सरकार ने यह फैसला राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निर्देश पर लिया है। इसके अलावा किश्तवाड़ के अतिरिक्त जिलाधीश को अदीबा का संरक्षक बनाया गया है।

घायलों के उपचार पर दिया जा रहा ध्यान

डॉ. जितेंद्र सिंह के निर्देशों पर उनका स्टाफ नियमित तौर पर जम्मू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचाराधीन घायलों का हाल चाल ले रहा है। सांसद ने अस्पताल प्रशासन से भी स्पष्ट किया है कि अगर इलाज के लिए किसी मरीज को एम्स और पीजीआइ भेजने की जरूरत है तो इसका भी बंदोबस्त किया जाएगा।

रामपुर में आजम खां के समधी का होटल सील

जागरण संवाददाता, रामपुर : रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने सांसद आजम खां के समधी रिजवान मुहम्मद खां का होटल प्लाजा सील कर दिया है। आरोप है कि उन्होंने नक्शे के विपरीत होटल का निर्माण कराया था।

आरडीए के सचिव बैजनाथ गुरुवार को पुलिस फोर्स के साथ डायमंड रोड स्थित होटल प्लाजा पहुंचे और होटल कर्मियों को बाहर निकाला। इसके बाद होटल को सील करने की कार्रवाई की। प्राधिकरण सचिव का कहना है कि होटल का निर्माण नक्शे के विपरीत कराया गया है। इस संबंध में एक शिकायत मिली थी। जांच के बाद शिकायत सही मिली थी। इस पर होटल स्वामी को नोटिस जारी किया गया। उन्होंने कंपाउंड कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन होटल का अधिकतर हिस्सा ऐसा है, जिसे कंपाउंड नहीं किया जा सकता। इस कारण सील कर दिया गया है। होटल 1401 वर्ग मीटर में बना है। गौरतलब है कि इस होटल का निर्माण सपा शासनकाल में हुआ था और इसका उद्घाटन भी प्रदेश के तत्कालीन नगर विकास मंत्री आजम खां ने किया था।

स्टार्ट-अप व नवजात इकाइयों को मिलेगा प्रोत्साहन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों के विकास और अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी का दायरा बढ़ाने के लिए उनको मिलने वाले प्रोत्साहन की नीति में सरकार बदलाव कर सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 से मिल रहे संकेतों को आधार माना जाए तो इस आशय की घोषणा सरकार आम बजट में कर सकती है। इसके तहत सरकार छोटी इकाइयों को प्रोत्साहन की मौजूदा नीति के बजाय नई प्रारंभिक इकाइयों को बढ़ावा देने की नीति अपना सकती है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में सरकार ने इस बदलाव के पीछे की अपनी मंशा को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। दरअसल, सरकार का मानना है कि अवधि आधारित प्रोत्साहनों की मौजूदा नीति छोटी इकाइयों को छोटी बने रहने के लिए बाध्य करती है। इससे उनमें कभी बड़ा बनने की इच्छा पैदा नहीं होती। इसमें बिलकुल नई इकाइयों के बजाय 100 से कम कामगारों वाली पुरानी और घिसीपिटी लकीर पर चलने वाली बौनी इकाइयां पनप रही हैं, जो हमेशा वैसी ही रहती हैं और कभी बड़ा आकार ग्रहण नहीं कर पातीं। इन इकाइयों का रोजगार में महज 14 प्रतिशत तथा उत्पादकता में महज 8 प्रतिशत योगदान है। जबकि संख्या में मात्र 15 प्रतिशत होने के बावजूद बड़ी इकाइयां (100 से ज्यादा कर्मचारियों वाली) का रोजगार में योगदान 75 प्रतिशत और उत्पादकता में 90 प्रतिशत है।

इसलिए इस नीति के स्थान पर ऐसी नीति अपनाए जाने की आवश्यकता है जो पुरानी छोटी इकाइयों को पोषित करने के बजाय नई छोटी इकाइयां स्थापित करने और उन्हें बड़ा बनाने में सहायक हो।

मौजूदा नीति की खामियां

आयु या अवधि आधारित प्रोत्साहन की वर्तमान नीति की खामियां गिनाते हुए सर्वेक्षण कहता है कि इसमें कोई उद्यमी नई इकाई शुरू कर दस वर्षों तक सरकार से मिलने वाले लाभों का उपयोग करता है। परंतु दस वर्ष बाद जब लाभ समाप्त हो जाते हैं तो उस इकाई को बंद कर पुनः लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरी जगह नई इकाई शुरू कर देता है। नई नीति में इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए 'आधार' के उपयोग की मंशा जताई गई है। इसके तहत पुरानी इकाई बंद कर नई शुरू करने की कोशिश करने वाले उद्यमी का आधार अधिकारियों को इसकी सूचना देगा और उसे पुरानी इकाई को चलाने तथा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बाध्य करेगा। यही नहीं, एमएसएमई क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए सरकार का प्राथमिकता क्षेत्र को कर्ज देने (प्रायारिटी सेक्टर लेंडिंग यानी पीएसएल) की वर्तमान नीति में भी संशोधन का इरादा है। सरकार का मानना है कि मौजूदा नीति में बैंकों को सूक्ष्म, लघु व मध्यम इकाइयों को कर्ज देने के कुछ लक्ष्य सौंपे जाते हैं। इससे भी इकाइयां छोटी बने रहने में ही फायदा समझती हैं। इसलिए सरकार की मंशा इसमें संशोधन कर पीएसएल को ऐसा स्वरूप प्रदान करने की है ताकि बैंक रोजगार की दृष्टि से लचीली स्टार्ट-अप एवं नवजात इकाइयों को कर्ज देने को वरीयता दें।

सनसेट क्लॉज : इसके अलावा एमएसएमई क्षेत्र में ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रत्येक प्रोत्साहन के साथ पांच या सात वर्ष का सनसेट क्लॉज जोड़ने के पक्ष में है। ताकि उक्त अवधि के बाद इकाई अपने बल पर आगे बढ़े।

एमएसएमई क्षेत्र के अलावा अतिरिक्त सरकार का फोकस पर्यटन जैसे उन सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर होगा जो होटल, खानपान, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, मनोरंजन आदि अन्य क्षेत्रों को भी लाभान्वित करने केसाथ रोजगार सृजन में योगदान करते हैं।

सरकार को बढ़ानी होगी रिटायरमेंट की उम्र सीमा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : भारत की विशालकाय युवा आबादी को अभी तक एक बड़ी शक्ति के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। देश की आबादी में वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से ज्यादा आयुवर्ग) का हिस्सा अभी 8.6 फीसद है जो वर्ष 2041 तक बढ़ कर 15.9 फीसद हो जाएगा। जाहिर है कि इसके साथ ही रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति की आयु में बढ़ोतरी जैसे उपाय करने पड़ेंगे।

युवा आबादी का फायदा देश की अर्थव्यवस्था को कितना हुआ, इसका तो कोई अध्ययन नहीं हआ है। लेकिन नीति नियामकों को बुजुर्ग होती आबादी से निबटने की रणनीति बनाने में अभी से जुट जाना होगा। गुरुवार को संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के मुताबिक बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्यों में युवाओं की संख्या अच्छी रहेगी। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ेगी।

वर्ष 2041 तक आबादी की स्थिति

- सालाना जनसंख्या वृद्धि दर 1.77 फीसद से घटकर रह जाएगी 0.46 फीसद
- कुल आबादी 121 करोड़ से बढ़कर 151 करोड़ हो जाएगी
- 60 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग की संख्या हो जाएगी 15.9 फीसद
- 2021-31 के दौरान 97 लाख सालाना तो 2031-41 में 42 लाख सालाना देने होंगे रोजगार

2018-19

के मुताबिक बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्यों में युवाओं की संख्या अच्छी रहेगी

- केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ेगी
- नीति नियामकों को रणनीति बनाने में अभी से जुट जाना होगा

भारत में जिस तरह पुरुषों व महिलाओं की औसत आयु बढ़ रही है उसे देखते हुए दूसरे देशों की तरफ यहां भी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ानी होगी। यह पेंशन सिस्टम को बनाए रखने और कुल श्रम में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी के लिए भी जरूरी होगा। सरकार को इसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि लोग भी तैयार रहें । लेकिन जनसंख्या में इस बदलाव के हिसाब से देश की शिक्षा व स्वास्थ्य नीति में भी बदलाव करना होगा।आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ अध्ययनों के आधार पर कहा गया है कि वर्ष 2001-11 के दौरान जनसंख्या की विकास दर 1.77 फीसद रही थी, जो वर्ष 2031-41 तक घटकर 0.46 फीसद रह जाएगी। इससे देश की कुल आबादी में 19 वर्ष तक के युवाओं की हिस्सेदारी घटेगी और वरिष्ठ नागरिकों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में देश के भीतर और ज्यादा श्रम पलायन देखना पड़ सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि भारत की स्थिति अगले कुछ दशकों तक यूरोपीय देशों जैसी हो जाएगी। काम करने वाले आयुवर्ग (20 से 59 वर्ष) की संख्या कुल आबादी में वर्ष 2011 में 50.5 फीसद थी, जो वर्ष 2041 में 58.9 फीसद होगी।

इतनी बड़ी कामगार आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना हर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। वर्ष 2021-31 के दौरान सरकार को हर वर्ष औसतन 97 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित करने होंगे।

न्यायिक सुधार पर रहेगा अगले पांच साल में विशेष जोर

करारों के लागू होने और विवादों के निपटारे की क्षमता से जुड़ी है आर्थिक सफलता

माला दीक्षित • नई दिल्ली

जरूरत

- न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर हासिल किया जा सकता है लक्ष्य
- अदालतों में 3.5 करोड़ मुकदमों का ढेर लगा हुआ है
- यह आंकड़ा डरावना जरूर है, लेकिन इससे निपटा जा सकता है

अदालतों में लगा 3.5 करोड़ मुकदमों का ढेर भले ही अजेय और डरावना लगता हो, लेकिन इससे निपटना असंभव नहीं है। जीरो पेंडेंसी यानी एक भी मामला लंबित नहीं रहने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए न्यायपालिका की मौजूदा कार्यक्षमता बढ़ाने और न्यायाधीशों के खाली पड़े पदों को भरने के अलावा अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने होंगे। आर्थिक सर्वेक्षण में इसकी जरूरत बताते हुए इसका पूरा रोडमैप पेश किया गया है।

गुरुवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लगे मुकदमों के ढेर से निपटने के लिए पूरी स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हुए हल पेश किया गया है। शुक्रवार को पेश होने वाले बजट मे सरकार सर्वेक्षण की सिफारिशों के आधार पर न्यायिक सुधार का खाका भी पेश कर सकती है। आर्थिक सफलता और समृद्धि कांट्रैक्ट (संविदा) यानी करारों के लागू होने और विवादों के निपटारे की क्षमता से जुड़ी हुई है। भारत में व्यवसाय को आसान बनाने और उच्चतर जीडीपी हासिल करने में सबसे बड़ी बाधा कांट्रैक्ट लागू होने और विवादों के निस्तारण में देरी है। हालांकि दिवालिया कानून और जीएसटी से भारत में व्यवसाय की स्थिति बहुत सुगम हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण में न्यायिक सुधार पर जोर देते हुए पांच साल में मुकदमों की 100 फीसद निस्तारण दर हासिल करने और पुराने मुकदमों का ढेर खत्म करने के लिए कार्यक्षमता बढ़ाने और अतिरिक्त जजों की जरूरत पर बल दिया गया है। जिला एवं सत्र न्यायालयों में दिसंबर, 2018 तक कुल 3.04 करोड़ मुकदमे लंबित थे। यहां जजों के कुल 22,750 पद मंजूर हैं जिनमें से मात्र 17,819 (79 फीसद) काम कर रहे हैं। बाकी पद खाली हैं। एक जज वर्षभर में औसतन 746 मुकदमे निपटाता है। ऐसे में 100 फीसद निस्तारण दर प्राप्त करने के लिए 2,279 अतिरिक्त जजों की और जरूरत है। लेकिन यह संख्या जिला अदालतों में जजों के मंजूर पदों के अंदर ही है। इसके अलावा पांच साल मे सभी लंबित मुकदमों खत्म करने के लिए 8,152 अतिरिक्त जजों की जरूरत होगी। इसी तरह उच्च न्यायालयों में पेंडेंसी खत्म करने के लिए 361 अतिरिक्त जजों की जरूरत है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में पांच साल में सभी लंबित मुकदमे खत्म करने के लिए छह और न्यायाधीशों की जरूरत होगी। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया है। आर्थिक सर्वेक्षण उनकी बातों का समर्थन करता दिखता है। पूर्वी राज्यों बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में मुकदमों की निस्तारण दर बहुत खराब है ऐसे में अतिरिक्त जजों की नियुक्ति में इन राज्यो को प्राथमिकता देने की जरूरत है।

सर्वे के मुताबिक निचली अदालतों की कार्यक्षमता में 24.5 फीसद की बढ़ोतरी करने से जजों की संपूर्ण स्वीकृति संख्या के साथ पांच वर्षो में लंबित मामलों को समाप्त किया जा सकता है। वर्तमान कार्यबल के अनुसार कार्यक्षमता में 58 फीसद की बढ़ोतरी करनी होगी। संपूर्ण मंजूर संख्या के साथ हाईकोर्ट में लंबित मामलों को खत्म करने के लिए कार्य क्षमता में सिर्फ 4.3 फीसद की बढ़ोतरी की जरूरत है। लेकिन बहुत से पद खाली पड़े हैं ऐसे में वर्तमान कार्यबल के मुताबिक कार्य क्षमता में 68 फीसद की वृद्धि चाहिए। इसके अलावा न्यायालय और न्यायाधिकरण सेवाओं की स्थापना और प्रौद्योगिकी के उपयोग से भी इसे बेहतर किया जा सकता है।

परंपरा का निर्वहन : बजट की पूर्व संध्या पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर का यह फोटो सत्र वर्षों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। इसमें बजट से जुड़े वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हैं। फोटो खिंचवाने की यह परंपरा उस वक्त से चली आ रही है, जब देश में फोटो भेजे जाने के आज जैसे संचार साधन नहीं थे। ऐसे में बजट के लिए फोटो एक दिन पहले ही देश के कोने-कोने से प्रकाशित अखबारों तक रेल अथवा वायु मार्ग से भेजे जाते थे। यह परंपरा इसलिए प्रारंभ की गई ताकि अगले दिन जब वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करें तो खबर सचित्र प्रकाशित हो सके। संचार के तीव्रतम साधनों के बावजूद आज भी परंपरा जारी है। • संजय

सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर निराश है : चिदंबरम

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस ने गुरुवार को संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर निराश लग रही है। वहीं, माकपा ने कहा कि सर्वे में दावे तो बड़े-बड़े किए गए हैं, लेकिन बुनियादी तथ्यों का अभाव है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने एक बयान में कहा, 'इस आर्थिक समीक्षा में क्षेत्रावार विकास को लेकर कोई अनुमान नहीं है। सिर्फ एक स्पष्ट कथन है कि 2019-20 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि सात फीसद रहने की उम्मीद है।' उन्होंने दावा किया कि आर्थिक समीक्षा से स्पष्ट है कि धीमी विकास दर, राजस्व में गिरावट, वित्तीय घाटे के लक्ष्य से कोई समझौता किए बिना संसाधन हासिल करने और चालू खाते पर तेल के कीमतों के असर की बात करें तो इनमें कुछ भी सकारात्मक और उत्साहजनक नहीं है। चिदंबरम ने कहा, 'ऐसा लगता है कि आर्थिक समीक्षा के जरिए सरकार यही बोल रही है कि वह अर्थव्यवस्था को लेकर निराश है।' वहीं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि आर्थिक सर्वे में बुनियादी तथ्यों की कमी है।

छात्रों की घट रही संख्या नहीं खुलेंगे नए स्कूल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या को देख आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार को नए स्कूल न खोलने की सलाह दी गई है। इसकी जगह पहले से चल रहे स्कूलों के विलय का भी सुझाव दिया गया है। यह विलय एक से तीन किमी के दायरे में मौजूद स्कूलों के बीच ही होगा। सर्वे में यह सुझाव उन नतीजों को देखने के बाद दिया गया है, जिसमें दिल्ली को छोड़कर देश के सभी राज्यों में ऐसे स्कूलों की संख्या बढ़ी है, जिसमें छात्रों की संख्या 50 से भी कम है।

आर्थिक सर्वेक्षण-2018-19 में जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और कनाडा जैसे देशों का उदाहरण भी दिया गया है, जहां प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या में ऐसी ही गिरावट देखने के बाद स्कूलों के विलय या बंद करने जैसे कदम उठाए गए हैं। सर्वेक्षण में यह भी साफ किया गया है कि नए स्कूलों को न खोलने का मतलब यह कतई नहीं है, कि प्राथमिक शिक्षा के बजट में कमी की जाए। बल्कि इस राशि का इस्तेमाल स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और क्षमता को बढ़ाने पर दिया जाए। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक जनसंख्या के पुर्वानुमान के आधार पर प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या (पांच से 14 वर्ष के बीच) में यह कमी 2041 तक बनी रहेगी। इसके तहत देश में 2021 से 2041 के बीच स्कूली बच्चों की संख्या में 18.4 फीसद तक की कमी होगी। फिलहाल जिन राज्यों के प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की संख्या में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज हुई है उनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं।

गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद

आर्थिक सर्वेक्षण में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के सरकार के प्रयासों को सराहा भी गया है। 2014 से 2018 के बीच शैक्षिक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि पहले के मुकाबले में इनमें काफी सुधार देखा गया है। कक्षा तीन के विद्यार्थियों के लिए मौलिक साक्षरता और अंकीय ज्ञान दोनों में सुधार हुआ है। हालांकि इनमें अभी भी एक चौथाई बच्चे ही पढ़ने की क्षमता जैसे कार्य में दक्ष होते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आठवीं पास करने वाले प्रत्येक चार में एक छात्र को मौलिक वाचन कौशल (कम से कम कक्षा दो के स्तर पर पढ़ने की योग्यता) भी नहीं है।

कृषि क्षेत्र की चुनौतियां गिनाईं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहले आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां गिनाईं गई हैं। कृषि क्षेत्र में पानी के अंधाधुंध दोहन पर चिंता जताते हुए इसके किफायती उपयोग पर जोर दिया गया है। सर्वेक्षण में 'भूमि की उत्पादकता' से 'सिंचाई जल उत्पादकता' को प्राथमिकता देने, जल के उचित उपयोग के साथ फसलों के विविधीकरण और जल को लेकर किसानों को संवेदनशील बनाने की जरूरत जैसे सुझाव दिए गए हैं।

संसद में शुक्रवार को आर्थिक समीक्षा पेश करते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भूजल स्तर में लगातार गिरावट कृषि क्षेत्र के लिए खतरनाक है। भूजल का 89 फीसद सिंचाई के उपयोग में आता है। देश में उपलब्ध जल का 60 फीसद से अधिक का उपयोग धान व गन्ने की फसल में सिंचाई के लिए किया जाता है। इसके चलते बाकी फसलों में कम पानी मिल पाता है। वर्ष 2050 तक दुनिया में भारत पानी की कमी वाला सबसे गर्म क्षेत्र हो जाएगा, जिसे लेकर सर्वेक्षण रिपोर्ट में गंभीर चिंता जताई गई है। देश के लघु व सीमांत किसानों के लिए पानी के किफायती उपयोग पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है।

चिंता

- पानी के किफायती उपयोग वाली कृषि नीति की जरूरत : सर्वेक्षण
- छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने वाली बनाई जाएं योजनाएं

आर्थिक सर्वेक्षण में खेतों के टुकड़े होने और जल संसाधनों की कमी से संकट गंभीर हो रहा है। छोटी जोत के इन किसानों की उत्पादकता को बढ़ाना बड़ी चुनौती है, जिसके लिए उपयुक्त नीति की जरूरत है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि कृषि व उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों की सकल पूंजी में हिस्सेदारी घटकर 14.4 फीसद रह गई है। कृषि, वानिकी व मत्स्य क्षेत्र की विकास दर 2.9 फीसद रहने का अनुमान लगाया गया है। कृषि के साथ पशुपालन, बागवानी, वानिकी, मत्स्यपालन और अन्य क्षेत्रों की भूमिका अहम होती है। शुक्रवार को पेश होने वाले बजट में कृषि अलावा इन क्षेत्रों पर विशेष फोकस रह सकता है। छोटे किसानों को बाजार की सहूलियत देने के लिए बुनियादी सुविधाएं बढ़ाए जाने पर जोर दिया गया है। सीतारमण के बजट में किसानों तक मंडी सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। फसलों के भंडारण और मूल्य के बारे में जानकारी दिलाना भी अहम होगा। किसानों तक जानकारी पहुंचाने वाली प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए विस्तार सेवा की बहाली जरूरी है।

सर्वेक्षण में कृषि अनुसंधान व शिक्षा क्षेत्र में हो रहे अल्प व्यय पर चिंता बताई गई है, जो वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.87 फीसद था। यह अब घटकर 0.37 फीसद रह गया है। इस क्षेत्र में निवेश नहीं हुआ तो कृषि क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन की भारी कमी हो जाएगी।

सर्वेक्षण में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की चुनौती से निपटने के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन पर जोर दिया गया है। ज्यादातर ग्रामीण गरीबों पशुपालन से ही होता है। मत्स्यपालन से देश में 1.45 करोड़ मछुआरों की रोजी-रोटी चल रही है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 6.5 फीसद है। सर्वेक्षण के मुताबिक बजट में किसानों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के उपायों पर जोर होगा।

लोक कल्याण के लिए डाटा के इस्तेमाल पर होगा जोर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अगले पांच-छह वर्षों में पांच लाख करोड़ डॉलर (वर्तमान भाव कर करीब 375 लाख करोड़ रुपये) की अर्थव्यवस्था बनने की राह में नागरिकों के निजी डाटा यानी सूचनाओं और जानकारियों की भूमिका अहम होने वाली है। समाज के कल्याण के लिए नीति निर्धारण में सरकार के लिए लोगों का यह डाटा बेहद महत्वपूर्ण होगा। यही वजह है कि आर्थिक सर्वे 2018-19 में सरकार में विभिन्न स्तरों पर बिखरे इस डाटा के संयोजन पर जोर दिया गया है। सर्वे का मानना है कि संविधान की मूल भावना के मुताबिक ये डाटा 'लोगों के, लोगों द्वारा और लोगों के लिए' होना चाहिए।

आधुनिक अर्थव्यवस्था में डाटा के महत्व को समझते हुए पहली बार आर्थिक सर्वे में इसे एक अलग अध्याय के रूप में शामिल किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को संसद में आर्थिक सर्वे 2018-19 पेश किया। सर्वे के पहले खंड में शामिल इस अध्याय में कहा गया है कि सामाजिक स्तर पर आंकड़ों का उपयोग अब पहले की तुलना में अधिक हो रहा है। सर्वे कहता है, 'जहां निजी क्षेत्र लाभकारी आंकड़ों से लाभ लेते हुए अच्छा कार्य कर रहा है, वहीं सरकार को भी कुछ ऐसे सामाजिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप की जरूरत है, जहां आंकड़ों के संदर्भ में निजी क्षेत्र की ओर से किया जाने वाला निवेश पर्याप्त नहीं है।'

सर्वे में इस दिशा में सरकार से आगे बढ़ने का आह्वान किया है। सरकार के पास पहले से ही नागरिकों के प्रशासनिक, सर्वेक्षण, संस्थागत और संव्यवहार संबंधी आंकड़े उपलब्ध हैं। लेकिन चुनौती यह है कि ये आंकड़े अलग-अलग निकायों में पड़े हैं। मसलन किसी नागरिक की ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सूचना एक विभाग के पास, तो उसकी संपत्तियों के पंजीकरण का डाटा दूसरे विभाग के पास है। सर्वे ने सरकार को इन बिखरे डाटा समूहों को संयोजित कर इसके इस्तेमाल का सुझाव दिया है। सर्वे में माना गया है कि इससे नागरिकों के जीवन-सुविधा में सुधार करने और कल्याण स्कीमों के लक्ष्य निर्धारण में सुधार करने में मदद मिलेगी।

सर्वे में कहा गया है कि गोपनीय सूचनाओं का संरक्षण और आदान-प्रदान करने के लिए पहले ही उन्नत प्रौद्योगिकी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। उसके बाद ही सरकारें आंकड़ों की निजता के कानूनी ढांचे के अंतर्गत लोक कल्याणकारी साधन के रूप में उनका सृजन कर सकती हैं।

सरकार चाहे तो निजी क्षेत्र कर सकता है चुनिंदा डाटा का इस्तेमाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : लोगों के डाटा की सुरक्षा और निजता की बहस के बीच सरकार के लिए इस डाटा से राजस्व जुटाने की संभावनाएं भी निकल रही हैं। आर्थिक सर्वेक्षण ने सुझाव दिया है कि सरकार निजी क्षेत्र को कुछ चुनिंदा डाटा के इस्तेमाल की इजाजत देकर उसके वाणिज्यिक उपयोग का रास्ता तलाश सकती है।

संसद में गुरुवार को पेश साल 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण में इसे किस तरह से आगे बढ़ाया जाए इसका भी रास्ता बताया गया है। चूंकि सर्वेक्षण डाटा को सार्वजनिक संपत्ति के तौर देख रहा है इसलिए वह उसके वाणिज्यिक इस्तेमाल के हक में भी है। इसके पीछे डाटा के रखरखाव पर आने वाली लागत को एक बड़ी वजह बताया गया है। निजी कंपनियों को इसके चुनिंदा इस्तेमाल की इजाजत देकर डाटा के रखरखाव की लागत की भरपाई की जा सकती है। इसमें यह भी स्वीकार किया गया है कि निजी क्षेत्र डाटा के इस्तेमाल से काफी लाभ कमा सकता है इसलिए उनसे कुछ कमाई करने में कोई हर्ज नहीं है। डाटा के निजीकरण के मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए सर्वेक्षण में विद्यार्थियों के डाटा का निजीकरण करने का उदाहरण दिया गया है।

डाटा की सुरक्षा को लेकर भी सर्वे में चिंता जताई गई है। इसमें नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है कि उन्हें यह जानकारी हो सके कि उनसे संबंधित सूचनाएं किसने और क्यों देखी। सामाजिक विकास के लिए सृजित होने वाले डाटा के रियल टाइम अपडेशन पर भी जोर दिया गया है। डाटा के महत्व को समझाते हुए सर्वे कहता है कि इस क्षेत्र में निजी कंपनियों का निवेश स्तर हमेशा से अधिक रहा है। फोर्ब्स सर्वे 2017 के हवाले से आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि 53 फीसद कंपनियों ने निर्णय लेने में बड़ी मात्रा में डाटा का सक्रिय रूप से प्रयोग किया। वास्तव में पिछले दो दशकों के दौरान फेसबुक, अमेजन, इंस्टाग्राम जैसी कंपनियां सामने आई हैं, जो केवल व्यक्तियों के डाटा से ही राजस्व अर्जित करती हैं। किंतु अभी भी ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां डाटा को व्यापक रूप से काम में नहीं लाया जाता।

अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत, विकास दर सात फीसद रहने का अनुमान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत देते हुए आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में देश की विकास दर चालू वित्त वर्ष में सात फीसद रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। खास बात यह है कि पिछले कई वर्षों से सुस्त पड़ी निवेश की रफ्तार अब फिर से तेजी पकड़ने लगी है। हालांकि अमेरिका और चीन के बीच छिड़े ट्रेड वार के चलते निर्यात के मोर्चे पर चुनौतियां बरकरार हैं।

अर्थव्यवस्था का हाल बयां करते हुए सर्वेक्षण में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2019-20 में विशाल राजनीतिक जनादेश सरकार को प्राप्त हुआ है जो उच्च आर्थिक वृद्धि दर के लिए अनुकूल है। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक स्थिति बेहतर होने और संरचनात्मक सुधारों के चलते विकास दर सात फीसद रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2018-19 में देश की विकास दर घटकर 6.8 फीसद रह गई, जबकि 2017-18 में यह 7.2 फीसद थी। इसके बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेज आर्थिक वृद्धि दर वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा। इसके साथ ही महंगाई दर भी चार फीसद के लक्ष्य की सीमा में ही रही। हालांकि वित्त वर्ष 2018-19 में चालू खाते का घाटा अधिक था। इसी तरह कृषि क्षेत्र की वृद्धि भी धीमी रही। सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2011-12 से सुस्त पड़ी निवेश की रफ्तार अब फिर से तेजी पकड़ने लगी है। वित्त वर्ष 2019-20 में मांग बेहतर होने और कर्ज प्रवाह बढ़ने से इसमें और तेजी आने का अनुमान है। इसका प्रमुख संकेत यह है कि उद्योग जगत को मिलने वाले ऋण में वृद्धि हो रही है। साथ ही छोटे और बड़े उद्यमों के लिए ऋण प्रवाह बढ़ा है। वर्ष 2016 और 2017 में एमएसएमई उद्यमों के लिए बैंक ऋण की वृद्धि कम थी लेकिन 2018 में इसमें वृद्धि हुई है। रिजर्व बैंक की रेपो रेट में कटौती से ब्याज दरें नीचे आएंगी। इसके साथ ही बैंकों के फंसे कर्ज में भी गिरावट आने का अनुमान है।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि ग्रामीण मजदूरी में जो गिरावट आ रही थी उसमें 2018 के मध्य से वृद्धि होने लगी है। खाद्य वस्तुओं के भाव में तेजी से ग्रामीण आय बढ़ने की उम्मीद है ।

पहल | सरकार ने बताया चार की जगह एक कानून का औचित्य

न्यूनतम मजदूरी की विसंगतियां होंगी दूर

18 राज्यों में लागू है केवल अभी न्यूनतम मजदूरी कानून, हर जगह अलग दरें

115 रुपये की दर नगालैंड में है अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की सबसे कम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने भारत में न्यूनतम मजदूरी की विसंगतियों को समाप्त करने और इसे अखिल भारतीय स्तर पर लागू करने के लिए चार श्रम कानूनों को मिलाकर एक कानून का रूप देने के लिए न्यूनतम मजदूरी संहिता बिल लाने की मंशा के साथ इसके औचित्य को स्पष्ट किया है। सरकार का मानना है कि यदि न्यूनतम मजदूरी दर को ऐसे उचित स्तर पर निर्धारित किया जाए जिससे उसका अनुपालन सुनिश्चित हो तो ये कामगारों की सुरक्षा के साथ गरीबी को कम करने में एक शक्तिशाली उपकरण साबित हो सकती है। यही वजह है कि मजदूरी संहिता बिल में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 को एक ही कानून के तहत सम्मिलित कर दिया गया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश में 429 अनुसूचित रोजगार की श्रेणियां हैं। लेकिन न्यूनतम मजदूरी तय करने में एक समान मानदंड नहीं है। कुछ राज्यों में न्यूनतम मजदूरी परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) से जुड़ी है। जबकि कुछ राज्यों में वीडीए घटक शामिल नहीं है। इससे मजदूरी दरों का स्तर और भिन्नता प्रभावित होती है।

जहां मिजोरम में अनुसूचित रोजगारों की संख्या 3 है, वहीं असम में इनकी संख्या 102 है। इनके अलावा अधिकांश राज्यों में अनुसूचित रोजगारों की संख्या दो अंकों में है। अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की सबसे कम 115 रुपये की दर नगालैंड में है। जबकि दिल्ली में 538 रुपये है। न्यूनतम मजदूरी की सबसे कम और सबसे अधिक दर के बीच भी अलग-अलग अंतर है। मसलन, नगालैंड में ये 16 रुपये है तो केरल में 905 रुपये।

यही नहीं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सभी कामगारों पर लागू नहीं होता। परिणामस्वरूप भारत में प्रत्येक तीन में से एक मजदूर संकट में है। घरेलू नौकर को केवल 18 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में अधिनियम के तहत संरक्षण मिलता है। न्यूनतम मजदूरी दरों के संशोधन में भी अक्सर विलंब होता है। यद्यपि अधिनियम महिला और पुरुष कामगारो के बीच भेदभाव नहीं करता। लेकिन हकीकत में भेदभाव होता है। उदाहरण के लिए घरेलू नौकरों में महिलाओं की, जबकि सिक्यूरिटी गार्ड में पुरुषों की प्रधानता है और घरेलू कामगारों की न्यूनतम मजदूरी सुरक्षा गार्डों के मुकाबले लगातार कम होती जा रही है। अलग-अलग राज्यों में इनकी न्यूनतम मजदूरी दरें अलग हैं। असम में सुरक्षा गार्डों की न्यूनतम मजदूरी काफी और घरेलू नौकरों के मुकाबले 44 प्रतिशत अधिक है। राष्ट्रीय आधारभूत न्यूनतम मजदूरी (एनएफएलएमडब्लू) से नीचे मजदूरी पाने वाले कामगारों को असुरक्षित मजदूर की श्रेणी में रखा जाता है। इस हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में 39 प्रतिशत अनौपचारिक पुरुष श्रमिक और 56 प्रतिशत अनौपचारिक महिला श्रमिक तथा शहरी क्षेत्रों में 28 प्रतिशत पुरुष और 59 प्रतिशत महिला श्रमिक 2012 में असुरक्षित थे। अनौपचारिक मजदूरों के मुकाबले ज्यादातर नियमित मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलती पाई है। अध्ययन से पता चलता है कि न्यूनतम मजदूरी में 10 प्रतिशत वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में 6.34 प्रतिशत तक रोजगार बढ़ता है।

राष्ट्रीय संस्करण
शुक्रवार 5 जुलाई 2019
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

सरकार ने शुरू की विदेश व्यापार नीति की समीक्षा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : निर्यात की रफ्तार बढ़ाने, घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग में वृद्धि और व्यापार घाटे को घटाने के लक्ष्य से सरकार ने मौजूदा विदेश व्यापार नीति की समीक्षा और प्रस्तावित नई नीति की तैयारी शुरू करने का फैसला लिया है। साल 2015 में लागू हुई इस नीति की अवधि मार्च 2020 में समाप्त हो रही है। सरकार ने इस संबंध में सभी संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं। विदेश व्यापार महानिदेशक ने गुरुवार को एक नोटिस जारी कर 2020-25 की प्रस्तावित नीति के लिए सभी पक्षों से 15 दिन के भीतर अपने सुझाव देने को कहा है।

मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि असत्य कहानी गढ़ना बेहद मुश्किल है। कई ऐसे संकेतक हैं जो जीडीपी के आंकड़ों की आलोचना करने वालों के दावों को झुठलाते हैं।
– कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन, मुख्य आर्थिक सलाहकार

सेंसेक्स	39,908.06 ▲ 68.81	निफ्टी	11,946.75 ▲ 30	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 34,210 ▼ ₹170	चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 38,580 ▼ ₹70	$ डॉलर	₹ 68.50 ▼ ₹ 0.39	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 63.62

सरकारी बैंकों की बदहाली के लिए आरबीआइ भी जिम्मेदार : पटेल

दो टूक ▶ पूर्व गवर्नर ने कहा, 2014 से पहले सभी पक्ष अपनी भूमिका निभाने से चूके

बैंकों, सरकार और नियामक की विफलता से पैदा हुई एनपीए की मौजूदा स्थिति

आरबीआइ मुख्यालय फाइल फोटो

मुंबई, प्रेट्र : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि 2014 तक बैंकों, सरकार और नियामक की विफलता की वजह से फंसे कर्ज के 'गड़बड़झाले' की मौजूदा स्थिति पैदा हुई और बैंकों के पूंजी आधार में कमी आई। उन्होंने सभी पक्षों से बैंकिंग क्षेत्र में यथास्थिति की ओर लौटने प्रवृत्ति से बचने को कहा है। पटेल ने पिछले साल 10 दिसंबर को रिजर्व बैंक के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। सरकार के साथ विवादों के चलते उन्होंने यह कदम उठाया था। अपने इस्तीफे के बाद पटेल ने पहली बार फंसे कर्ज पर प्रतिक्रिया दी है।

पटेल ने कहा कि बैंक जहां जरूरत से ज्यादा कर्ज देते रहे, वहीं सरकार ने अपनी भूमिका को 'पूरी तरह' से नहीं निभाया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि नियामक को कुछ पहले ही जरूरी कदम उठा लेने चाहिए थे। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने बुधवार को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में देश के बैंकिंग क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों का उल्लेख किया। इनमें खास तौर से सरकारी बैंकों में एनपीए का ऊंचा स्तर और मौजूदा पूंजी बफर शामिल है। इस बफर को बढ़ाचढ़ाकर दिखाया जा रहा है और यह बैंकिंग क्षेत्र के तनाव से निपटने के लिए नाकाफी है। पटेल ने अपने प्रजेंटेशन में कहा कि हम इस हालत में कैसे पहुंचे? इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। 2014 से पहले सभी पक्ष अपनी भूमिका सही से निभाने में विफल रहे। इनमें बैंक, नियामक और सरकार शामिल हैं।

पटेल ने कहा कि हमें पिछले रवैये की तरफ लौटने से बचना चाहिए। समस्या को छिपाने से काम नहीं चलेगा। इससे भविष्य में निवेश के लिए जरूरी कर्ज की उपलब्धता प्रभावित होगी। मौद्रिक नीति के मुकाबले वित्तीय नीति को प्राथमिकता के बाद अब हम बैंकिंग रेग्युलेशंस के मुकाबले वित्तीय नीति के दबदबे देख रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की संपत्ति की गुणवत्ता की समीक्षा जरूरी है, क्योंकि वे वित्तीय प्रणाली गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं।

पिछले पांच वर्षों में हुए बड़े बदलाव

वर्ष 2014 से कुछ महीने पहले ही पटेल के पूर्ववर्ती रघुराम राजन ने आरबीआइ की कमान संभाली थी और इसके बाद केंद्र में सरकार बदल गई। इसके बाद रिजर्व बैंक ने संपत्ति की गुणवत्ता की समीक्षा शुरू की। इसके परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली में भारी तनाव की पहचान हुई और इसके समाधान के लिए बैंक्रप्सी कानून बना। इन कदमों से अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी कर्ज उपलब्ध कराने की बैंकों की क्षमता प्रभावित हुई।

आम बजट से पहले लगातार चौथे दिन शेयर बाजारों में उछाल

मुंबई, प्रेट्र : चालू वित्त वर्ष में विकास दर के सात फीसद रहने के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमान के बाद गुरुवार को देश के शेयर बाजारों में लगाता चौथे सत्र में तेजी दर्ज की गई। विश्लेषकों ने कहा कि आम बजट में खपत बढ़ाने और विकास तेज करने संबंधी कदमों की घोषणा की उम्मीद से भी बाजार में तेजी को बल मिला। आम बजट शुक्रवार को पेश होगा।

बीएसई का सेंसेक्स 68.81 अंकों की तेजी के साथ 39,908.06 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 30 अंकों की तेजी के साथ 11,946.75 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भारती एयरटेल में सर्वाधिक 2.60 फीसद तेजी रही। टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक एक फीसद से अधिक उछले। हीरो मोटोकॉर्प 0.73 फीसद और पावर ग्रिड 0.60 फीसद उछले। दूसरी ओर यस बैंक में सर्वाधिक 3.56 फीसद गिरावट रही। एचसीएल टेक 1.15 फीसद, सन फार्मा 0.90 फीसद और वेदांता भी 0.90 फीसद लुढ़के।

सेक्टरों के लिहाज से बीएसई के टेलीकॉम सेक्टर में सर्वाधिक 1.53 फीसद तेजी रही। दूसरी ओर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में सर्वाधिक 1.58 फीसद गिरावट रही। बीएसई के मिडकैप इंडेक्स में 0.19 फीसद गिरावट रही, जबकि स्मॉलकैप में 0.12 फीसद तेजी रही। आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के फंडामेंटल रिसर्च (इन्वेस्टमेंट सर्विसेज) - एवीपी इक्विटी रिसर्च के प्रमुख नरेंद्र सोलंकी ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में चालू वित्त वर्ष के लिए सात फीसद का विकास अनुमान दिए जाने से बाजार में सकारात्मकता का माहौल बना। सरकार ने पिछले वित्त वर्ष की विकास दर 6.8 फीसद आंकी है। सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के मुख्य निवेश अधिकारी सुनील शर्मा ने कहा कि बाजार का ध्यान बजट पर टिका हुआ है। विकास को बढ़ावा देने वाले और सुधारवादी बजट से बाजार में तेजी आएगी।

विदेशी बाजारों में तेजी का रुझान : अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की मुख्य नीतिगत ब्याज दर में इस महीने कटौती किए जाने की उम्मीद और उसके बाद अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा भी अपनी-अपनी ब्याज दर घटाने के अनुमान से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेजी का रुझान रहा। एशिया के प्रमुख बाजारों में शंघाई और हांगकांग के शेयर बाजारों में गिरावट रही, जबकि टोक्यो और सियोल के बाजारों में तेजी रही। यूरोपीय बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी का माहौल देखा गया।

इंडियामार्ट की दमदार शुरुआत

नई दिल्ली : कारोबारी उत्पादों व सेवाओं की ऑनलाइन मार्केटप्लेस कंपनी इंडियामार्ट इंटरमेश गुरुवार को शेयर बाजारों पर सूचीबद्ध हुई। बीएसई पर पहले कारोबार दिन कंपनी के शेयर इश्यू प्राइस के मुकाबले 33.87 फीसद उछलकर 1,302.55 रुपये पर बंद हुए। एनएसई पर कंपनी के शेयर 1,301 रुपये पर बंद हुए।

- **सेंसेक्स 68.81 अंकों की तेजी के साथ 39,908.06 पर बंद**
- **निफ्टी 30 अंकों के उछाल के साथ 11,946.75 पर स्थिर**

बांबे स्टॉक एक्सचेंज फाइल फोटो

इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण केंद्र बन सकता है भारत

आर्थिक सर्वेक्षण-2018-19

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- **देश में अभी कुल वाहनों का महज 0.06 फीसद है बिजली चालित**
- **वर्ष 2030 तक 30 फीसद बिजली चालित पैसेंजर कारों का लक्ष्य**

दुनिया में अभी तक जितनी भी मोटर वाहन-क्रांति हुई हैं, भारत उनमें लेट-लतीफ ही साबित हुआ है। लेकिन अब इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में सरकार की मंशा बदली नजर आ रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दुनिया के दूसरे देश जिस तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं, भारत भी वही तेजी दिखाएगा और देश के कुछ शहर इलेक्ट्रिक वाहनों के डेट्रायट (कार निर्माण के लिए प्रसिद्ध अमेरिकी शहर) के तौर पर स्थापित होंगे। यह बात गुरुवार को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में कही गई है। माना जा रहा है कि शुक्रवार को पेश होने वाले आम बजट में भी इलेक्ट्रिक वाहनों (इवी) को बढ़ावा देने वाले उपायों का एलान होगा।

सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में बिजली से चलने वाली गाड़ियों की अपार संभावनाएं सिर्फ इसलिए नहीं है कि यह पर्यावरण अनुकूल है, बल्कि यहां इन वाहनों के मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने की और विकास की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन इसके लिए नीतियों का समर्थन चाहिए। खास तौर पर इवी रखने की लागत कम करने की जरुरत है। इसके लिए देश में बैटरी निर्माण को बढ़ावा देने और पूरे देश में एक यूनिवर्सल चार्जिंग नीति लाने का सुझाव दिया गया है। अभी कुछ तकनीक से आधे घंटे में इवी चार्ज हो जाते हैं तो कुछ से आठ घंटे में।

वैसे, अभी भारत में कुल वाहनों में ईवी की हिस्सेदारी सिर्फ 0.06 फीसद है। जबकि चीन में यह बढ़कर दो फीसद हो चुकी है। नॉर्वे जैसे देशों में यह 36 फीसद है। हाल ही में नीति आयोग ने इस बारे में एक रोडमैप तैयार किया गया है जिसमें वर्ष 2030 तक देश के कुल निजी कारों का 30 फीसद और वाणिज्यिक वाहनों का 70 फीसद बिजली चालित करने का लक्ष्य रखा है। सर्वेक्षण का कहना है कि हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सबसे जरुरी है देशभर में चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराना और वाहनों को तेजी से चार्जिंग की सुविधा देना। साथ ही बैट्री की क्षमता को बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है ताकि एक बार चार्ज करने के बाद ज्यादा से ज्यादा दूरी तय की जा सके। बहरहाल, एक अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार के साथ ही कई राज्यों ने इवी नीति को बढ़ावा देना शुरू किया है, लेकिन अभी यह शुरुआत ही है।

एस्सार स्टील के अधिग्रहण की सभी बाधाएं खत्म

नई दिल्ली, प्रेट : नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल (एनक्लैट) ने गुरुवार को आर्सेलरमित्तल की पात्रता को लेकर एस्सार स्टील के प्रमुख शेयरधारक की आपत्तियों को खारिज कर दिया। एनक्लैट ने इसके साथ ही आर्सेलरमित्तल की ओर से एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए जमा की गई 42,000 करोड़ रुपये की बोली को मंजूरी दे दी। हालांकि एनक्लैट ने परिचालन कर्जदाताओं को दिवाला प्रक्रिया से प्राप्त रकम में वित्तीय कर्जदाताओं के समान अधिकार दिया।

एस्सार स्टील की नीलामी नए इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत 54,547 करोड़ रुपये की वसूली के लिए हुई है। कंपनी पर यह बकाया वित्तीय और परिचालन कर्जदाताओं का था। एनक्लैट ने अपने आदेश में कहा कि वित्तीय कर्जदाताओं को उनके 49,473 करोड़ रुपये के स्वीकृत दावे का 60.7 फीसद मिलेगा। समाधान प्रक्रिया से प्राप्त होने वाली राशि का शेष हिस्सा परिचालन कर्जदाताओं को मिलेगा।

पीठ ने कहा कि 42,000 करोड़ रुपये के वितरण में कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) की कोई भूमिका नहीं होगी। एनक्लैट ने परिचालन कर्जदाताओं के दावों को भी मंजूरी दे दी। परिचालन कर्जदाताओं में दक्षिण गुजरात, गुजरात एनर्जी, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, गेल, ओएनजीसी और एनटीपीसी शामिल हैं। एस्सार स्टील का अधिग्रहण करने को लेकर आर्सेलरमित्तल की पात्रता के मुद्दे पर एनक्लैट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे का निपटारा कर दिया है और इसे बार-बार नहीं उठाया जा सकता है। इसलिए याचिकाकर्ता प्रशांत रुइया और हस्तक्षेपकर्ता एस्सार स्टील एशिया होल्डिंग्स लिमिटेड की याचिका खारिज की जाती है।

- **एनक्लैट ने एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए आर्सेलरमित्तल की बोली को मंजूरी दी**
- **परिचालन कर्जदाताओं समाधान प्रक्रिया से प्राप्त रकम में वित्तीय कर्जदाताओं के समान अधिकार दिया**

सपूरजी पालोनजी की याचिका पर वेंकटरमणन को नोटिस

नई दिल्ली, प्रेट्र : सपूरजी पालोनजी समूह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टाटा ट्रस्ट्स के पूर्व मैनेजिंग ट्रस्टी आर वेंकटरमणन से जवाब मांगा। याचिका में वेंकटरमणन के खिलाफ सपूरजी पालोनजी के अवमानना मामले को खारिज किए जाने को चुनौती दी गई है। वेंकटरमणन को नोटिस जारी करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि यह और कुछ नहीं, बल्कि कॉरपोरेट युद्ध है।

सपूरजी पालोनजी समूह के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि कंपनी द्वारा दाखिल अवमानना याचिका को बांबे हाइ कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने में गलती हुई है। सपूरजी पालोनजी समूह द्वारा आपराधिक अवमानना याचिका दाखिल किए जाने के बाद निचली अदालत ने अक्टूबर 2018 में वेंकटरमणन को सम्मन भेजने की प्रक्रिया शुरू किए जाने का आदेश दिया था। सपूरजी पालोनजी समूह ने अपनी शिकायत में कहा था कि वेंकटरमणन ने प्रेस विज्ञप्ति में कुछ टिप्पणी की थी, जो गलत थी और समूह के लिए अपमानजनक थी।

प्रवर्तन निदेशालय ने आम्रपाली के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) नोएडा में निवेशकों के करोड़ों रुपये हड़पने के आरोपित आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनीलांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। आम्रपाली ग्रुप ने निवेशकों को फ्लैट देने का सपना दिखाकर करीब पांच हजार करोड़ रुपये की धांधली की है।

गौरतलब है कि आम्रपाली बिल्डर्स ने नोएडा में बहुमंजिला इमारतें बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था। आम्रपाली ग्रुप की करीब 46 रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। कंपनी ने फ्लैट देने का वादा कर 40 हजार से अधिक लोगों से निवेश कराया था और उनकी रकम हड़प ली थी। कंपनी संचालकों ने निवेशकों को रकम वापस करने का झांसा देकर काफी दिनों टरकाया भी था। बाद में निवेशकों ने नोएडा व दिल्ली में कंपनी संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी के कई मुकदमे दर्ज कराए थे। कई निवेशकों ने अपनी डूबी रकम हासिल करने के लिए कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया है। करोड़ों की इस धांधली के मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट भी ले चुका है, जिसके बाद जांच एजेंसी भी हरकत में आई। ईडी ने निवेशकों की एफआइआर को आधार बनाकर अपना केस दर्ज किया है। आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा समेत तीन पदाधिकारी जेल में हैं।

फाइल फोटो

- **नोएडा में हजारों निवेशकों से ठगी का मामला, फ्लैट का सपना दिखाकर लूटी गाढ़ी कमाई**
- **करीब पांच हजार करोड़ रुपये की धांधली का है आरोप**

रिवरफ्रंट घोटाले में तीन इंजीनियरों की एक करोड़ की संपत्ति अटैच

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

सपा शासनकाल में हुए करोड़ों के गोमती रिवरफ्रंट घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोपित तीन इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की है। ईडी ने इंजीनियरों की एक करोड़ की संपत्ति अटैच की है। आरोपित इंजीनियरों ने ठेकेदारों से हुई काली कमाई से भूखंड व फ्लैट खरीदे थे।

उल्लेखनीय है कि गोमती रिवरफ्रंट घोटाले के मामले में 19 जून 2017 को लखनऊ के गोमतीनगर थाने में सिंचाई विभाग के तत्कालीन चीफ इंजीनियर गुलेश चंद (अब सेवानिवृत्त) सहित आठ अभियंताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। बाद में सीबीआइ ने इस घोटाले का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। ईडी ने फरवरी 2018 में रिवरफ्रंट घोटाले के मामले में मनीलांड्रिंग का केस दर्ज कर अपनी पड़ताल शुरू की थी। ईडी के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह के निर्देश पर गुरुवार को आरोपित इंजीनियर रूप सिंह यादव, अनिल यादव व एसएन शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हुई। बताया गया कि रूप सिंह यादव का नोएडा स्थित भूखंड, अनिल यादव के लखनऊ स्थित तीन भूखंड व एसएन शर्मा का गाजियाबाद स्थित फ्लैट अटैच किया गया है। ईडी ने बीते दिनों आरोपित इंजीनियरों को तलब कर उनसे पूछताछ की थी। रिवरफ्रंट के निर्माण काम से जुड़े कई ठेकेदारों से भी गहनता से पूछताछ की गई थी।

ईडी ने जनवरी माह में आरोपितों के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद समेत नौ ठिकानों में छापेमारी भी की थी और अहम सुबूत जुटाये थे। सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त इंजीनियर रूप सिंह यादव के नोएडा स्थित आवास में भी छानबीन की गई थी। ठेकेदारों व इंजीनियरों के ठिकानों से बैंकों से जुड़े कई दस्तावेज भी मिले थे। सूत्रों का कहना है कि आरोपित इंजीनियरों व ठेकेदारों के बैंक खातों की पड़ताल में ईडी के हाथ अहम साक्ष्य लगे थे, जिनके आधार पर जांच एजेंसी ने आगे कदम बढ़ाये। आरोपित इंजीनियरों ने पत्नी व करीब रिश्तेदारों के नाम पर कई संपत्तियां जुटा रखी थीं।

बासमती चावल निर्यातक की संपत्ति जब्त

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बासमती चावल निर्यातक कंपनी केआरबीएल लिमिटेड की 15 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त कर ली। ईडी ने संप्रग सरकार के कार्यकाल में हुए एंब्रेयर विमान रक्षा सौदे में मनी लांड्रिंग जांच के तहत गुरुवार को यह कार्रवाई की। यह मामला 20.8 करोड़ डॉलर के एंब्रेयर सौदे में कथित कमीशनखोरी के लिए किए गए भुगतान की जांच से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा है कि जब्त की गई संपत्तियों में पंजाब के संगरूर जिले के धुरी तहसील में एक भूखंड और चावल मिल शामिल हैं। यह संपत्ति चावल कंपनी केआरबीएल लिमिटेड से जुड़ी है। केआरबीएल लिमिटेड इंडिया गेट बासमती चावल का उत्पादन करती है। बयान के मुताबिक, मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 15.32 करोड़ रुपये है। ईडी ने ब्राजील के एंब्रेयर एसए, रक्षा मंत्रालय के अज्ञात अधिकारियों, कथित बिचौलिए विपिन खन्ना, सिंगापुर के इंटरडेव एविएशन सर्विस एवं अन्य के खिलाफ सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआइआर के आधार पर आपराधिक शिकायत दर्ज की थी।

मुनाफावसूली के कारण सोना, चांदी लुढ़के

नई दिल्ली, प्रेट्र : मुनाफावसूली और विदेशी बाजारों के कमजोर रुझानों के कारण गुरुवार को सराफा बाजार में सोने और चांदी में गिरावट दर्ज की गई। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक सोना 170 रुपये गिरकर 34,210 रुपये प्रति 10 ग्राम का रह गया। राष्ट्रीय राजधानी में 99.9 फीसद खरा सोना 170 रुपये गिरकर 34,210 रुपये और 99.5 फीसद खरा सोना भी इतनी गिरावट के साथ 34,040 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर आ गया। न्यूयॉर्क में बुधवार को सोने में 1,413.46 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर और चांदी में 15.26 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार हुआ।

मुनाफावसूली के कारण सोने के हाजिर भाव में गिरावट आई। अमेरिकी बाजार गुरुवार को उस देश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बंद रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में आठ ग्राम सोने की गिन्नी 26,800 रुपये प्रत्येक के भाव पर कायम रही। सोने में 260 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल दर्ज किया गया था। चांदी हाजिर 70 रुपये लुढ़ककर 38,580 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। वीकली डिलीवरी 198 रुपये गिरकर 37,150 रुपये प्रति किलोग्राम की रह गई।

अगले दो दिन में पूरे देश पर छा जाएगा मानसून

जेएनएन, नई दिल्ली

- **उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में पकड़ी रफ्तार, हिमाचल में दी दस्तक**
- **पंजाब, हरियाणा में किसानों के चेहरे खिले, दिल्ली-एनसीआर में भी राहत**

दिल्ली सहित उत्तर भारत में मानसून अगले दो दिनों में पहुंच जाएगा। कई राज्यों में मानसून पूर्व बारिश भी शुरू हो चुकी है। बीच-बीच में हो रही बूंदा-बांदी से लोगों को राहत मिली है। मानसून गुजरात, राजस्थान, मप्र और उप्र के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा में भी गुरुवार शाम हल्की बारिश ने लोगों को सुकून दिया है। आने वाले दो दिनों में यह दिल्ली-एनसीआर में पूरी तरह पहुंच जाएगा।

गुरुवार को राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी बारिश हुई। हालांकि, 44.7 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। ज्यादातर बारिश पूर्वी राजस्थान के इलाकों में हुई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू में भी बारिश हुई। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी दिखा। पंजाब और हरियाणा में भी मानसून पूर्व बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए। यह बारिश धान के लिए फायदेमंद है। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में शुक्रवार को भी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी एक दो दिनों में भारी बारिश की संभावना है।

हरियाणा की ऐतिहासिक नगरी पानीपत में गुरुवार को मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। अर्से से प्यासे खेतों में बारिश की बूंदें बरसी तो धरतीपुत्र पानी के बहाव को बांधने में जुट गए। धान की रोपाई के लिए यह बरसात वरदान है। राजेंद्र फोर

हिमाचल में जमकर बारिश : हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को जमकर बारिश हुई। प्रदेश के आधे हिस्से में झमाझम बारिश हुई। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में सबसे अधिक 41 मिलीमीटर बारिश हुई। रिमझिम फुहारों से अधिकतम तापमान पांच से छह डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया। शुक्रवार को मानसून के पूरे प्रदेश में पहुंचने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, इन दिनों बारिश धान के लिए फायदेमंद है। मक्का सहित अन्य सब्जियों के पौधों के लिए बारिश अमृत बनकर आई है।

उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट : उत्तराखंड में मौसम का मिजाज डराने लगा है। राज्य मौसम केंद्र ने छह से आठ जुलाई तक दून समेत आठ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को भी सात जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गुरुवार को रुद्रप्रयाग जिले की सारी चमसील ग्रामसभा के अतिवृष्टि से मलबा और पानी आबादी के निकट खेतों में घुस गया। इससे लोग सहम गए। मलबे से कृषि भूमि को नुकसान हुआ है। भूस्खलन से बड़ेथी में गंगोत्री हाईवे चार घंटे अवरुद्ध रहा।

जम्मू में राहत की बारिश : जम्मू में शाम में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिला दी। आठ जुलाई तक मानसून के जम्मू में दस्तक देने की संभावना है। अगले कुछ दिनों तक बीच-बीच में बारिश होती रहेगी। इससे तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन उमस परेशान करेगी।

रास उपचुनाव से पहले पालनपुर में जुटे गुजरात के 65 कांग्रेसी विधायक

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

- **पार्टी ने बागी विधायक अल्पेश ठाकोर व धलव झाला के घरों पर व्हिप चिपकाए**

गुजरात में राज्यसभा की दो सीटों के लिए शुक्रवार को होने वाले मतदान से पहले गुरुवार की शाम को कांग्रेस ने अपने 65 विधायकों को पालनपुर के एक पैलेस में इकट्ठा कर लिया। पार्टी ने इसे विधायक दल की बैठक बताया है। हालांकि, बागी विधायक अल्पेश ठाकोर व उनके साथी विधायक धवलसिंह झाला वहां नहीं पहुंचे हैं। कांग्रेस ने उनके घरों पर पार्टी का व्हिप चिपका दिया है।

राज्यसभा उपचुनाव से पहले टूट को लेकर सशंकित कांग्रेस ने अपने 71 में से 65 विधायकों को बनासकांठा जिले के पालनपुर स्थित बालाराम पैलेस में इकट्ठा कर लिया। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने बताया कि गुरुवार को यहां विधायकों को राज्यसभा चुनाव का प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद के विधायक गयासुद्दीन शेख, हिम्मतसिंह पटेल व कुछ अन्य रथयात्रा आदि के कारणों से पालनपुर नहीं पहुंच पाए हैं। पार्टी से दूरी बनाने वाले विधायक अल्पेश ठाकोर व धवलसिंह झाला को व्हिप मेल व डाक के जरिये भेजने के साथ ही उनके घरों पर भी चिपका दिए गए हैं। ठाकोर ने पालनपुर न जाने के लिए बीमारी और झाला ने कोई सूचना न होने की बात कही है।

कांग्रेस विधायक शुक्रवार सुबह पालनपुर से सीधे गांधीनगर मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। राज्यसभा की दोनों सीटों के लिए सुबह नौ से शाम चार बजे तक मतदान होगा, जबकि पांच बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। अगस्त 2017 में हुए राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु ले जाया गया था और वे चुनाव के दिन सीधे मतदान केंद्र पर पहुंचे थे।

आज गांधीनगर पहुंचेंगे एस. जयशंकर : राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी एवं केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर शुक्रवार सुबह गांधीनगर पहुंचेंगे। पहले सूचना थी कि वह गुरुवार की शाम को ही पहुंच जाएंगे, लेकिन बाद में कार्यक्रम में बदलाव हो गया।

एफएसएसएआइ ने कहा, किसी नमक से स्वास्थ्य को खतरा नहीं

नई दिल्ली, आइएएनएस : प्रमुख नमक ब्रांड्स के इस्तेमाल को लेकर पैदा हुई सुरक्षा जोखिम की चिंता के बीच भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) ने इस आरोप को खारिज किया है कि प्रमुख ब्रांड्स के नमक में पोटैशियम फेरोसाइनाइड का स्तर बहुत ज्यादा है।

एफएसएसएआइ ने एक ट्वीट में कहा कि नमक की प्रोसेसिंग में फेरोसाइनाइड का इस्तेमाल एंटी केकिंग एजेंट्स के रूप में किया जाता है और यह खाने के नजरिए से सुरक्षित है। मीडिया में प्रस्तुत की गई टेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी मौजूदगी एफएसएसएआइ द्वारा तय की गई 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम की सीमा के दायरे में है। यह अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानक कोडेक्स की सीमा से भी कम है। कोडेक्स के द्वारा तय की गई सीमा 14 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम है। एंटी केकिंग एजेंट का मतलब यह है यह पदार्थ नमक को ढेला बनने से रोकता है।

दस हजार करोड़ की लागत से शुरू होगा तिलहन मिशन

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

मांग आधारित उत्पादन के सहारे कृषि क्षेत्र के विकास की योजनाओं को अंतिम रूप देने की तैयारी है। खाद्य तेलों की भारी मांग को देखते हुए शुक्रवार को पेश होने वाले बजट में इसकी खेती पर जोर दिए जाने की संभावना है। बजट में इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये की लागत वाले एक मिशन की शुरुआत करने का प्रावधान हो सकता है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन की तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि से इसके संकेत भी दे दिए हैं।

खाद्य तेलों की घरेलू मांग का लगभग 60 फीसद हिस्सा आयात से पूरा होता है, जिस पर पर लगभग 75 हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च होती है। कुल आयात बिल में खाद्य तेलों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, जिसे रोकना सरकार की प्राथमिकता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों तिलहन पैदावार को बढ़ावा देने की अपनी मंशा जाहिर की थी। उन्होंने दलहन की दर्ज पर तिलहन के क्षेत्र में भी पैदावार में वृद्धि पर जोर दिया था।

कृषि मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक तिलहन फसलों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना तैयार की है, जिसके लिए करीब 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान हो सकता है। देश में तिलहन खेती के लिए किसानों को उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक और उपज बेचने की उचित सुविधा मुहैया कराने का प्रावधान किया जा सकता है। तिलहन उपज के खरीद की गारंटी देने की योजना बन सकती है। खाद्य तेलों के आयात को हतोत्साहित करने पर भी जोर होगा। खरीफ सीजन की तिलहन फसलों के साथ आगामी रबी सीजन वाली फसलों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। बजट में तिलहन पैदावार बढ़ाने के लिए मिशन शुरू किया जा सकता है। कई दशक पहले तिलहन मिशन बना तो था, लेकिन वह बेनतीजा रहा। दरअसल, देश में तिलहन की पैदावार में लगातार वृद्धि तो हो रही है, लेकिन इसकी रफ्तार खाद्य तेलों की बढ़ती मांग के मुकाबले बहुत कम है।

Downloaded from: www.iascgl.com

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 5 जुलाई 2019

दैनिक जागरण

जो आप आज और अभी कर रहे हैं, उसे सर्वश्रेष्ठ करें

जनप्रतिनिधियों की गुंडागर्दी

इंदौर में भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय की ओर से नगर निगम के कर्मियों से मारपीट का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक नीतेश राणे की ओर से एक इंजीनियर से बदसलूकी का मामला सामने आ गया। इन दोनों घटनाओं के साथ तेलंगाना की उस शर्मनाक और भयावह घटना को भी नहीं भुलाया जा सकता जिसमें टीआरएस विधायक के भाई ने भारी भीड़ जुटाकर वन विभाग की महिला अधिकारी को घेरकर पीटा था। ये तीनों मामले लोकतंत्र, राजनीति और जनप्रतिनिधियों को शर्मिंदा करने के साथ ही विधि के शासन का उपहास उड़ाने वाले हैं। इन तीनों मामलों में यह देखने को मिला कि जो सरकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधियों की हिंसा का शिकार बने वे अपना काम करने में लगे हुए थे। इंदौर में नगर निगम कर्मचारी एक जर्जर मकान को गिराने गए थे, लेकिन भाजपा विधायक को यह रास नहीं आया और वह उन्हें बल्ला लेकर पीटने लगे। तेलंगाना के आदिलाबाद में टीआरएस विधायक के भाई एवं जिला परिषद के अध्यक्ष कोनेरू कृष्णा ने वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने गईं महिला वन अधिकारी पर लाठियां बरसाकर उन्हें मरणासन्न कर दिया। महाराष्ट्र में मुंबई-गोवा हाईवे के पास कांग्रेसी विधायक ने अपने समर्थकों के साथ एक इंजीनियर को घेरकर पहले उन पर कीचड़ उड़ेला और फिर उन्हें खंभे से बांधने की कोशिश की। क्या ऐसी हरकतों को गुंडागर्दी के अलावा और कुछ कहा जा सकता है? आखिर जब जनप्रतिनिधि इस तरह खुली गुंडागर्दी करेंगे तब फिर आम लोगों से यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि वे कानून के शासन के प्रति समर्पित रहें?

यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि बीते कुछ समय से ऐसे मामले बढ़े हैं जिनमें भीड़ किसी न किसी बहाने एकत्रित होकर अराजकता फैलाने अथवा सरकारी कामकाज में अड़ंगा लगाने का काम करती है। यह हमारे नीति-नियंताओं के लिए गंभीर चिंता का विषय बनना चाहिए कि अराजक भीड़ केवल कानून हाथ में लेने का ही काम नहीं कर रही, बल्कि वह सरकारी कर्मियों, डॉक्टरों और यहां तक कि पुलिस को भी निशाना बना रही है। क्या इससे खराब बात और कोई हो सकती है कि कानून की रक्षक पुलिस ही भीड़ की अराजकता का शिकार हो जाए? यदि लोकतंत्र को भीड़तंत्र में तब्दील होने से रोकना है तो फिर भीड़ की हिंसा के सिलसिले को रोकना ही होगा। आवश्यक हो तो नए नियम-कानून बनाने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि इंदौर, आदिलाबाद और महाराष्ट्र में जिन जनप्रतिनिधियों ने गुंडागर्दी की उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जरूरी यह है कि उन्हें अपने किए की सजा मिले और जल्द से जल्द मिले। आकाश विजयवर्गीय, कोनेरू कृष्णा और नीतेश राणे जैसे अराजक जनप्रतिनिधियों और उनके समर्थकों को सजा देकर ही यह संदेश दिया जा सकता है कि अराजकता को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या यह अजीब नहीं कि जिन जनप्रतिनिधियों पर नियम-कानूनों के पालन का दायित्व है वे ठीक इसका उलट करने में लगे हुए हैं? किसी को भी इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वह भीड़ के सहारे अभद्र अथवा अराजक हरकतें करके बच निकल सकता है।

मंथन के बाद हों फैसले

शिक्षकों के तबादलों और उच्चीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अन्यत्र समायोजित करने के मामले में आखिरकार उत्तराखंड सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। तबादलों को लेकर शिक्षा महकमे का रवैया चौंकाने वाला है। तबादला एक्ट लागू होने के बावजूद महकमे के स्तर पर एक्ट के क्रियान्वयन को लेकर जमीनी स्तर पर कार्यवाही नजर नहीं आती। ऑनलाइन पोर्टल की हालत भी अपेक्षा के अनुरूप दुरुस्त नहीं हो सकी। एजुकेशन पोर्टल को अपडेट करने के लिए हर बार निर्देश तो दिए जाते हैं, लेकिन ब्लॉकों, जिलों से लेकर विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों से संबंधित डाटा दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। तबादलों की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन की गई। यही नहीं अनिवार्य और अनुरोध, दोनों ही आधार पर तबादलों के लिए शिक्षकों से विकल्प भी मांगे गए। इसके बावजूद दुर्गम से ऐसे शिक्षकों के तबादले कर दिए गए, जिन्होंने सुगम में जाने के लिए आवेदन ही नहीं किया था। लापरवाही का आलम यह है कि बगैर प्रतिस्थानी भेजे ही एकल विद्यालयों और सीमांत पर्वतीय जिलों में शिक्षकों के तबादले कर दिए गए। सेवानिवृत्ति की कगार पर खड़े शिक्षकों को भी बख्शा नहीं गया। तबादला एक्ट लागू नहीं होने से शिक्षकों का बड़ा वर्ग खफा है। एक्ट का समर्थन करने वाला यह तबका अब एक्ट के क्रियान्वयन में हीलाहवाली से अचंभित है। ऐसे में तबादलों को लेकर महकमे का उदासीन रवैया अंततः सरकार पर भारी पड़ गया। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालयों में तबादलों पर आपत्तियों के लिए प्रत्यावेदन दिए जा रहे हैं। नतीजतन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके बाद ही ऐसे तबादलों को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का आदेश शासन ने जारी किया। यही नहीं, तबादलों को लेकर शासन ने जांच भी बिठा दी है। कमोबेश इसी तरह सरकार को उच्चीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन की दोहरी व्यवस्था खत्म करने के लिए गए फैसले को भी बदलने को मजबूर होना पड़ा है।

योग्य नेताओं के अभाव से जूझती राजनीति

डॉ. एके वर्मा

अधिकतर पार्टियां केवल चुनाव को ही अपनी कर्मभूमि मानती हैं, चुनावों के बाद उन्हें समझ में नहीं आता कि किया क्या जाए?

बीते दिनों लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री के लिए जैसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया और इसके पहले चुनावों में राहुल गांधी ने जिस तरह उन्हें 'चोर' कहा वह राजनीति में भाषाई अशिष्टता की पराकाष्ठा है। इस अशिष्टता से सभी परिचित हैं। यह भी सर्वविदित है कि सांसदों और विधायकों द्वारा किस प्रकार अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की उपेक्षा की जाती है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि देश की सभी समस्याओं के लिए किस तरह राजनीति और राजनीतिज्ञों को दोष दिया जाता है। लोगों का मानना है कि ज्यादातर राजनीतिज्ञ भ्रष्ट, आपराधिक-प्रकृति के होते हैं और धनार्जन में लिप्त रहते हैं। इसके बावजूद चुनावों में जनता बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती है और वैसे ही लोगों को लोकसभा, विधानसभाओं, पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए चुनती है। विडंबना यह कि हमें जनप्रतिनिधियों से शिकायत भी है और उन पर भरोसा भी। निःसंदेह जनता की आस्था लोकतंत्र में बनी हुई है, लेकिन उसे वैकल्पिक जन-प्रतिनिधियों की तलाश भी है। जब अच्छे लोगों से राजनीति में भाग लेने की बात की जाती है तो वे उसके गंदे स्वरूप का हवाला देकर उससे किनारा कर लेते हैं। जो लोग राजनीति की ओर रुख करते हैं वे या तो निराश होकर लौट आते हैं या फिर स्थानीय स्तर पर नेताओं की खींच-तान में उलझ कर रह जाते हैं।

इसमें दोराय नहीं कि लोगों को राजनीति में आने में दिलचस्पी है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि राजनीति वास्तव में है क्या? उसमें आने का सही रास्ता क्या है? उसकी तैयारी कैसे की जाती है? कब उसमें प्रवेश करना चाहिए? दैनिक कार्यों के साथ कितना समय सक्रिय राजनीति में देना जरूरी है? छात्रों और युवाओं को समझ नहीं आता कि वे कैरियर और राजनीति में कैसे समन्वय स्थापित करें? यदि कोइ युवा राजनीति में जाना चाहता है तो परिवार का समर्थन नहीं मिलता, क्योंकि उसे पढ़ाई और नौकरी के लिए एक बाधा के रूप में देखा जाता है। जब तक हम बीज नहीं बदलेंगे तो भावी राजनीतिज्ञों की फसल कैसे बदलेगी? स्वतंत्रता के पूर्व गांधीजी ने राजनीति की नई पौध तैयार की, लेकिन उसे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आगे नहीं बढ़ाया और पार्टी में 'टॉप-डाउन' मॉडल को जन्म दिया। परिणामस्वरूप कांग्रेस में आलाकमान संस्कृति चल निकली जिसका दंश पार्टी आज तक झेल रही है। कांग्रेस गांधी परिवार पर इतना आश्रित हो गई है कि ज्यादातर कांग्रेसी राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद भी उन्हें ही अध्यक्ष पद पर देखना चाहते हैं। 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण ने राजनीतिज्ञों की नई पौध तैयार की, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जून 1975 में आपातकाल लगा कर उसे कुचलने का प्रयास किया। 1977 में विभिन्न दलों के विलय के चलते जनता पार्टी की सरकार बनी जरूर, लेकिन घटक दलों के आपसी कलह से वह उस पौध को संभाल न सकी और इस तरह जुझारू राजनीतिज्ञों की फसल समय से पूर्व ही नष्ट हो गई। 2011 में अन्ना हजारे ने तीसरी बार नई पौध लगाने की कोशिश की और वैकल्पिक राजनीति का नया-मॉडल देने का प्रयास किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे महत्वाकांक्षी लोगों के हाथों वह खत्म हो गई। अब चौथी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नव-राजनीति और नव-राजनीतिज्ञों की पौध तलाशी जा रही है।

अवधेश राजपूत

ज्यादातर पार्टियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है कि नई राजनीति के लिए नए राजनीतिज्ञ आएंगे कहां से? जो लोग स्वेच्छा से राजनीति में आए उनकी दलों ने कभी चिंता नहीं की और न ही इसकी जरूरत समझी कि उन्हें समुचित प्रशिक्षण देकर बताया जाए कि राजनीति होती क्या है? हम राजनीति और राजनीतिज्ञों को कोसते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि राजनीति तो समाज में संघर्षों के समाधान की वह कुंजी है जिससे लोक-कल्याण सुनिश्चित किया जाता है। एक पहल कांग्रेस ने 2005 में की थी। चित्रकूट और गोरखपुर में 500-600 युवा कांग्रेसियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की गई थी। इनमें राहुल गांधी और मनमोहन सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों सहित युवा कांग्रेसी शामिल हुए। दोनों शिविरों में उन्हें प्रशिक्षित करने का मेरा अनुभव अच्छा रहा। मैंने पार्टी और नेतृत्व की गलतियों को इंगित करते हुए सुझाव दिया था कि कांग्रेस को अपने पुनरुत्थान के लिए 1885 में पार्टी की स्थापना के समय पारित प्रस्ताव पर अमल करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने उन सुझावों को गंभीरता से नहीं लिया। चूंकि भाजपा को संघ के माध्यम से प्रशिक्षित कार्यकर्ता मिलते रहते हैं इसलिए उसके पास राजनीतिज्ञों की सप्लाई लाइन अच्छी है, लेकिन कांग्रेस ने सेवा दल, वानर सेना और युवा कांग्रेस जैसी अपनी ही सप्लाई लाइन को काट दिया। देश में और किसी पार्टी ने ऐसी कोई सप्लाई लाइन बनाने के लिए न तो कभी कोई प्रयास किया, न ही उपलब्ध राजनीतिज्ञों के प्रशिक्षण के लिए कभी सोचा।

पार्टी का अर्थ है एक विचारधारा के इर्द-गिर्द निष्ठावान लोगों का संगठन जो जनता से संवाद और सेवा का माध्यम बने, लेकिन अधिकतर पार्टियां केवल चुनाव को ही अपनी कर्मभूमि मानती हैं। चुनावों के बाद उन्हें समझ में नहीं आता कि किया क्या जाए, जबकि चुनाव तो राजनीति का 'बाई-प्रोडक्ट' है। वास्तविक राजनीति तो चुनाव के बाद ही की जाती है। यदि जीतें तो अपने क्षेत्र में अपनी पार्टी का एजेंडा लागू कराने का प्रयास करें और हारें तो राजनीतिक सक्रियता बरकरार रखते हुए सरकार और प्रशासन पर दबाव बनाएं कि निर्वाचन क्षेत्र को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। यह भी देखें कि इन योजनाओं पर सही से अमल हो रहा है या नहीं? अमेठी में स्मृति ईरानी की विजय इसी मॉडल की राजनीति का ज्वलंत उदाहरण है।

आज जनता बेहतर शासन के लिए सत्ताधारी दल बदलती है, लेकिन पार्टियों के पास जो लोग हैं उनमें से अधिकांश को राजनीति का ककहरा भी पता नहीं। इसीलिए दल और सत्ता परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आइएएस और पीसीएस की कठिन परीक्षाओं में सफल होकर आने वाले प्रशासक को कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है तो उन्हें निर्देशित करने वाले राजनीतिक प्रशासकों के लिए दलीय स्तर पर नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं है? देश में इंजीनियर, डॉक्टर और व्यावसायिक प्रबंधन के लिए अनेक प्रशिक्षण संस्थान हैं, लेकिन जो उनके ऊपर बैठते है और जो राजनीतिक प्रबंधन करते हैं उनके लिए कोई शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान क्यों नहीं? वक्त आ गया है कि देश में आइआइटी और आइआइएम के पैटर्न पर भारतीय राजनीतिक प्रबंधन संस्थानों की स्थापना की जाए जिसमें पंचायत से लेकर संसद तक की राजनीति के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि योग्य, समर्पित और कुशल राजनीतिज्ञों की नई पौध और नई फसल तैयार की जा सके। इसका लाभ सभी दलों को मिलेगा और देश में राजनीतिज्ञों की एक नई फसल लहलहाएगी और वैचारिक, प्रक्रियात्मक एवं भाषाई नव-राजनीति का श्रीगणेश होगा।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं)

response@jagran.com

शिक्षा जगत को समर्थ बनाने का समय

प्रो. निरंजन कुमार

शिक्षा पर जीडीपी का छह प्रतिशत खर्च करने की तमाम सिफारिशों के बाद भी यह लक्ष्य अप्राप्य है

मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट एक ऐसे समय प्रस्तुत करने जा रही है जब उच्चतर शिक्षा पर बढ़ते विभिन्न वित्तीय दबावों का मुद्दा सतह पर है। नई शिक्षा नीति के मसौदे में भी उच्चतर शिक्षा के वित्तीय आयामों का उल्लेख है। एक सशक्त राष्ट्र को ऐसी सशक्त शिक्षा व्यवस्था की जरूरत होती है, जो सर्व-सुलभ भी हो। इस सर्व-सुलभ, सशक्त एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रचुर धनराशि की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा के वित्तीय दबावों, चुनौतियों और उनके समाधान पर सम्यक तरीके से पुनर्विचार करने की जरूरत है। सबसे पहले तो शिक्षा खास तौर से उच्च शिक्षा पर सार्वजनिक क्षेत्र का बजट बढ़ाने की आवश्यकता है। 1964-66 के कोठारी आयोग से लेकर अब तक के सभी शिक्षा आयोगों और समितियों ने एक स्वर से शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का छह प्रतिशत खर्च करने की सिफारिश की, लेकिन पिछले लगभग 55 वर्षों में यह लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका, जबकि जिंबाब्वे, कोस्टारिका, किर्गिस्तान से लेकर भूटान जैसे देश शिक्षा पर अपने जीडीपी का 6 से 7.5 प्रतिशत खर्च करते हैं। स्वीडन, फिनलैंड जैसे विकसित देशों में यह व्यय 7 से 7.5 प्रतिशत है। वर्तमान शिक्षा नीति का मसौदा भी छह प्रतिशत के लक्ष्य की अनुशंसा करता है। हालांकि पहले की सिफारिशों से अलग इस बार क्रमिक रूप से यह लक्ष्य हासिल करने की बात की गई है, जो ज्यादा व्यावहारिक लगती है। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि 18 से 30 वर्ष के युवाओं की लगभग 40 करोड़ की तादाद को देखते हुए उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी की भी जरूरत है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी चार तरीकों से हो सकती है। पहला, निजी क्षेत्र में खोले गए कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अन्य तकनीकी संस्थान जिसमें पूर्णतया निजी धन लगा हुआ है और जिनमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं। दूसरे, निजी क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों के पूर्व छात्रों का सहयोग हासिल किया जाए। पश्चिमी देशों में पूर्व छात्र करोड़ों की राशि अपनी मातृ-संस्था को दान के रूप में देते हैं। पिछले साल अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को 1 अरब 40 करोड़ डॉलर का चंदा मिला। अपने यहां भी आइआइटी, आइआइएम आदि में ऐसा कुछ हो रहा है। कुछ महीने पहले खबर थी कि बिट्स पिलानी को एक पूर्व छात्र ने 10 लाख डॉलर का चंदा दिया। हालांकि गैर तकनीकी संस्थाओं में ऐसा होना अपेक्षाकृत मुश्किल है, लेकिन इस तरह की कोशिश तो होनी ही चाहिए। कुछ ही दिन पहले जेएनयू ने फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट के लिए राशि जुटाने के लिए अपने पूर्व छात्रों से संपर्क करना शुरू किया है। तीसरे तरीके के रूप में निजी भागीदारी का भारतीय मॉडल अपनाया जाना चाहिए। भारतीय मानस धार्मिक मानस है। शास्त्रों में उल्लिखित 'विद्या दान, परम दान' जैसे वचन आज भी प्रभावी हैं। शिक्षा के लिए काफी लोग दान के लिए तैयार हैं, बस उन्हें यह विश्वास हो कि उनके पैसे का सदुपयोग होगा। याद कीजिए हमारे यहां धर्मशाला, प्याऊ, स्कूल, अस्पताल खोलने की पुरानी परंपरा रही है। विद्या के लिए दान को प्रोत्साहन देने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक तो दानराशि के उपयोग की जानकारी दानकर्ता को दी जाए और दूसरे, बजट में घोषित कर दिया जाए कि सभी सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं को दिए गए दान इनकम टैक्स अधिनियम के 80जी के तहत टैक्स छूट प्राप्त होंगे।

चौथा तरीका यह है कि हर सरकारी शिक्षण संस्थान में एक दानपेटी रखी जाए जैसा कि विभिन्न धार्मिक संस्थाओं में होता है। इसमें अनाम तरीके से जो चाहे पैसा, जेवर इत्यादि डाल सके। यहां न केवल छोटे दानकर्ता (80जी से परे वाले) भी इससे जुड़ सकते हैं, बल्कि इससे वह धन भी एक तरह से सदुपयोग में आ सकेगा, जिसका हिसाब-किताब नहीं होता।

शिक्षा में वित्त बढ़ाने से जुड़ा एक अन्य कठोर, लेकिन जरूरी कदम यह है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों की फीस बढ़ाई जाए। सरकारी क्षेत्र में जिस कोर्स की फीस 10-20 हजार रुपये होती है, निजी क्षेत्र में वही दो से लेकर चार लाख रुपये के बीच होती है। उदाहरण के लिए कानून की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय या राज्यों के कॉलेजों में कुछ हजार रुपये में हो जाती है वहीं निजी क्षेत्र के शिक्षा संस्थानों में यह फीस लाखों में है। इसका मतलब है कि एक बड़ी तादाद में लोग पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। इस आय वर्ग के लोग सरकारी संस्थाओं में भी पढ़ते हैं। फिर उनसे कम फीस क्यों ली जाए? इसका एक और लाभ यह होगा कि उच्चतर शिक्षा में सिर्फ टाइम पास करने वालों की भीड़ कम होगी और केवल वही लोग आएंगे जो सचमुच गंभीर होंगे। इससे शिक्षा-शोध की गुणवता भी बढ़ेगी। यह मानव-मनोविज्ञान है कि जो चीज मुफ्त या कम पैसे अथवा आसानी से मिल जाती है उसका मूल्य नहीं समझा जाता। जरूरी है कि सरकारी फीस बढ़ाकर निजी क्षेत्र के 20 प्रतिशत तक या कम से कम दोगुनी-तिगुनी कर दी जाए। अमेरिका में सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों की फीस में कोई खास अंतर नहीं होता। यह भी जरूरी है कि कमजोर और निम्न आय वाले तबके के लिए शून्य से लेकर 3-4 प्रतिशत पर शैक्षणिक लोन आसानी से उपलब्ध हो, जिसे वे रोजगार मिलने के बाद ही चुकाएं। मानव संसाधन मंत्रालय को एजुकेशनल लोन स्कीम में यथोचित परिवर्तन करना होगा। टेक्नोलॉजी के इस दौर में लोनधारकों को ट्रैक करना भी मुश्किल नहीं है।

शिक्षा के वित्त का अंतिम पहलू निजी शिक्षण संस्थानों की आसमान छूती फीस का है। शिक्षण एक चैरिटेबल कार्य है। इससे मुनाफा नहीं कमाया जा सकता, लेकिन तरह-तरह के हथकंडों से निजी संस्थानों में खूब मुनाफाखोरी हो रही है। कुछ को छोड़कर निजी क्षेत्र के अधिकांश संस्थान या तो नेताओं द्वारा चलाए जा रहे हैं या उनमें उनका पैसा लगा हुआ है। उनके दबाव एवं प्रभाव से अनेक छेद वाली ऐसी ढीली-ढाली नीतियां बनी हुई हैं, जिनका दुरुपयोग किया जाता है। दूसरी तरफ इन संस्थानों का ठीक से ऑडिट भी नहीं होता। निजी शिक्षण संस्थानों का उचित विनियमन और फीस की एक सम्यक सीमा निर्धारित करना जरूरी है। समय आ गया है कि शिक्षा के वित्तीय आयामों को दुरुस्त किया जाए।

(लेखक दिल्ली विवि में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सुख

जिस तरह ट्रेडमिल पर व्यक्ति लगातार भागते रहते हैं, उसी तरह सुख की ट्रेडमिल पर भी व्यक्ति लगातार भागते ही रहते हैं। आप एक घर खरीदना चाहते हैं और मानते हैं कि इससे आप सुखी हो जाएंगे। आपको एक बड़ा सा घर मिल जाता है। घर पाते ही आप खुशी और सुख से चहकने लगते हैं, पर प्रतिदिन यह खुशी कम होती जाती है और आपके मन में दूसरे सुख को पाने की इच्छा बलवती होने लगती है। यह स्थिति मनोवैज्ञानिक रूप से 'सुख का अनुकूलन' कहलाती है। इस चक्र को ही सुख की ट्रेडमिल कहा जाता है। सुख की ट्रेडमिल यह स्पष्ट करती है कि धन-दौलत, शोहरत और उच्च पद को प्राप्त करने के बाद भी कामना कभी खत्म नहीं होती, बल्कि वह पहले से अधिक प्राप्ति की लालसा में लग जाती है। इस तरह यह चक्र व्यक्ति के अंत के साथ ही समाप्त होता है। क्या ऐसा संभव है कि इस ट्रेडमिल पर चढ़े बिना जीवन में दीर्घकालीन सुख और खुशी को प्राप्त किया जा सके। यदि व्यक्ति अपने जीवन में कुछ प्राथमिकताएं निश्चित कर ले तो वह दीर्घकालीन सुख का अनुभव करके सुख के अनुकूलन को न्यूनतम कर सकता है।

जैसे व्यक्ति को पर्याप्त रुपये कमाने के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि रुपये का सुख से केवल उतना ही संबंध रहता है जितना कि व्यक्ति का आराम से गुजारा चल जाए। वास्तव में जीवन में सुख के लिए जो एकमात्र चीज सचमुच मायने रखती है, वह है दूसरे लोगों के साथ आपके संबंध। मधुर और दोस्ताना संबंध व्यक्ति को न केवल प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष करने का बल देते हैं, बल्कि हार को भी सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। अपने स्वास्थ्य और मन को बेहतर बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि सुख का अनुभव तभी संभव होता है जब व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ होता है। तनाव एवं ईर्ष्या को हटा दें, क्योंकि तनाव और ईर्ष्या ऐसे छोटे-छोटे कारण हैं जो घुन की तरह व्यक्ति को खा जाते हैं।

जाहिर है सुख की ट्रेडमिल पर भागने से मन की शांति नहीं मिल सकती। इससे उतर कर भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति की जगह अनुभवों और अहसास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये अनुभव और अहसास ही व्यक्ति की दीर्घकालीन सुख की गारंटी हैं।

रेनू सैनी

बच्चे और रियलिटी शो

मनीषा सिंह

चैनलों को छोटे बच्चों को लेकर डांस प्रतियोगिता कराने से पहले उनके मानसिक और शारीरिक विकास को ध्यान में रखना चाहिए

भारतीय टेलीविजन के लिए नाचने, गाने और कई किस्मों के करतब दिखाने का दावा करने वाले रियलिटी शो नए नहीं हैं। रियलिटी शो के लिए यह सलाह भी नई नहीं है कि उनमें शामिल होने वाले बच्चों पर ज्यादती न करें। यानी न उन्हें कोई बेमिसाल करतब दिखाने को बाध्य करें और न ही उन्हें बड़ों की तरह परफॉर्म करने पर विवश करें, लेकिन इन सलाहों को दरकिनार कर यही सब कुछ होता रहा है। शायद इसी के चलते सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इधर यह एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है कि निजी टीवी चैनल नृत्य आधारित रियलिटी शो में छोटे बच्चों की डांस प्रतियोगिताएं कराने में संयम बरतें। मंत्रालय के मुताबिक टीवी के ज्यादातर रियलिटी शो में जिन बच्चों को नृत्य करते दिखाया जा रहा है, मूल रूप से वह वयस्कों द्वारा अन्य मनोरंजन के साधनों को साधने के लिए किए गए होते हैं, जो कि वयस्कों के लिए विचारोत्तेजक और उम्र के अनुकूल होते हैं। ऐसे में इन नृत्यों को छोटे बच्चों से करवाने पर उनके मानसिक और संरचनात्मक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

यूं यह पहला मौका नहीं है जब ऐसे शो पर पाबंदी लगाने या उनके संचालन के संबंध में कड़े नियम-कायदों की बात उठ रही है। कई रियलिटी शो में बच्चों के साथ हुए तमाम हादसों के मद्देनजर बाल अधिकारों की शीर्ष संस्था नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) 2011 में टीवी सीरियलों, रियलिटी शो और विज्ञापनों में बच्चों की भागीदारी को लेकर दिशानिर्देश जारी कर चुकी है। इन निर्देशों के मुताबिक किसी शो में बच्चों को ऐसे रोल या मंचन में नहीं शामिल किया जाना चाहिए, जिनमें किसी वजह से उन्हें तनाव या शर्मिंदगी का सामना करना पड़े।

बाल आयोग ने अपने आकलन में पाया था कि ज्यादातर रियलिटी शो में बच्चे ऐसे डायलॉग बोलते दिखते हैं, जो उनकी उम्र के हिसाब से सही नहीं होते हैं। इन्हीं दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया था कि बच्चों की भागीदारी वाले टीवी के रियलिटी शो प्रतिस्पर्धा पर आधारित नहीं होने चाहिए, लेकिन इस निर्देश की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। आज शायद ही कोई मनोरंजन टीवी चैनल ऐसा होगा, जिनमें प्रतियोगिता से बाहर कर दिए जाने का नियम बनाकर प्रतिस्पर्धा न कराई जा रही हो और उनका शोषण न किया जा रहा हो।

इन टीवी शो में भाग लेने वाले बच्चों को बचपन में ही बड़ों जैसी प्रतिस्पर्धा में धकेलने का खामियाजा इस रूप में सामने आता है कि वे बच्चे हार को बड़ी संजीदगी से लेने लगते हैं और कई बार अवसादग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे शो में मिलने वाली हार बच्चों का मनोबल तोड़ती है जो उनके व्यक्तित्व पर नकारात्मक असर डालती है। बच्चों पर अपनी महत्वाकांक्षा थोपने वाले मां-बाप को न सिर्फ ऐसे शो में होने वाले शोषण को लेकर सजग होना होगा, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि शो खत्म होने के बाद उनसे बाहर आने वालों बच्चों का भविष्य क्या है। पिछले दो दशकों में सैकड़ों रियलिटी शो से तमाम बच्चे विजेता बनकर निकले हैं, लेकिन उनमें से कितनों ने कोई मुकाम हासिल किया है इस पर भी गौर करने की जरूरत है।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

एक कृत्रिम रचना है पाकिस्तान

ब्रिगेडियर आरपी सिंह का लेख 'बिखराव की ओर बढ़ता पाकिस्तान' (3 जुलाई) उस वास्तविकता को रेखांकित करता है, जो इस कृत्रिम मुल्क को अपने स्वाभाविक विनाश की ओर धकेल रही है। बलूच, सिंधी, पख्तून, गिलगित-बाल्टिस्तानी ही नहीं, शिया, सरायकी तथा मुहाजिर वे समुदाय हैं, जो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी एकरूप नहीं हो पाए। ये तमाम लोग, जिनकी जनसंख्या 50 प्रतिशत से थोड़ी ही कम बैठती है, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। और इस अलगाव की जड़ में पाकिस्तानी हुक्मरानों की वे उत्पीड़न वाली नीतियां हैं, जो पंजाबी सुन्नी प्रभाव में क्रियान्वित की जाती रही हैं। सेना द्वारा बलूचों, पख्तूनों, मुहाजिरों के रक्तिम दमन के अमानवीय किस्से अब तो दुनिया में आम हो चुके हैं। यदि भारत इन लोगों के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करता चले तो शीघ्र ही उत्पीड़क पाकिस्तान घुटने टेकने को विवश होगा, इसमें संदेह नहीं है।

अजय मित्तल, मेरठ

प्रशिक्षित हो पुलिस

दिल्ली को सांप्रदायिकता की आग में झुलसाने की नाकाम कोशिशों के पीछे कौन है और क्यों की जा रही है? एक यक्ष प्रश्न है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मुखर्जी नगर क्षेत्र में सिख समुदाय को भड़काने की कोशिश की गई और अब चांदनी चौक के हौजकाजी इलाके में पार्किंग की जिद को लेकर दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ कर घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। दोनों ही मामलों में पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। मुखर्जी नगर की घटना में पुलिस ने पेशेवर तरीके से व्यवहार नहीं किया, जिस कारण तनाव बढ़ा।

मेलबाक्स

हौजकाजी में भी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई नहीं की, अन्यथा मामला इतना नहीं बढ़ता। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को विशेष प्रशिक्षण की जरूरत है।

दीपक गौतम, सोनीपत

नोटों की सुरक्षा

भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट को सुरक्षित रखने के लिए इन पर पिन लगाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बावजूद बहुत से लोग नोटों पर पेन से कुछ न कुछ लिख देते हैं, जिससे नोट खराब लगते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को चाहिए कि इस संदर्भ में आम जनता को जागृत करने के लिए किसी एक दिन नोट को साफ सुथरा बनाने का दिवस मनाए। इस दिन विचार गोष्ठी आदि के जरिए आम जनता को नोटों को सुरक्षित रखने के प्रति जागरूक किया जाए।

विजय कुमार धनिया, नई दिल्ली

बैट वाले नेता जी

संसद और विधानसभाओं में नेता कानून बनाते हैं और नौकरशाह उन्हें लागू करते हैं। मगर अभी कुछ दिन पूर्व मध्यप्रदेश में एक नेता ने सरे आम नगर निगम अधिकारी को ही क्रिकेट बैट से पीट डाला, जबकि वह अधिकारी जनहित में अपने कर्तव्य पर थे। उसके बाद एक अन्य नेता भी ऐसे ही अपने कंधे पर बैट लिए घूमते दिखाई दिए। पीटने वाले नेता को अपने क्षेत्र के वोट की कुछ ज्यादा ही चिंता थी और दूसरी ओर बेचारा निगम अधिकारी भी जन सुरक्षा में अपने कार्य पर था। माना कि अपने हिसाब से ये दोनों ही सही थे मगर इस तरह की हिंसा का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इससे इन दोनों की ही छवि धूमिल हुई है। इसलिए ऐसे गंभीर मसलों पर सदा शांति और समन्वय से ही आगे बढ़ना चाहिए।

वेद मामूरपुर, नरेला

प्रतिभा के साथ न्याय हो

हाल ही में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू हुआ। इसके लिए आय संबंधी कुछ शर्तें लगाई गई हैं। जिस प्रकार से सामान्य वर्ग में आरक्षण का आधार आर्थिक रखा गया है, ठीक उसी प्रकार से शासन अन्य वर्गों में भी आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करे। दूसरी बात, नौकरी/शिक्षा/प्रवेश आदि में आरक्षण केवल साधनों-सुविधाओं तक ही सीमित होना चाहिए। किसी भी स्तर पर चयन का एकमात्र मापदंड केवल योग्यता होना चाहिए जिसमें धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से ही देश की प्रतिभा के साथ न्याय होगा। आरक्षण नीति में संशोधन और इसकी समयानुसार समीक्षा अत्यावश्यक है, अन्यथा इसका मूल उद्देश्य अधूरा ही रहेगा।

sonimohit895@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

650 ग्लेशियर हैं समस्त हिमालय पर्वतमाला के दायरे में जिनमें करीब 60 करोड़ टन बर्फ जमी हुई है। इस ग्लेशियर क्षेत्र को तीसरे ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बाद धरती का यह तीसरा बड़ा क्षेत्र है जहां इतनी मात्रा में बर्फ जमी है।

आजकल

ओजोन की रक्षा से ही सुरक्षित होंगे हम

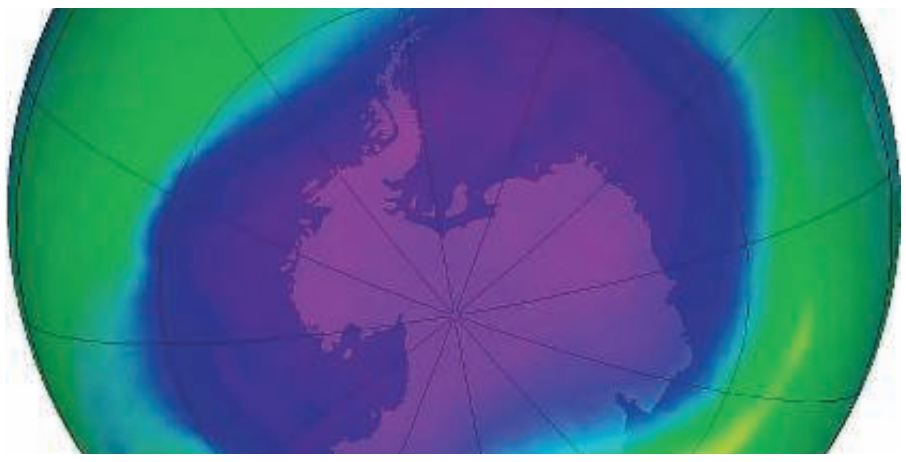

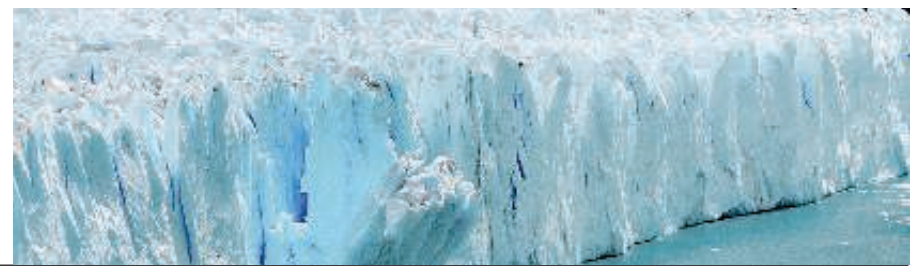

समूचा उत्तर भारत भयावह गर्मी की चपेट में है। हालांकि पिछले दो-तीन दिनों से छिटपुट तौर पर मानसून ने दस्तक जरूर दी है, लेकिन जून माह में तापमान कई जगहों पर 48 डिग्री तक चला गया था। राजस्थान में भीषण लू चलने का बीते 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बिहार में महज सप्ताह भर में 200 से अधिक लोगों की मौत होने की खबरें आई हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार बीते माह देश के करीब 35 जिले तापमान में सामान्य से चार-पांच डिग्री से भी अधिक की बढ़ोतरी के चलते भयंकर गर्मी की चपेट में आए

ज्ञानेंद्र रावत
लेखक एवं पर्यावरणविद्

पिछले दो माह से लगभग समूचा उत्तर भारत भीषण गर्मी से त्रस्त है। भीषण गर्मी के चलते होने वाली बीमारियों से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस गर्मी और चिलचिलाती जानलेवा धूप का दुष्परिणाम ओजोन प्रदूषण में बढ़ोतरी के रूप में सामने आया है। विडंबना यह कि एक ओर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण पर काम करने वाली संस्था 'सफर' दिल्ली एनसीआर सहित समीपस्थ राज्यों में हवा में ओजोन की मौजूदगी का दावा कर रही है। वहीं हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इसके विपरीत यह दावा कर रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी भी खराब नहीं जितनी मीडिया बता रहा है। उनका कहना है कि मीडिया ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है जिससे यह लग रहा है कि प्रदूषण की वजह से लाखों लोगों की मौत हो रही है। यह हमारे देश के कर्णधारों की सोच का एक सबूत भी है। यह तब है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन स्पष्ट रूप से कह चुका है कि भारत और चीन में वायु प्रदूषण का स्तर अमेरिका से कई गुना अधिक है। हमारे देश के मौजूदा हालात बयां कर रहे हैं कि इस गर्मी से मैदान ही नहीं, पहाड़ भी अछूते नहीं हैं। दिल्ली और उसके समीप के इलाकों की हवा में पीएम 10 और पीएम 2.5 से भी ज्यादा खतरनाक प्रदूषक कण यानी ओजोन की मात्रा रिकार्ड की जा रही है। यह खतरनाक तो है ही, साथ ही सतह पर पाए जाने वाले ओजोन कण मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। 'सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट' की मानें तो चिलचिलाती धूप की किरणें वाहनों से निकलने वाले धुएं से प्रतिक्रिया करके ओजोन के प्रदूषक तत्व बनाते हैं। यह स्थिति भयावहता की ओर इशारा करती है।

यदि आइआइएम अहमदाबाद की रिपोर्ट की मानें तो देश के उत्तरी राज्यों में आने वाले दिनों में भीषण गर्म हवाओं का खतरा बढ़ जाएगा। बीते 50 सालों में लू चलने वाले दिनों की संख्या और इससे मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। 'क्लाइमेट ट्रेंड' की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के चलते तेज गरम हवाएं जो पहले अप्रैल महीने में चलती थीं, अब मार्च माह में ही चलनी शुरू हो गई हैं। जाहिर है यह सब जलवायु परिवर्तन का नतीजा है।

जलवायु में भीषण परिवर्तन मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि बिजलीघरों, फैक्ट्रियों और वाहनों में जीवाष्म ईंधनों के जलने से पैदा होने वाली ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैसों का पर्यावरण में फैलाव तथा जंगलों की बेहिसाब कटाई। मालूम हो कि वृक्ष कार्बन डाईऑक्साइड को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वे कार्बन डाईऑक्साइड भी उत्पन्न करते हैं, पर सोखने और उत्पन्न करने की निरंतर प्रक्रिया से वे कार्बन डाईऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में सहयोग देते हैं। वृक्षों के अभाव में जितनी भी कार्बन डाईऑक्साइड पर्यावरण में छोड़ी जाती है, वह वहीं जमा होती रहती है और उसकी बढ़ोतरी तापमान में वृद्धि करती है और मौसम का मिजाज दिन-ब-दिन गर्म करती है। यह गर्माहट यदि इसी तरह बढ़ती रही और पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की बर्फीली चादरें यदि पिघलने लगीं, तो समुद्र की सतह ऊपर उठ जाएगी और अनेक छोटे द्वीप जो समुद्र की ऊपरी सतह से कुछ ही ऊंचे हैं, समुद्र में डूब जाएंगे। साथ ही वातावरण में पहले की तुलना में कार्बन डाईऑक्साइड का संकेद्रण 30 प्रतिशत से ज्यादा हुआ है, जो मानवीय स्वास्थ्य के लिए कई तरह से घातक साबित हो सकता है।

> बढ़ती गर्मी के लिए प्रदूषण भी जिम्मेदार है, इसलिए प्रदूषण का स्तर कम करने पर जोर देना आवश्यक है

जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर ओजोन परत पर पड़ा है जिससे उसके लुप्त होने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में लगभग 25 किमी की ऊंचाई पर फैली ओजोन परत सूर्य की किरणों के खतरनाक अल्ट्रावायलेट हिस्से से पृथ्वी के जीवन की रक्षा करती है। लेकिन यही ओजोन गैस जब धरती के वायुमंडल में आ जाती है तो हमारे लिए जहरीली गैस के रूप में काम करती है। यदि हवा में ओजोन का स्तर काफी अधिक हो जाए तो बेहोशी और दम घुटने की स्थिति आ सकती है। मौसम के बदलाव से कहीं प्रचंड गर्मी तो कहीं प्रचंड सर्दी ने मानवीय स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित किया है। गर्मी बढ़ने से हवा में प्रदूषण के रूप में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड व नाइट्रोजन डाईऑक्साइड जैसी गैसों के तत्व टूट कर हवा में मौजूद ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं। इससे ओजोन गैस बनती है। हवा में ओजोन का स्तर बढ़ने से उसकी गुणवत्ता खराब होती है। तब अन्य प्रदूषक तत्वों की अपेक्षा ओजोन आसानी से शरीर में प्रवेश कर अंगों को प्रभावित करती है। प्रचंड गर्मी ओजोन के रूप में नई मुश्किलें पैदा कर रही है जो हवा में ओजोन के स्तर बढ़ने से पैदा हुई है। यह समस्या सांस से जुड़ी बीमारियां, उल्टी आने, चक्कर, थकान बढ़ने और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की मुख्य वजह साबित हो रही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार जिस रफ्तार से ओजोन परत की क्षति हो रही है, उससे प्रत्येक वर्ष त्वचा कैंसर के तीन लाख अतिरिक्त रोगी पैदा होंगे और फसलों को नुकसान पहुंचेगा।

वर्ष 1988 में मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में इस संबंध में एक समझौता किया गया था जिसमें ओजोन के लिए खतरनाक गैसों के प्रयोग एवं रिसाव में 90 फीसद की कटौती का प्रस्ताव था, लेकिन इससे समस्या का समाधान नजर नहीं आता दिख रहा है। सारा दोष उपभोगवादी संस्कृति का है जिसने प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन, शोषण व बर्बादी को जन्म दिया। उपभोगवादी संस्कृति के विकास व प्रसार का मनोवैज्ञानिक पहलू भी है जो इसके अर्थशास्त्र, राजनीति व समाजशास्त्र से अधिक महत्वपूर्ण है। आज भौतिक समृद्धि ही सम्माननीय बन गई है। सोच और व्यवहार की इस क्रिया को इंसान यदि स्वयं नहीं बदलेगा, तो एक दिन प्रकृति उसे बदलने पर बाध्य कर देगी। समय की मांग है कि हम उपभोगवादी प्रवृत्ति को त्यागकर पृथ्वी को शस्य, श्यामला और समस्त चराचर जीवों के लिए सुरक्षित बनाएं, तभी ओजोन की रक्षा संभव है। और ओजोन की रक्षा से ही हमारी रक्षा होगी।

संकट में ग्लेशियर का अस्तित्व

सूची दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की गंभीरता को समझ चुकी है। अब यदि इस मामले में देरी की गई तो मानव जीवन का अस्तित्व मिट जाएगा। वैज्ञानिक बरसों से चेतावनी दे रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते समूची दुनिया में ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हिमालय पर्वतमाला के दायरे में आने वाले अनेक विशाल ग्लेशियर बीते पांच दशकों से लगातार गर्म हो रहे हैं। इससे हिमखंड तेजी से पिघल रहे हैं। इस तथ्य को चीन की एकेडेमी ऑफ साइंसेज, हुनान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड माउंट कुमोलाग्मा स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन सेंटर ने भी काफी पहले प्रमाणित कर दिया था। यह भी सच है कि वह चाहे हिमालय के ग्लेशियर हों या तिब्बत के या फिर आर्कटिक ही क्यों न हो, वहां बर्फ के पिघलने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। कई हालिया अध्ययन इस बात का सबूत हैं कि बढ़ते तापमान के चलते हिमालय के तकरीबन 650 से अधिक ग्लेशियरों पर अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। उनकी पिघलने की रफ्तार दोगुनी हो गई है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ अर्थ के शोधकर्ताओं ने उपग्रह से लिए गए बीते चार दशकों के चित्रों के आधार पर किए शोध में यह खुलासा किया है। उसके अनुसार भारत, नेपाल, भूटान और चीन में तकरीबन 2,000 वर्ग किमी के इलाके में फैले 650 से ज्यादा ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के चलते लगातार पिघल रहे हैं। साल 1975 से 2016 के बीच हिमालयी क्षेत्र के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसका दुष्परिणाम ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के रूप में सामने आया। शोध रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1975 से 2000 के बीच जो ग्लेशियर हर साल 10 इंच की दर से पिघल रहे थे, वे वर्ष 2000 से 2016 के बीच हर साल 20 इंच की दर से पिघलने लगे।

हिमालय के इन 650 ग्लेशियर में करीब 60 करोड़ टन बर्फ जमी हुई है। इन ग्लेशियर क्षेत्र को तीसरे ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। कारण उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बाद यह तीसरा बड़ा इलाका है जहां इतनी बर्फ जमी है। इन ग्लेशियरों से निकली नदियों से भारत, चीन, नेपाल और भूटान की करीब 80 करोड़ आबादी का जीवन निर्भर है। पेयजलापूर्ति, सिंचाई और बिजली उत्पादन में इन नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि इन ग्लेशियरों का अस्तित्व खत्म हो गया तो 80 करोड़ आबादी का जीना मुहाल हो जाएगा। चिंता की बात यह कि यहां के कुछ ग्लेशियर सालाना पांच मीटर की दर से पिघल रहे हैं। कम ऊंचाई वाले ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार में तेजी आई है। इससे कृत्रिम झीलों के निर्माण में बढ़ोतरी हुई है। इन झीलों के टूटने से बाढ़ की आशंका बनी रहती है। बीते बरसों में डॉ. मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में चिंता जाहिर की थी कि हिमालयी क्षेत्र के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इस समिति ने सरकार को सिफारिश भी की थी कि हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के व्यापक अध्ययन के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन और आधारभूत ढांचा मुहैया कराए जाने की आवश्यकता है।

हिमालय के करीब 75 फीसद ग्लेशियर पिघल कर झरने और झीलों का रूप ले चुके हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सेटेलाइट चित्रों के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि भी कर चुका है। इस क्षेत्र में बीते 15-20 वर्षों में 3.75 किमी की बर्फ पिघल चुकी है। जंगलों में लगी आग से निकले धुएं और कार्बन से ग्लेशियरों पर एक महीन सी काली परत पड़ रही है। यह कार्बन हिमालय से निकलने वाली नदियों के पानी के साथ बहकर हमारे घरों तक पहुंच रहा है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2035 तक हिमालय के सभी ग्लेशियर और आगामी दो सदी में आइसलैंड के सभी ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के चलते खत्म हो सकते हैं। चीन के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि तिब्बत के ग्लेशियरों के पिघलने की दर तेज हो गई है। धरती पर ताजे पानी के सबसे बड़े स्रोत ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के विश्वसनीय सूचक माने जाते हैं।

जहां तक आर्कटिक महासागर का सवाल है तो वहां यदि इसी रफ्तार से बर्फ पिघलती रही तो आगामी चार दशकों में यह इलाका बर्फ रहित हो जाएगा। मालूम हो कि आर्कटिक धरती पर पैदा होने वाले कार्बन का एक बड़ा हिस्सा सोखता है। ग्लेशियर और हिमखंडों के पिघलने का तात्पर्य यह होगा कि आर्कटिक बड़ी मात्रा में कार्बन डाईऑक्साइड अवशोषित करने की अपनी क्षमता खो देगा, लिहाजा धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है।

खरी-खरी

फॉर्म का वापस आ जाना

मृदुल कश्यप

लगातार दो चौके लगाते ही सीधा प्रसारण कर रहे टीवी चैनल पर एक क्रिकेट विशेषज्ञ ने घोषणा कर दी, 'लगता है उनका फॉर्म वापस आ गया है।' ये महज चार शब्द नहीं थे, बल्कि चार एटम बम थे। इन्हें सिर्फ सुनने भर से उनके प्रशंसकों के दिलों में जबरदस्त विस्फोट हो गया और वे झुंड बनाकर सड़कों पर निकल पड़े। जो लोग बाहर नहीं निकले, वे अपने घरों से ही सोशल मीडिया पर टूट पड़े। देखते ही देखते प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। जब तक यह आशंका थी कि वह खिलाड़ी बिना फॉर्म के ही खेल रहा है, तब तक पूरे देश के मन में धुकुर-धुकुर मची थी। वह जब पैड पहन कर मैदान में उतरता, तो पूरा देश बेचैनी महसूस करने लगता। उसके प्रशंसक अपने अपने देवताओं के सामने डट जाते। पूरे देश में मन्नतों का दौर चालू हो जाता था। अब जबकि उनका फॉर्म लौट आया है, पूरे देश ने चैन की सांस ली है।

अक्सर देखा गया है कि जब टीम की चयन प्रक्रिया चल रही होती है, तब चर्चा होती है कि फलाना खिलाड़ी फॉर्म में नहीं चल रहा। फिर बाद में जाने कैसे बिना फॉर्म वाले उसी खिलाड़ी का चयन हो जाता है। ऐसा अक्सर नामी-गिरामी खिलाड़ियों के साथ होता है। चयन के बाद देशवासियों के मन में यह चिंता सतत बनी रहती है कि फलां खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है। तब भी एक उम्मीद बनी रहती है कि शायद खेलते-खेलते उसका फॉर्म वापस आ जाए। कब आएगा, यह तो नहीं कह सकते पर जब शून्य पर आउट होने वाला खिलाड़ी दहाई के अंक को छूने लगता है, तो यह तय हो जाता है कि फॉर्म प्राप्ति के करीब पहुंच रहा है और संभावना है कि जल्द ही लौटेगा।

देश वासियों को भले ही यह डर लगता रहता है कि खिलाड़ी सिर पर कफन बांध कर बिना फॉर्म के ही मैदान में उतरा है, जबकि खिलाड़ी इस बात की परवाह किए बिना अपने मजे में खेलता है। उसको पता है, वह अच्छा खेले न खेले, मैच के बाद टीवी पर साबुन-तेल बेचकर बढ़िया पैसा कूट लेगा।

क्रिकेट में खिलाड़ी तो महज हाड़-मांस का पुतला होता है, उसका प्राण तो उसका फॉर्म है। ये बात और है कि वह मैदान के फॉर्म से ज्यादा उस कागजी फॉर्म को तवज्जो देता है, जो उसने मल्टीनेशनल कंपनी के साथ करार करते वक्त भरा था। खेल तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, असल खेल तो वह खेल के बहाने खेल की पीठ के पीछे खेलता है।

ट्वीट-ट्वीट

कश्मीरी अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी और असरफ सेहरई आदि आम कश्मीरियों को वर्षों से मूर्ख बनाते आ रहे हैं। कश्मीर के 112 अलगाववादियों के 220 सगे-संबंधी विदेशों में शांति से रह रहे हैं। आखिर इनमें से किसी ने भी कश्मीर में रहना और पत्थरबाजी में शामिल होना या हुर्रियत में शामिल होना पसंद क्यों नहीं किया?

आदित्य राज कौल@AdityaRajKaul

कोई अधिकारी पर बल्ला चला रहा है... कोई कीचड़ उड़ेल रहा है...!! आकाश विजयवर्गीय हों या नीतेश राणे, ऐसे नेता-पुत्रों को जेल की हवा खिलानी जरूरी है, तभी होश ठिकाने आएंगे।

मानक गुप्ता@manakgupta

आर्थिक सर्वे-2019 देश की अर्थव्यवस्था की एक निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है और आर्थिक मोर्चे पर निष्क्रिय पड़ी सत्तारूढ़ पार्टी को जगाने के लिए सार्थक प्रयास करता नहीं दिख रहा है।

रणदीप सिंह सुरजेवाला@rssurjewala

राज्यनामा

झारखंड

कानून को ताक पर रखकर जमीन की हेराफेरी

झारखंड में जमीन को लेकर अक्सर विवाद होता है। इसकी एक बड़ी वजह है दो पुराने जमीन संबंधी कानून- छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम और संताल परगना काश्तकारी अधिनियम। इस कानून के मुताबिक स्थानीय समुदाय के लोगों की जमीन की बिक्री थाना क्षेत्र से बाहर प्रतिबंधित है। इसके अलावा गैर जनजातीय समुदाय का व्यक्ति इनकी जमीन को नहीं खरीद सकता है। लेकिन इन कानूनों के रहने के बावजूद इसका बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ है। जाहिर है, बगैर प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत के यह संभव नहीं होगा। वर्षों तक जमीन की लूट होती रही। आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े जनजातीय समुदाय ने इसका विरोध भी किया, लेकिन अलग-अलग समय में कानून में ढिलाई देकर जमीन माफियाओं ने उल्लू सीधे किए। अब इन दो कानूनों से इतर सरकारी जमीन की लूट भी बड़े पैमाने पर हो रही है। राज्य के कुछ वरीय अफसरों पर भी इससे संबंधित मामले चल रहे हैं। ताजा वाकया हाल ही में पुलिस महानिदेशक के पद से रिटायर हुए भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी डीके पांडेय से जुड़ा है। दरअसल प्रशासनिक जांच में यह सामने आया है कि इस अधिकारी की पत्नी ने राजधानी में 50 डिसमिल से ज्यादा जमीन गैर-कानूनी तरीके से खरीदी। इस जमीन की प्रकृति गैर मजरूआ थी, जिसकी खरीद-बिक्री नहीं की जा सकती है। इसके बावजूद जमीन माफियाओं ने इस जमीन की प्रकृति बदलकर रैयती कर दी और इनकी पत्नी के नाम से जमाबंदी भी हो गई। यही नहीं, जमीन पर आलीशान कोठी का भी निर्माण बगैर नक्शा पास कराए हो गया। जाहिर है इतना बड़ा घालमेल कोई अकेले नहीं कर सकता। झारखंड में जमीन के खेल में बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत का यह उदाहरण है। यह प्रमाणित करता है कि जमीन का हेरफेर कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध तरीके से हुई जमाबंदी को रद किया जाएगा। प्रशासन ने इस बाबत नोटिस भी जारी कर दिया है। अवैध निर्माण को तोड़ने का भी दावा किया जा रहा है। सवाल उठता है कि तंत्र बाद में सक्रिय

क्यों होता है? जमीन की बड़े पैमाने पर लूट में अगर आला अधिकारी लिप्त हैं तो देर-सवेर लीपापोती होने की भी संभावना है। ऐसे में सख्त कार्रवाई कर लोगों को यह विश्वास दिलाना होगा कि कानून सबके लिए बराबर है। आदिवासियों की जमीन संरक्षित करने के लिए बने कानून का भी सख्ती से अनुपालन आवश्यक है। इस जुड़े कोर्ट में चल रहे मामलों का भी स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, ताकि दोषी सामने आएं।

खंड-खंड राजद : लोकसभा चुनाव में औंधे मुंह गिरी लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल का संगठन अब खंड-खंड हो रहा है। झारखंड में दल के दो टुकड़े हो चुके हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव के ऐन पहले झारखंड प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा का दामन थाम लिया था। राष्ट्रीय जनता दल की ऐसी स्थिति पहले नहीं थी। विधानसभा में कभी पार्टी के पांच विधायक हुआ करते थे। यहां से सांसद भी चुनकर लोकसभा तक पहुंचे हैं, लेकिन धीरे-धीरे व्यक्तिवादी राजनीति पूरी तरह संगठन पर हावी हो गई। गणेश परिक्रमा करने वाले नेताओं को संगठन में जगह मिली। सबसे बड़ा झटका चुनाव के ऐन पहले प्रदेश अध्यक्ष का भाजपा में शामिल होना रहा। पहले लोगों को इस पर सहज विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद की विश्वासपात्र रही हैं। लेकिन संगठन की ढीली होती पकड़ के कारण उन्होंने सुरक्षित रास्ता तलाश किया। इसके बाद गौतम सागर राणा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन बाद में उन्हें चलता कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपना अलग धड़ा बना लिया है। अब कार्यालय पर कब्जे को लेकर भी नए सिरे से रस्साकशी शुरू हुई है। दरअसल लालू प्रसाद का जेल में रहना राष्ट्रीय जनता दल के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। बिहार में पार्टी की जड़ें गहरी हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में करारा झटका लगा है। झारखंड में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होंगे। यदि स्थिति नहीं सुधरी तो बिहार से सटे झारखंड के विधानसभा सीटों पर पार्टी के प्रदर्शन पर सीधा असर पड़ेगा। लालू प्रसाद के उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई का भी संगठन पर सीधा असर पड़ रहा है। जेल में रहने के कारण उनका संगठन पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रह गया है। उनके दोनों पुत्रों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है। रह-रहकर यह उजागर भी होता है। संगठन में सक्रिय प्रमुख नेता इसके कारण उदासीन हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में झारखंड में संगठन को मुख्यधारा में लाना एक बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय जनता दल के ज्यादातर प्रमुख नेता पाला बदल चुके हैं या फिर इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में कोई करिश्मा ही अलग-अलग गुटों में बंटे राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य बेहतर कर सकता है।

जागरण जनमत कल का परिणाम

राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर सही किया है?

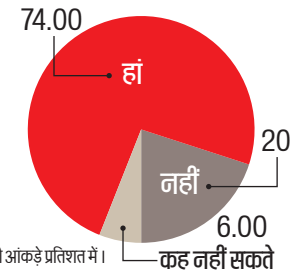

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

केंद्र ने पश्चिम बंगाल का नाम बांग्ला करने की ममता सरकार की मांग ठुकरा कर सही किया है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

ट्विटर पर युवराज के फूट रहे उद्गार,
उन्हें मनाने के लिए बहे अश्रु की धार।
बहे अश्रु की धार चल रही मान-मनौवल,
ग्रैंड ओल्ड दल बीच न कोई दिखता अव्वल।
साफ दिख रहे आज हाथ से उड़ते तीतर,
राहुल ने इस बार किया है जबसे ट्वीटर।

- ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

स्वावलंबन का आधार व्यावसायिक शिक्षा

डॉ. दर्शनी प्रिय
स्वतंत्र टिप्पणीकार

भारत जैसे देश में जहां बड़ी संख्या में युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं वहां उन्हें व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जाना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में छात्रों के स्वावलंबन की नींव व्यावसायिक शिक्षा के आधार पर ही टिकी है

व्यावसायिक शिक्षा जीविकोपार्जन के मूल में है। ज्ञान-आधारित शिक्षा से इतर व्यावसायिक शिक्षा की मांग हाल के वर्षों में बढ़ी है। ज्ञान की विविधता के साथ जीविका आधारित शिक्षा के जरिये भविष्य को सुरक्षित रखना है तो व्यावसायिक शिक्षा के मूल मंत्र को समझना होगा। रोजगारपरक व पेशेवर शिक्षा के बिना आज अर्थोपार्जन की राह कठिन है। नई शिक्षा नीति के प्रारूप में व्यावसायिक या रोजगारपरक शिक्षा पर खासा जोर दिया गया है जो इस बात की पुष्टि करता है कि रोजगारपरक शिक्षा के बूते ही एक सशक्त और स्वावलंबी पीढ़ी तैयार की जा सकती है। लेकिन चिंतनीय है कि हमारे यहां परंपरागत शिक्षा से इतर कभी किसी दूसरी समकक्ष शिक्षा को पाठ्यक्रमों में वांछित महत्ता नहीं दी गई।

यदि व्यावसायिक शिक्षा की बात करें तो यह अकादमिक शिक्षा से कई मायनों में अलग है। इसमें ज्ञान और कौशल का, व्यावहारिक चुनौतियों और अर्थव्यवस्था की स्थितियों के बीच गहरा संबंध होता है। इसे कौशल एवं कौशल विकास से अलग रखकर देखा जाना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा में ज्ञान, कौशल अभिवृत्ति का एक एकीकृत रूप समाहित होता है। देश में युवा बेरोजगारों की एक बड़ी संख्या है जिनमें से ज्यादातर केवल उच्च शिक्षा के भरोसे अपने भविष्य को संवारने में लगे हैं। उनके पास वैकल्पिक शिक्षा का कोई स्कोप नहीं और अगर उपलब्ध भी है तो संसाधनों की भारी कमी है। ऐसे में देश की विशाल आबादी को केवल परंपरागत शिक्षा के जरिये रोजगार मुहैया कराना एक दुःस्वप्न ही है। हालांकि अतीत में भी व्यावसायिक शिक्षा संबंधी सरकारी प्रयास किए जाते रहे हैं, अपितु उनके सफल क्रियान्वयन में अड़चनें अधिक आई हैं।

ऐसे कई कारण हैं जिसने व्यावसायिक शिक्षा के बारे में लोगों की सोच को प्रभावित किया है। अकादमिक और पेशेवर शिक्षा से व्यावसायिक शिक्षा के अलगाव और व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों की सामान्यतः खराब गुणवत्ता ने स्पष्ट रूप से इसमें अपनी भूमिका अदा की है। इस स्थिति में तुरंत बदलाव की आवश्यकता है। व्यावसायिक शिक्षा को छात्रों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाया जाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र इसके प्रति उन्मुख हो सकें। कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिसमें छात्रों के पास अपने अकादमिक करियर के दौरान व्यावसायिक शिक्षा को चुनने का विकल्प हो और वे इस चुने गए विकल्प पर एक उचित समयावधि तक काम कर सकें। स्नातक उत्तीर्ण करने के उपरांत सभी को रोजगार के पर्याप्त मौके मिल सकें, इसके लिए मानक उद्योग संस्थानों और भावी नियोक्ताओं को साथ मिलकर काम करना होगा। आइटीआइ, पॉलिटेकनिक,

स्थानीय उद्योगों और कारोबारों, खेती से जुड़े उद्योगों, अस्पतालों समेत तमाम गैर-सरकारी संस्थानों के साथ समन्वय करना होगा जहां छात्रों को व्यावहारिक कौशल का प्रशिक्षण दिया जा सके। ऐसे शिक्षा कार्यक्रमों को भी विकसित करना होगा जो मुख्यधारा की शिक्षा से एकीकृत हो और जिनसे प्राप्त व्यावहारिक प्रशिक्षण को, उससे संबद्ध सैद्धांतिक ज्ञान से पूरा किया जा सके।

हालांकि नई शिक्षा नीति के प्रारूप में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय आधार पर कौशल के अवसरों का पता लगाने, सभी शैक्षिक संस्थानों के साथ व्यावसायिक शिक्षा एकीकरण हेतु वित्तीय सहयोग, बुनियादी संरचना एवं व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लोगों की भर्ती, तैयारी और सहयोग के लिए पर्याप्त निवेश, अप्रेंटिसशिप को प्रोत्साहित करने जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात की गई है। सभी शैक्षिक संस्थानों द्वारा उनके पाठ्यक्रम में 25 प्रतिशत व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करना इस दिशा में एक अहम कड़ी साबित हो सकती है।

हालांकि सरकार द्वारा इस दिशा में की जा रही पहल सराहनीय है। सरकारी स्तर पर देश भर में कई ऐसे व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो छात्रों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में लाभकारी साबित हो रहे हैं जिसमें 'उड़ान' एक ऐसी ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसे जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत के अनेक इलाकों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए खास तौर पर शुरू किया गया है। इस व्यावसायिक कार्यक्रम के अंतर्गत बीपीओ और रिटेल जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कुछ इसी तर्ज पर 'परवाज' नामक एक अन्य व्यावसायिक परियोजना है जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्रों, बीपीएल, ड्रॉपआउट्स या बाहरी लोगों को प्रशिक्षण देना है।

इसके अतिरिक्त पॉलिटेकनिक जैसे पुराने व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पहले से बाजार में हैं जिसके जरिये छात्रों को इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान जैसे पारंपरिक विषयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है। इस कड़ी में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन भी है जिसमें विशेष छात्रों और गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं, और दिव्यांगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। आजीविका मिशन जैसी परियोजना ने तो व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी ख्याति अर्जित कर ली है जिसके अंतर्गत ग्रामीण गरीबों को रोजगारपरक ज्ञान, उपकरण, कौशल और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्त प्रदान किया जाता है। ये परियोजनाएं सरकार की अति-महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, लेकिन अभी इनके जरिये बहुत कुछ करना होगा। इसके लिए व्यापक और बहुसंख्यक योजनाओं सहित उसके उचित क्रियान्वयन की दरकार होगी।

व्यावसायिक शिक्षा आधारित इनोवेशन से इस दिशा में वांछित परिणाम हासिल किए जा सकेंगे। यदि छात्रों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है तो व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को समझना होगा तथा उसे परंपरागत शिक्षा के समकक्ष खड़ा कर शैक्षिक पाठ्यक्रमों में लागू करना होगा, केवल तभी पूर्ण स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा।

304 यात्रियों का पहला जत्था जम्मू-कश्मीर से हज के लिए गुरुवार को रवाना हुआ। ये सभी श्रीनगर हवाईअड्डे से दो विमानों से गए हैं। इस वर्ष राज्य से 11,600 लोग हज यात्रा करेंगे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 5 जुलाई 2019

जगन्नाथ रथ यात्रा में उमड़ा अपार जनसमूह : दुनियाभर में प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का गुरुवार को ओडिशा के पुरी शहर में शुभारंभ हो गया। इसमें दो लाख से अधिक देश-विदेश के श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। अगले 10 दिन तक पुरी में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के रथ यात्रा महोत्सव को हर्षोल्लास से मनाया जाएगा (बाएं)। उधर, कोलकाता में रथ यात्रा का बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भगवान जगन्नाथ की पूजा कर विधिवत उद्घाटन किया। उनके साथ तृणमूल की सांसद नुसरत जहां भी मौजूद रहीं (मध्य)। गुजरात के अहमदाबाद में रथयात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा-अर्चना करके जगन्नाथ रथयात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रथ का रस्सा खीचकर श्रद्धालु पुण्य अर्जित करने यहां पहुंचते हैं (दाएं)। जागरण व एजेंसी

पुलवामा हमले में हुआ था आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल

राजफाश ▶ सीएफएसएल के विशेषज्ञों ने साढ़े चार माह में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपी

अब जल्द अदालत में मामले को लेकर आरोपपत्र दायर किया जाएगा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जम्मू कश्मीर के पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के काफिले पर आत्मघाती हमले में जैश-ए-मुहम्मद ने आरडीएक्स के साथ अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया था।

दिल्ली स्थित सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (सीएफएसएल) के विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के अधिकारियों ने बताया कि सीबीआइ के अधीन काम करने वाली सीएफएसएल के विशेषज्ञों ने करीब साढ़े चार माह में अपनी जांच पूरी करते हुए रिपोर्ट सौंपी है। उन्होंने बताया कि हमले के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन में आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट को आपस में मिलाकर तैयार किया गया खतरनाक विस्फोटक जैरीकैन में फिट किया गया था। इसके बाद यह जैरीकैन हमले में इस्तेमाल मारुति इको कार में लगाया गया। इस मामले में सीएफएसएल की रिपोर्ट बहुत अहम है। यह पुलवामा कांड के गुनहगारों के खिलाफ आरोपपत्र में बहुत काम आएगी। हम जल्द ही अदालत में इस मामले को लेकर आरोपपत्र दायर करेंगे।

पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले में चली गई थी 40 जवानों की जान। फाइल

एनआइए के अधिकारियों के मुताबिक, जैश के आतंकियों ने धमाके के असर को बढ़ाने के लिए ही आरडीएक्स को अमोनियम नाइट्रेड के साथ मिलाया होगा। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि कई किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी। धमाके की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विस्फोट में शामिल कार पूरी तरह पिघल गई थी। यही नहीं, जिस बस को टक्कर मारी गई थी, वह भी पिघल गई थी। यही कारण है कि सीएफएसएल के विशेषज्ञों को घटनास्थल से जांच के लिए डीएनए के नमूने जमा करने में ही कई दिन लग गए।

सुरक्षा एजेंसियां पहले दिन से ही कह रही थी कि विस्फोट में मिलिट्री ग्रेड का आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ है, जिसे पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों को उपलब्ध कराया है। यह विस्फोटक विभिन्न रास्तों से कश्मीर में पहुंचाया गया था। एनआइए के अधिकारियों ने कहा कि इसकी आवाज और उसमें हुए नुकसान के आधार पर ही विस्फोटक की मात्रा का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन एक जैरीकैन में 45-50 किलो तक ही विस्फोटक को भरा जा सकता है। उन्होंने बताया कि पुलवामा हमले की साजिश को अंजाम देने वाला आतंकी आदिल मौके पर ही मारा गया था। उसके शरीर का कोई हिस्सा नहीं मिला। इस हमले की साजिश में लिप्त जैश के लगभग एक दर्जन ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े जा चुके हैं। हमले की साजिश में शामिल मुदस्सर, खालिद और सज्जाद बट समेत चार आतंकी भी मारे गए हैं। इस मामले में एनआइए ने अपनी जांच लगभग पूरी कर ली है। पकड़े गए लोगों के खिलाफ आरोपपत्र भी अंतिम चरण में है। सीएफएसएल की रिपोर्ट ही शेष थी, जो अब मिल गई है। ऐसे में जल्द ही कोर्ट में आरोपपत्र भी दायर कर दिया जाएगा।

गौरतलब है कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित लितपोरा पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर जैश के एक आत्मघाती ने विस्फोटकों से भरी कार से हमला किया था। इस हमले में 40 सीआरपीएफ कर्मी शहीद हुए थे। काफिले पर हमला करने वाला आतंकी भी इस धमाके में मारा गया था।

विदेशी नागरिकों के लिए उत्तराखंड में बनेगा डिटेंशन सेंटर

विकास गुसाईं, देहरादून: उत्तराखंड में जल्द ही अवैध रूप से आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए डिटेंशन सेंटर (नजरबंद रखने के लिए केंद्र) बनाने की तैयारी चल रही है। अब तक ऐसा कोई सेंटर न होने के कारण विदेशी नागरिकों को प्रारंभिक पूछताछ के बाद संबंधित दूतावासों को सौंप दिया जाता है।

उत्तराखंड एक सीमांत राज्य है। यहां की सीमाएं चीन व नेपाल से मिलती हैं। इस नाते यह सामरिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। इसके अलावा यहां का नैसर्गिक सौंदर्य देश-विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बीते कुछ समय से यहां अवैध रूप से आने वाले विदेशी नागरिकों की आमद बढ़ी है। चाहे वे यूरोप, अमेरिका अथवा अन्य देशों से आए नागरिक हों या फिर अवैध रूप से यहां आने वाले बंग्लादेशी।

देश के सभी राज्यों में अवैध रूप से आने वाले अथवा किसी संदिग्ध गतिविधि में लिप्त पाए जाने वाले विदेशियों को जेल की जगह डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। दरअसल, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत विदेशी नागरिक को संगीन जुर्म में ही जेल में रखा जाता है। अवैध रूप से प्रवेश करने अथवा अन्य मामलों में संबंधित दूतावास को सूचित कर इन नागरिकों को सौंप दिया जाता है। बीते कुछ वर्षों से उत्तराखंड में अवैध रूप से विदेशी नागरिकों की आमद बढ़ी है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी विदेशी पकड़े गए हैं। डिटेंशन सेंटर न होने के कारण पूछताछ के बाद इन्हें संबंधित दूतावासों को सौंपा गया है।

रथ यात्रा में शामिल हुईं नुसरत जहां कहा-करती हूं सभी धर्मों का सम्मान

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- 48वीं कोलकाता रथ यात्रा का शुभारंभ, तृणमूल सांसद ने मुख्यमंत्री ममता संग की पूजा-अर्चना
- प्रख्यात नृत्यांगना डोना गांगुली की मंडली ने पेश किया कार्यक्रम

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट की तृणमूल सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां ने गुरुवार को तमाम आलोचनाओं के बीच कोलकाता में इस्कॉन जगन्नाथ मंदिर में मंगल आरती की। इस दौरान उनके साथ राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल अध्यक्ष ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। नुसरत पीले और लाल रंग की साड़ी और मांग में सिंदूर लगाकर मंदिर पहुंची थीं। नुसरत इंटरनेशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कॉन) की तरफ से न्योता मिलने के बाद रथ यात्रा में शामिल हुईं थी। पूजा करने के बाद नुसरत जहां ने कहा कि मैं जन्म से मुस्लिम थी और अब भी मुस्लिम हूं। ये आस्था का मुद्दा है। इसे धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। नुसरत ने आगे कहा कि मैं हर धर्म का सम्मान करती हूं। इस्लाम में विश्वास रखती हूं। मुझे लेकर बेवजह विवाद फैलाया गया। विदित हो कि 29 साल की नुसरत जहां ने जून में तुर्की में कोलकाता के व्यवसायी निखिल जैन से शादी की थी।

ममता ने किया शुभारंभ, उमड़ा श्रद्धा का सैलाब : कोलकाता में हर साल की तरह इस्कॉन की ओर से भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने पहले प्रभु जगन्नाथ की आरती की। फिर रथ की रस्सी खींचकर 48वीं कोलकाता रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली की पत्नी व प्रख्यात नृत्यांगना डोना गांगुली भी मौजूद थीं। उनकी नृत्य मंडली ने कार्यक्रम पेश किया। रथ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा के रथों की रस्सियां खींचने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ लगी रही।

लगे जय श्री राम के नारे : हुगली में रथ यात्रा में ममता बनर्जी के सामने भाजपा समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाएं। बता दें कि मुख्यमंत्री के आने के पहले पुलिस भाजपा समर्थकों को हटा रही थी, इसी दौरान उनका काफिला निकला और भाजपाइयों ने जय श्री राम के नारे लगे। पश्चिमी मिदनापुर में भी रथ यात्रा के दौरान ऐसे नारे लगाए गए।

फिर उलमा के निशाने पर नुसरत : रथ यात्रा में शामिल होने को लेकर नुसरत एक बार फिर देवबंद (सहारनपुर, उप्र) के उलमा के निशाने पर हैं। फतवा ऑनलाइन के प्रभारी मुफ्ती अरशद फारूकी ने कहा कि मुसलमान किसी दूसरे धर्म की निशानी या क्रियाकलाप को नहीं कर सकता है। जमीयत दावतुल मुसलिमीन के संरक्षक मौलाना कारी ने कहा कि मुसलमान केवल अल्लाह की इबादत कर सकता है। मजलिस इत्तेहाद-ए-मिल्लत के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती अहमद ने कहा कि नुसरत जहां अगर यह इकरार करें कि उन्होंने मुस्लिम धर्म छोड़ दिया है तो फिर वह कुछ भी करने के लिए आजाद हैं। इससे पहले भी देवबंद के मौलवियों के एक धड़े ने नुसरत जहां के खिलाफ कथित तौर पर 'फतवा' भी जारी किया था।

सीबीआइ टीम पहुंची गोड्डा, जुटा रही चिटफंड घोटाले के साक्ष्य

जागरण संवाददाता, महागामा (गोड्डा) : गोड्डा के महागामा अनुमंडल में वर्ष 2013 में हुए चिटफंड घोटाले की सीबीआइ टीम जांच कर रही है। इसी क्रम में गुरुवार को दो सदस्यीय टीम महागामा पहुंची। सीबीआइ टीम के सदस्यों ने अनुमंडल क्षेत्र की पांच चिटफंट कंपनियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाने में पूरे दिन मशक्कत की। टीम ने ठगी के शिकार खाताधारकों से पूछताछ कर उनसे जरूरी कागजात भी लिए।

वर्ष 2013 में गोड्डा के तत्कालीन उपायुक्त रवि कुमार ने जनता की गाढ़ी कमाई डकारने वाली चिटफंड कंपनियों पर नकेल कसी थी। महागामा थाना में पांच कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी और राशि गबन का मामला दर्ज कराया था। वर्ष 2015 में इस मामले पर हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया। इसके बाद जांच की जिम्मेदारी सीबीआइ को सौंपी गई। 2018 में सीबीआइ ने एक चिटफंड कंपनी प्रतिज्ञा इंडस्ट्रीज के निदेशक व एक अधिकारी को गिरफ्तार कर चार्जशीट दायर की थी। गुरुवार को महगामा टीम 6 जुलाई तक यहां रहकर चिटफंड कंपनियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाएगी। टीम के सदस्यों ने गुरुवार को रियल इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेस लिमिटेड के बारे में भी अहम जानकारियां ली। चिटफंड कंपनी के खाताधारकों से पूछताछ कर उनके दावों को साक्ष्य के रूप में इकट्ठा किया जा रहा है।

बकोरिया में मुठभेड़ का किया नाट्य रूपांतरण, जब्त वाहन की जांच की

- सीबीआइ और सीएफएसएल ने शुरू की तफ्तीश, जुटाए सुबूत
- बारिश के कारण कुछ देर पड़ी जांच में बाधा, मीडिया से नहीं किया संवाद

अजय चौधरी, सतबरवा (पलामू)

पलामू स्थित बकोरिया पंचायत के भेलवाही में कथित तौर पर 12 माओवादियों के मारे जाने की घटना की जांच गुरुवार को सीबीआइ और केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (सीएफएसएल) की टीम ने संयुक्त रूप से की। सीएफएसएल के निदेशक डॉ. निलेंदु विकास वर्धन की टीम पूरी सुरक्षा के बीच सुबह 10.15 बजे सतबरवा थाना पहुंची। यहां घटना में जब्त स्कार्पियो की गहन जांच की। कई एंगल से जब्त वाहन व अन्य वस्तुओं की फोटोग्राफी भी की। इसके बाद लगभग 2 बजकर 5 मिनट पर जांच टीम मुठभेड़ स्थल बकोरिया के भेलवाही पहुंची। यहां पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार घटना का नाट्य रूपांतरण (डेमो) किया।

नाट्य रूपांतरण के दौरान पुलिस की उस थ्योरी को दोहराया गया, जिसमें मारने से लेकर नक्सलियों को जमीन पर लिटाए जाने की कहानी थी। रिपोर्ट के अनुसार पोजिशन, दूरी की मापी व एक-एक कर कैसे माओवादियों को मुठभेड़ में मारा गया, कैसे लिटाया गया, हर एक बिंदु पर जांच की गई। 3.40 बजे तेज बारिश शुरू हो गई। इसके बाद सभी पदाधिकारी और सुरक्षाकर्मी अपने टेंट में चले गए। करीब 40 मिनट तक सभी जांचकर्मी और सुरक्षाकर्मी बारिश से बचते हुए देखे गए।

सीबीआइ का लोगो।

गुरुवार को घटनास्थल पर जांच टीम ने पहुंचते ही पत्रकारों को घटनास्थल से 100 मीटर दूर कर दिया। कहा कि जांच में कोई परेशानी न हो इसलिए ऐसा किया जा रहा है। कहा गया कि टीम जांच के बाद मीडिया से मुखातिब होगी। लेकिन जांच टीम बारिश की वजह से मुखातिब हुए बिना चली गई।

मुठभेड़ की घटना : 8-9 जून 2015 की रात सतबरवा के बकोरिया पंचायत अंतर्गत भेलवाही गांव में सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच हुई कथित मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दावा किया था कि टॉप माओवादी कमांडर अनुराग उर्फ डॉक्टर उर्फ आरके समेत 12 माओवादी मारे गए हैं। मारे गए कथित माओवादियों में चार नाबालिग, एक ड्राइवर, अनुराग का बेटा और भतीजा, एक पारा शिक्षक शामिल था। सुरक्षाबलों ने उस समय दावा किया था कि सभी माओवादी एक स्कॉर्पियो से जा रहे थे। इसी क्रम में भेलवाही में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में कोबरा और सतबरवा ओपी के प्रभारी और उनकी टीम शामिल थी। मुठभेड़ को लेकर हाई कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए इसकी जांच सीबीआइ से करवाने का आदेश दिया था।

पंचतत्व में विलीन हुए उद्योगपति बीके बिड़ला

जागरण संवाददाता, कोलकाता

सुप्रसिद्ध उद्योगपति व समाजसेवी बसंत कुमार बिड़ला का गुरुवार को कोलकाता के केवड़ातल्ला श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। उद्योग जगत के साथ समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी।

बसंत कुमार बिड़ला का बुधवार को मुंबई में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। बुधवार रात करीब एक बजे उनके पार्थिव शरीर को विशेष विमान से कोलकाता लाया गया था। गुरुवार को बिड़ला पार्क परिसर में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था। वहां हजारों की तादाद में उमड़े लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वह उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे।

उनके पौत्र कुमार मंगलम बिड़ला उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें कोलकाता से मुंबई ले गए थे, जहां इलाज के दौरान बुधवार को उनका निधन हो गया।

कोलकाता के बिड़ला पार्क में गुरुवार को सुप्रसिद्ध उद्योगपति बसंत कुमार बिड़ला के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण करते उनके पौत्र कुमार मंगलम बिड़ला। जागरण

अमरनाथ यात्रा

देश-विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए ढाल बन रहे हैं ये जवान, कहीं वे चोटियों से गिरने वाले पत्थरों से लोगों को बचा रहे हैं, तो कहीं बंदूक व पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए यात्रियों का हौसला बढ़ा रहे हैं।

भक्तों के लिए सीना ताने खड़े हैं आइटीबीपी के जवान

राज्य ब्यूरो, जम्मू

बर्फीले पहाड़ों पर सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने में दक्ष इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (आइटीबीपी) बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए देश-विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए ढाल बन रही है। कहीं वे चोटियों से गिरने वाले पत्थरों से लोगों को बचा रहे हैं, तो कहीं बंदूक व पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए यात्रियों का हौसला बढ़ा रहे हैं।

बाबा अमरनाथ की गुफा के निकट ग्लेशियर पर बर्फ में यात्रा को सुगम बनाने का बंदोबस्त करने के साथ आइटीबीपी के जवान पहाड़ों से गिरने वाले पत्थरों को रोकने के लिए सीना ताने खड़े हैं। ये जवान न सिर्फ यात्रा को सुरक्षित बना रहे हैं, बल्कि यात्रियों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए भी आइटीबीपी की मेडिकल टीमें सक्रिय हैं। गुरुवार को भी इन वीरों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण बीमार हो गई एक महिला श्रद्धालु की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई।

प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए पूरा बंदोबस्त : यात्रा को कामयाब बनाने के लिए आइटीबीपी के जवानों ने जून के अंतिम सप्ताह में पहलगाम व बालटाल मार्ग के दुर्गम हिस्सों में डेरा डाल लिया था। आइटीबीपी की माउंटेन रेस्क्यू टीमों के पास यात्रियों को हर प्रकार की प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए पूरा बंदोबस्त है। इनमें पहाड़ों की ढलानों पर गिरने वाले छोटे पत्थर को रोकने वाली शील्ड भी है। इससे गिरने वाले छोटे पत्थरों व बर्फ के टुकड़ों को रोका जा सकता है। मददगार की भूमिका निभा रहे जवान श्रद्धालुओं की तबीयत खराब होने पर तत्काल सहायता पहुंचा रहे हैं।

बाबा अमरनाथ यात्रा मार्ग पर ग्लेशियर की ढलानों से गिर रहे पत्थरों को शील्ड से रोक कर यात्रियों को बचाते आइटीबीपी के जवान। जागरण

सांस लेने में दिक्कत के बाद अब तक 25 श्रद्धालुओं की मदद की

आइटीबीपी ने यात्रा मार्ग के ऐसे हिस्सों की पहचान की है, जहां ऑक्सीजन कम है। इन जगहों पर यात्रियों को रुकने नहीं दिया जाता है। उन्हें वहां से आगे ले जाने के लिए जवान यात्रियों की सहायता करते हैं। 12 हजार फीट से ऊपर अगर किसी यात्री का दम फूलने लगे तो उसे फौरन ऑक्सीजन देकर सामान्य किया जाता है। अब तक जवानों ने ऊंचाई पर सांस लेने में दिक्कत के बाद 25 श्रद्धालुओं की मदद की है। जवानों ने उन्हें तुरंत ऑक्सीजन देकर सुनिश्चित किया कि उनकी तबीयत और न बिगड़ जाए। बुधवार को जम्मू से रवाना हुए 4,600 से अधिक श्रद्धालुओं में से 15 यात्रियों को सांस की तकलीफ हुई थी। उनकी हालत को देखते हुए आइटीबीपी के जवानों ने यात्रियों की मदद की। श्रद्धालुओं को मदद देने की आइटीबीपी की मुहिम 15 अगस्त को यात्रा संपन्न होने तक जारी रहेगी।

50 हजार से अधिक श्रद्धालु कर चुके भगवान अमरेश्वर के दर्शन

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- आज 16789 श्रद्धालुओं ने किए बाबा अमरनाथ के दर्शन
- जम्मू से 5522 श्रद्धालु दर्शन के लिए हुए रवाना

भगवान अमरेश्वर की गुफा में वीरवार को 16789 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसके साथ ही इस साल यात्रा शुरू होने के बाद चार दिनों में ही बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 हजार का आंकड़ा पार कर गई। जम्मू से वीरवार सुबह 5522 श्रद्धालु दर्शन के लिए रवाना हुए।

इस बीच, राज्यपाल के सलाहकार के विजय कुमार ने रामबन व चंद्रकोट का दौरा कर बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए किए गए सुरक्षा प्रबंधों और ट्रैफिक को निर्विघ्न बनाने के प्रबंधों का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि वीरवार को चौथे दिन सुबह से शाम तक 16789 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इसके साथ ही पहली जुलाई की सुबह से वीरवार शाम पांच बजे तक 50483 श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर चुके हैं।

राज्यपाल के सलाहकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, उनके ठहरने, खाने-पीने और उनके वाहनों के अलावा अन्य नागरिक वाहनों की हाईवे पर सुरक्षित आवाजाही के लिए किए गए प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में एडीजी मुनीर खान, आइजी ट्रैफिक आलोक कुमार, जिला उपायुक्त रामबन शौकत एजाज बट, जिला उपायुक्त ऊधमपुर डॉ. पीयूष सिंगला, डीआइजी डोडा रेंज भीमसेन टूटी के अलावा सेना, सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

राज्यपाल के सलाहकार ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाए रखने के लिए कहा ताकि यात्रा संचालन में कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियों के संयुक्त नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील बनाए रखा जाए।

5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास हुए जबरदस्त विस्फोट में। पाक की सेना ने इसे आतंकी कार्रवाई बताया है। इस वारदात में एक सैनिक घायल भी हुआ है।

न्यूज गैलरी

ब्रिटिश नौसेना ने पकड़ा सीरिया जा रहा तेल टैंकर

लंदन : ब्रिटिश नौसेना और जिब्राल्टर के अधिकारियों ने सीरिया जा रहे एक बड़े तेल टैंकर को पकड़ा है। इस मालवाहक पोत को यूरोपीय यूनियन (ईयू) के प्रतिबंधों की अवहेलना के आरोप में पकड़ा गया है। ईयू ने 2011 से ही सीरिया पर पाबंदी लगा रखी है। ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र वाले जिब्राल्टर द्वीप के अधिकारी फैबियन पिकार्डो ने बताया कि कच्चे तेल से भरे ग्रेस-1 नाम के इस तेल टैंकर को सीरिया की बनयास रिफाइनरी भेजा जा रहा था। शुरुआती जांच में ग्रेस-1 के मैपिंग डाटा से पता चला कि यह ईरान से चला था। (रायटर)

ईस्टर हमले के बाद श्रीलंका में पर्यटकों की संख्या में गिरावट

कोलंबो : ईस्टर आतंकी हमले के बाद श्रीलंका आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट हुई है। श्रीलंका पर्यटन विकास प्राधिकरण के अनुसार, इस साल जून में महज 63 हजार पर्यटक ही आए। जबकि पिछले साल जून में एक लाख 46 हजार से ज्यादा पर्यटक श्रीलंका आए थे, जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय थे। गत 21 अप्रैल को ईस्टर के दिन हुए हमलों में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। (एपी)

इराक में इस्लामिक स्टेट के 18 आतंकी ढेर

बगदाद : इराक के विभिन्न इलाकों में सुरक्षाबलों और अमेरिका की अगुआई वाली गठबंधन सेना के हवाई हमले में इस्लामिक स्टेट के 18 आतंकी मारे गए। संयुक्त अभियान कमान के अनुसार, यह कार्रवाई सीरिया से लगे सीमावर्ती हिस्सों में आतंकियों के ठिकानों पर की गई। सीरिया, जॉर्डन और सऊदी अरब तक फैले अनबर रेगिस्तान के इलाकों में आइएस आतंकी अब भी सक्रिय हैं। (आइएएनएस)

प्रदूषण को लेकर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पर मुकदमा

जकार्ता : इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंचने पर पर्यावरण समूहों ने देश के राष्ट्रपति जोको विडोडो समेत अन्य अधिकारियों पर मुकदमा किया है। पर्यावरण कार्यकर्ता बोंडान एंड्रीयन के मुताबिक, यह केस इसलिए किया गया है ताकि सरकार प्रदूषण की वजहों की जांच कर उसे कम करने में जुटे। जकार्ता विश्व के दस सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। (रायटर)

पुतिन ने माना, परमाणु चालित थी हादसे का शिकार पनडुब्बी

मॉस्को : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने माना कि तीन दिन पहले हादसे का शिकार हुई पनडुब्बी परमाणु चालित थी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि इसके रिएक्टर को सुरक्षित तरीके से अलग कर दिया है। इस पनडुब्बी में गत सोमवार को आग लग गई थी। (रायटर)

मैक्स विमान हादसे पीड़ितों के लिए 700 करोड़ देगी बोइंग

सिएटल, रायटर : अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने कहा है कि वह इंडोनेशिया और इथोपिया में हुए 737 मैक्स विमान हादसों के पीड़ित परिवारों की मदद के लिए दस करोड़ डॉलर (करीब 700 करोड़ रुपये) देगी। यह मदद संबंधित देशों की सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के जरिये कुछ सालों के दौरान पहुंचाई जाएगी। बोइंग के इस कदम को दो विमान हादसों के कारण अपनी खराब हुई छवि को सुधारने के तौर पर देखा जा रहा है।

पिछले साल 29 अक्टूबर को इंडोनेशिया की लॉयन एयर का विमान हादसे का शिकार हो गया था। इसके बाद इस साल दस मार्च को इथोपिया में भी एक 737 मैक्स विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इन दोनों हादसों में 346 लोगों की जान चली गई थी। इन हादसों के बाद से ही दुनिया के कई देशों ने 737 मैक्स विमानों की उड़ानें रद कर दी थीं। प्रारंभिक जांच में पाया गया था कि दोनों हादसों के लिए विमान का एंटी-स्टॉल सॉफ्टवेयर और अन्य तकनीकी खामियां जिम्मेदार हैं। यह बात सामने आने के बाद बोइंग को दुनियाभर में तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था। हादसों के बाद से बोइंग का यह विमान अमेरिका के न्याय विभाग की जांच के दायरे में है। बोइंग के खिलाफ पीड़ित परिवारों

इंडोनेशिया और इथोपिया में हुए विमान हादसों में गई थी 346 लोगों की जान

पीड़ित परिवारों की नहीं बदलेगी रणनीति

इथोपिया विमान हादसे को लेकर दायर मुकदमे में कई पीड़ित परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यूयॉर्क के वकील जस्टिन ग्रीन ने कहा, 'इस राशि से अदालत में उनके मुवक्किलों की रणनीति पर असर नहीं पड़ेगा। पीड़ित परिवार यह जानना चाहते हैं कि हादसा क्यों हुआ और क्या इससे बचा जा सकता था?'

की ओर से भी 100 से ज्यादा मुकदमे किए गए हैं। बोइंग के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा, 'यह भुगतान मुकदमों से अलग है और कानूनी लड़ाई पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। दस करोड़ डॉलर से प्रभावित लोगों की शिक्षा और आर्थिक उन्नति में मदद की जाएगी।' दुनिया की इस सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी ने हालांकि यह नहीं बताया कि वह यह धनराशि किस प्राधिकरण या संगठन को देगी।

सैन्य बजट से मेक्सिको सीमा पर दीवार नहीं बनवा पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप

वाशिंगटन, आइएएनएस : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने की योजना पर झटका लगा है। सैन फ्रांसिस्को की एक अपीलीय अदालत ने दीवार निर्माण के लिए सैन्य बजट से ढाई अरब डॉलर (करीब 17 हजार करोड़ रुपये) लेने की योजना पर रोक लगा दी है। अदालत ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि यह संघीय कानून का उल्लंघन प्रतीत होता है। अदालत ने ट्रंप प्रशासन की उन दलीलों को भी खारिज कर दिया कि इस तरह का खर्च लोगों के हित के लिए आवश्यक है।

ट्रंप प्रशासन की इस योजना को दो गैर लाभकारी संगठनों ने चुनौती दी थी। सीमा पर दीवार का निर्माण ट्रंप की महत्वाकांक्षी परियोजना है। उनकी दलील है कि मेक्सिको सीमा पर दीवार खड़ी होने से शरणार्थी अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसके लिए उन्होंने संसद से 6.7 अरब डॉलर (करीब 46 हजार करोड़ रुपये) का फंड मांगा था, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाने के कारण इस साल के शुरू में अमेरिका में 35 दिन तक शटडाउन रहा था। गत फरवरी में ट्रंप ने इस मुद्दे पर देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी ताकि दीवार के निर्माण के लिए सैन्य और अन्य स्रोतों से रकम का प्रबंध किया जा सके।

तूफान में तबाही के निशां...

चीन के उत्तर-पश्चिम प्रांत लियाओनिंग के काइयुआन में गुरुवार को तूफान में क्षतिग्रस्त मकान के मलबे को देखती महिला। इस तूफान से राज्य में भारी नुकसान हुआ है। कई इलाकों में भारी बारिश से सामान्य जन-जीवन बुरी तरह से अस्तव्यस्त हो गया है। उधर, सिचुआन के गोंग काउंटी के यिबिन शहर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 5.6 मापी गई। रायटर

कड़ी शर्तों के साथ आइएमएफ ने पाक को दिया 41 हजार करोड़ रुपये का कर्ज

चुनौती ▶ पाकिस्तान को अगले तीन वर्षों में खर्चों में कटौती के कड़े उपाय करने होंगे

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के फंड से आर्थिक संकट से उबरने में मिलेगी मदद

वाशिंगटन, प्रेट्र : आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को आखिरकार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) से बड़ा सहारा मिल गया है। आइएमएफ ने पाकिस्तान को छह अरब डॉलर (करीब 41 हजार करोड़ रुपये) का कर्ज दिए जाने पर मुहर लगा दी है। आइएमएफ ने इसके लिए कड़ी शर्तें भी लगाई हैं। इनके तहत पाकिस्तान को आगामी तीन वर्षों में खर्चों में कटौती के कड़े उपाय करने होंगे।

आइएमएफ के प्रवक्ता गैरी राइस ने बुधवार को कहा, 'आइएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान की आर्थिक योजना की सहायता के लिए छह अरब डॉलर के कर्ज को मंजूरी दी है। यह कर्ज इस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और लोगों की जीवन दशा को बेहतर करने के मकसद से दिया गया है।' उन्होंने बताया कि छह अरब डॉलर की इस आर्थिक मदद के तहत पाकिस्तान को भुगतान संकट का समाधान करने के लिए तत्काल एक अरब डॉलर की रकम दी

इमरान खान। फाइल

इन देशों से भी मिली मदद

- चीन ने जमा और वाणिज्यिक कर्ज के तौर पर 4.6 करोड़ डॉलर दिए
- सऊदी अरब ने तीन अरब डॉलर नकद और 3.2 अरब डॉलर का तेल दिया
- संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से दो अरब डॉलर मिले
- कतर भी तीन अरब डॉलर की आर्थिक मदद की घोषणा कर चुका है

जाएगी। बाकी राशि एक कार्यक्रम के तहत तीन वर्ष की तय अवधि के दौरान दी जाएगी। इस अवधि के दौरान चार बार तिमाही और इतने ही बार अर्ध वार्षिक समीक्षा भी की जाएगी। इससे जाहिर होता है कि आने वाले तीन वर्षों के दौरान पाक को खर्चों में कटौती के कड़े उपाय करने होंगे। पीएम इमरान खान के वित्तीय मामलों के सलाहकार डॉ अब्दुल हफीज शेख ने कर्ज को मंजूरी की पुष्टि की है।

22वीं बार बेलआउट पैकेज : पाकिस्तान साल 1950 में आइएमएफ का सदस्य बना था। तब से पाकिस्तान इस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन से 21 बार आर्थिक मदद पा चुका है। यह 22वां मौका है, जब उसे आइएमएफ से बेलआउट पैकेज मंजूर हुआ है।

इमरान सरकार ने पिछले साल लगाई थी गुहार : सत्ता में आने के बाद इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले साल अगस्त में बेलआउट पैकेज के लिए आइएमएफ से गुहार लगाई थी। बेलआउट पैकेज पर लंबी बातचीत के बाद दोनों पक्षों में पिछले माह सहमति बनी थी।

ट्रंप से 22 जुलाई को पहली बार मिलेंगे इमरान खान

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस माह अमेरिका का पहला दौरा करने जा रहे हैं। वह अपनी इस यात्रा के दौरान 22 जुलाई को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। उनकी ट्रंप से यह पहली मुलाकात होगी। उनका यह दौरा ऐसे समय होने जा रहा है, जब दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे नहीं रह गए हैं। ट्रंप ने यह कहते हुए पाकिस्तान को मिलने वाली सैन्य मदद रद कर दी थी कि उसने आतंकवाद से लड़ाई में कुछ नहीं किया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुहम्मद फैसल ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के आमंत्रण पर इमरान खान अमेरिका का पहला दौरा करेंगे। दोनों नेताओं की बातचीत का मुख्य एजेंडा द्विपक्षीय संबंधों में ताजगी लाने पर केंद्रित होगा। यह घोषणा ऐसे समय हुई जब एक दिन पहले ही अमेरिका ने बलूच लिबरेशन आर्मी को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित कर दिया।

गिरफ्तार किए जाएंगे हाफिज और उसके साथी : पाक पुलिस

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तानी पुलिस ने गुरुवार को कहा कि मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद और उसके 12 साथियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सभी के खिलाफ बुधवार को पंजाब पुलिस के आतंक निरोधी विभाग (सीटीडी) ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में आतंकी फंडिंग और मनी लांड्रिंग के 23 मामले दर्ज किए गए थे।

पंजाब पुलिस के प्रवक्ता नियाब हैदर नकवी ने बताया कि एफआइआर दर्ज की जा चुकी है और संदिग्धों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि एफआइआर में नामित किए जाने के बावजूद सईद और अन्य को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? नकवी ने कहा, पहले संदिग्धों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाती है और फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। पहले भी आतंकी फंडिंग के मामले में प्रतिबंधित संगठनों के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और बाद में आतंकरोधी अदालतों ने उन्हें जेल भेजा है।

इमरान खान सरकार के एक सूत्र ने बताया कि बताया, 'सईद फिलहाल लाहौर के जौहर कस्बे में स्थित अपने आवास पर है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके आवास पर छापा मारने के लिए सरकार से हरी झंडी का इंतजार कर रही है।' उक्त सूत्र ने आगे बताया कि सईद को संभवतः इसी हफ्ते गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि इमरान सरकार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स

जमात उद दावा प्रमुख और उसके 12 साथियों के खिलाफ बुधवार को दर्ज किए गए थे मामले

मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा का प्रमुख हाफिज सईद। फाइल

(एफएटीएफ) के तहत आतंकी फंडिंग पर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रति गंभीर दिख रही है।

इटली में ज्वालामुखी में विस्फोट

इटली के सिसिली के उत्तरी क्षेत्र में स्ट्रोमबॉली द्वीप पर एक ज्वालामुखी में अचानक विस्फोट के बाद हवा में कई किलोमीटर ऊंचाई तक काला धुआं और राख फैल गई। इस दौरान दम घुटने से एक पर्वतारोही की मौत हो गई। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद द्वीप पर मौजूद कई पर्यटकों ने समुद्र में कूदकर अपनी जान बचाई। एएफपी

जनगणना में नागरिकता का सवाल शामिल नहीं करेगा ट्रंप प्रशासन

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में अगले साल होने वाली जनगणना में नागरिकता के बारे में सवाल शामिल करने की विवादास्पद योजना से ट्रंप प्रशासन पीछे हट गया है। अब नागरिकता का सवाल जनगणना में शामिल नहीं किया जाएगा। यह नागरिक अधिकार समूहों की बड़ी जीत मानी जा रही है। उनकी दलील थी कि इस कदम से आप्रवासी जनगणना में हिस्सा नहीं लेंगे।

ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से कुछ दिन पहले अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जनगणना में नागरिकता संबंधी सवाल शामिल करने के प्रयास पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सरकार का यह तर्क काल्पनिक प्रतीत होता है कि इससे अल्पसंख्यक वोटरों को बेहतर संरक्षण मिलेगा। विरोधियों का कहना था कि यह आप्रवासियों को जनगणना में हिस्सा लेने से रोकने का कदम है। उनकी दलील थी कि साल 1950 से ही नागरिकता का सवाल जनगणना में शामिल नहीं किया जा रहा। इसे शामिल करने से बहुत से लोग जनगणना में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहेगा कि इससे वे अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ ट्रंप प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अभियान में पकड़े जा सकते हैं।

चीन पहुंचीं बांग्लादेश की पीएम हसीना, नौ समझौते किए

बीजिंग, प्रेट्र : चीन के तीन दिवसीय दौरे पर गुरुवार को बीजिंग पहुंचीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उनकी चीन के प्रधानमंत्री ली कछ्यांग के साथ द्विपक्षीय मसलों पर वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच नौ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। बांग्लादेश की सरकारी न्यूज एजेंसी बीएसएस के अनुसार, चीन के प्रधानमंत्री ने बीजिंग के ग्रेट हॉल में हसीना का स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक हुई वार्ता के बाद ऊर्जा, आर्थिक, प्रौद्योगिकी सहयोग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पर्यटन के क्षेत्र में नौ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। एक समझौते के तहत म्यांमार से बांग्लादेश में पलायन करने वाले रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए चीन ढाई हजार टन चावल मुहैया कराएगा। हसीना का राष्ट्रपति शी चिनफिंग समेत चीन के दूसरे शीर्ष नेताओं से भी मिलने का कार्यक्रम है।

बीसीआइएम के लिए बनाया दबाव : द्विपक्षीय वार्ता के दौरान हसीना पर चीन की ओर यह दबाव बनाए जाने की चर्चा है कि वह बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार (बीसीआइएम) आर्थिक गलियारे को आगे बढ़ाने में तेजी दिखाएं। चीन की यह परियोजना

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके चीनी समकक्ष ली कछ्यांग। एएनआइ

गति नहीं पकड़ पाई है। वह अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बीसीआइएम को आगे बढ़ाने की फिराक में है। 2800 किमी लंबी इस परियोजना के तहत चीन के युन्नान प्रांत के कुनमिंग शहर को म्यांमार के मांडले, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और कोलकाता से जोड़ने की योजना है।

उत्तर कोरिया में हिरासत में लिया गया ऑस्ट्रेलियाई छात्र रिहा

सिडनी, एएफपी : उत्तर कोरिया में हिरासत में लिए गए ऑस्ट्रेलियाई छात्र एलेक सिगले को रिहा कर दिया गया है। उत्तर कोरिया में रहकर पढ़ाई करने वाले सिगले (29) गत 23 जून से लापता थे। रिहाई के बाद सिगले को गुरुवार को बीजिंग एयरपोर्ट पर सुरक्षित देखा गया। वह तानाशाही शासन के अधीन उत्तर कोरिया में रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में अक्सर ब्लॉग लिखते थे। लापता होने के बाद आशंका जताई जा रही थी कि कहीं सिगले का हश्र भी अन्य विदेशी छात्रों की तरह तो नहीं हो गया। वर्ष 2016 में उत्तर कोरिया घूमने गए अमेरिकी छात्र ओटो वार्मबियर को वहां हिरासत में इतनी प्रताड़ना दी गई थी कि कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई थी।

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने गुरुवार को यहां कहा कि सिगले को रिहा कर दिया गया है और अब वह सुरक्षित हैं। मॉरिसन ने इसके लिए स्वीडन की सरकार का आभार जताया। उत्तर कोरिया में ऑस्ट्रेलियाई राजनयिक नहीं होने की वजह से स्वीडन के विशेष दूत ने सिगले की रिहाई के लिए उत्तर कोरिया का दौरा किया था। मॉरिसन ने इसे पर्दे के पीछे की कूटनीतिक जीत बताया।

बड़ा मामला

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने भारत और पाकिस्तान को भेज दी है सूचना, पाक की सैन्य कोर्ट से नौसेना के पूर्व अधिकारी को सुनाई गई फांसी की सजा को भारत ने दी है चुनौती

आइसीजे में कुलभूषण पर फैसला 17 को

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पाकिस्तान की जेल में बंद और वहां की एक सैन्य अदालत से फांसी की सजा प्राप्त भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के भाग्य का फैसला 17 जुलाई को हो जाएगा। भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) में पाक सैन्य कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रखी है। अब तकरीबन दो वर्षों बाद आइसीजे इस पर अपना फैसला सुनाएगा। आइसीजे ने भारत व पाकिस्तान को इस बारे में सूचना भेज दी है।

मई, 2018 में आइसीजे की 10 सदस्यीय पीठ ने भारत की अपील पर विचार करते हुए जाधव की फांसी पर तत्कालिक तौर पर रोक लगा दी थी। आइसीजे का फैसला न सिर्फ जाधव के लिए महत्वपूर्ण होगा बल्कि भारत व पाकिस्तान के रिश्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा।

भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि उन्हें जाधव पर होने वाले फैसले की सूचना दे दी गई है। भारतीय पक्षकार को पहले से ही इस बात उम्मीद है कि जाधव के मामले पर सकारात्मक फैसला आएगा। इसके पीछे जो वजहें बताई जा रही हैं उसमें

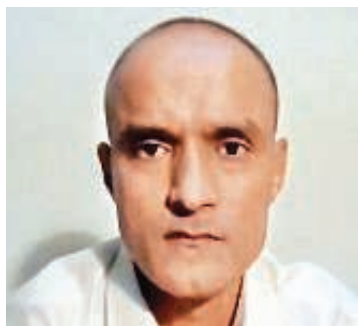

कुलभूषण यादव। फाइल

दम भी नजर आता है। एक तो यह कि जाधव को जिस तरह से सैन्य कोर्ट ने एक संदेहास्पद कानूनी कार्रवाई में सजा सुनाई है उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमेशा से संदेह की नजर से देखा जाता है। जाधव को कभी भी भारतीय उच्चायोग से मदद नहीं लेने दिया गया। यही कारण है कि वह अपनी बात सही तरीके से नहीं रख सके।

भारत की उम्मीद इसलिए भी मजबूत है कि इसी साल फरवरी में सुनवाई के दौरान आइसीजे पाकिस्तान की कई अपीलों को खारिज कर चुका है। पाकिस्तान की तरफ से जाधव का इकबालिया बयान पेश करने का प्रस्ताव किया गया था। आइसीजे ने इसे खारिज कर दिया था।

यह वीडियो मार्च, 2016 में ही पाकिस्तान सरकार ने यह कहते हुए जारी किया था कि कुलभूषण ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है। भारत ने तभी इस वीडियो की समीक्षा की थी और इसे फर्जी बताते हुए खारिज कर दिया था। भारत ने अपनी अंतिम अपील में इस साल 20 फरवरी को कहा था कि पाकिस्तान में दी गई सजा को निरस्त किया जाना चाहिए।

बता दें कि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान द्वारा गिरफ्तार किए गए भारतीय नागरिक और पूर्व नौसेना अधिकारी हैं। पाकिस्तान का दावा है कि जाधव बलूचिस्तान में विध्वंसक गतिविधियों में शामिल थे और वह भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के कर्मचारी हैं। भारत ने इनकी भारतीय नागरिकता और पूर्व नौसेना अधिकारी होने की ही पुष्टि की थी। 10 अप्रैल 2017 में पाक फौज की अदालत ने उन्हें जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। 10 मई, 2017 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जाधव की फांसी पर रोक लगा दी।

दुबई हवाईअड्डे पर अब भारतीय रुपये से भी होगी खरीदारी

दुबई, प्रेट्र : भारतीय पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। दुबई के सभी हवाईअड्डों पर अब भारतीय रुपये में लेनदेन हो सकेगा। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के तीनों टर्मिनलों पर और अल मख्तूम हवाईअड्डे पर भारतीय मुद्रा स्वीकार की जाएगी। अखबार ने दुबई ड्यूटी फ्री स्टाफ को कोट करते हुए कहा, 'हां, हमने भारतीय मुद्रा को स्वीकार करना शुरू कर दिया है।'

रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल दुबई एयरपोर्ट से करीब नौ करोड़ यात्री गुजरे। इनमें 1.22 करोड़ यात्री भारतीय थे। भारतीय यात्रियों को दुबई की ड्यूटी फ्री दुकानों पर खरीदारी से पहले रुपये को डॉलर, दिरहम या यूरो में परिवर्तित करना पड़ता था। खबर में कहा गया है कि रुपये दुबई में ड्यूटी फ्री दुकानों पर स्वीकार की जाने वाली 16वीं मुद्रा है। यहां दिसंबर 1983 में दूसरी मुद्राओं को स्वीकार करने की शुरुआत हुई थी। भारतीय पर्यटकों के लिए यह अच्छी खबर है, क्योंकि उन्हें विनिमय दरों के रूप में एक बड़ी राशि गंवानी पड़ती थी।

दुबई की रानी हया ने ब्रिटेन में मांगी राजनीतिक शरण

लंदन, एएनआइ : दुबई की रानी हया बिंत अल हुसैन ने ब्रिटेन में राजनीतिक शरण मांगी है। हया दुबई के शासक शेख मुहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम की पत्नियों में से एक हैं। पिछले दिनों सामने आया था कि हया पति को छोड़कर चली गई हैं। उन्होंने पति से तलाक भी मांगा है।

नाम नहीं बताने की शर्त पर शाही परिवार से जुड़े एक शख्स ने बताया कि 45 वर्षीय रानी हया कई महीने पहले ही अपने 11 और सात साल के बच्चों को लेकर लंदन चली गई थीं। तभी से वह बच्चों शेख जायेद और जलीला के साथ केंसिंगटन पैलेस के नजदीक एक भवन में रह रही हैं। पिछले महीने एक शाही कार्यक्रम में रानी की अनुपस्थिति के बाद उनके भागने की खबरें सामने आई थीं। रानी हया को शेख की छह पत्नियों में सबसे आकर्षक माना जाता है। वह जॉर्डन के पूर्व राजा हुसैन की बेटी हैं और अपने सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने 2004 में दुबई के 69 वर्षीय शासक से अम्मान में एक सादे कार्यक्रम में शादी की थी। रानी हया ने दुबई छोड़कर जाने

पति शेख मुहम्मद को छोड़कर लंदन में रह रही हैं हया बिंत अल हुसैन

जानकारों के मुताबिक, शेख से तलाक चाहती हैं रानी

को लेकर सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। हालांकि उनके जाने के बाद से शेख ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कुछ शायरियां पोस्ट की हैं। इनमें सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया गया है। एक पंक्ति में उन्होंने लिखा, 'मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं, मुझे परवाह नहीं कि तुम जियो या मरो।'

पहले भागी थीं दो राजकुमारियां: रानी हया दुबई में शेख मुहम्मद के महल से भागने वाली तीसरी महिला हैं। इससे पूर्व शेख मुहम्मद की दो बेटियां शेखा शम्स अल मख्तूम और शेखा लतीफा बिंत मुहम्मद अल मख्तूम महल से भाग गई थीं। उन्हें सैनिकों ने पकड़ लिया था। वकीलों का कहना है कि दोनों की इच्छा के बिना उन्हें दुबई में रखा गया है।

ये भी जानिए
वेस्टइंडीज के लिए विश्व कप में क्रिस गेल ने 35 मैच में 35.93 के औसत से 1186 रन बनाए हैं। इसमें दो शतक और छह अर्धशतक शामिल रहे। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच उनका आखिरी विश्व कप मैच था।

सचिन के लिए यॉर्कशायर ने तोड़ा था 129 साल पुराना नियम

अभिषेक त्रिपाठी ● लीड्स

सचिन तेंदुलकर यानी क्रिकेट के भगवान... बात 1992 की है तब उनके खाते में कुछ हजार रन ही थे, वह क्रिकेट के भगवान भी नहीं थे, लेकिन उनके अंदर क्रिकेट की इतनी चाहत थी कि वह दुनिया के हर कोने में खेलना चाहते थे, ऐसी ही एक चाहत थी इंग्लैंड के सबसे पुराने काउंटी क्लबों में से एक यॉर्कशायर के लिए खेलना। अंग्रेज अपने नियमों के पक्के होते हैं और वह किसी की चाहत के लिए उन्हें नहीं तोड़ते हैं, लेकिन सचिन की प्रतिभा और एक अन्य भारतीय मूल के पूर्व खिलाड़ी सोली एडम की मेहनत के आगे उन्हें झुकना पड़ा।

1863 में बने यॉर्कशायर क्लब ने 129 साल तक किसी विदेशी खिलाड़ी को अपने यहां से खेलने का मौका नहीं दिया था। उनके क्लब में सिर्फ यॉर्कशायर के ही खिलाड़ी खेलते थे, लेकिन भारतीय मूल के ब्रिटिश खिलाड़ी सोली एडम से जब सचिन ने संपर्क किया तो उन्होंने इसके लिए कोशिश शुरू की। यॉर्कशायर के पूर्व क्रिकेटर सोली कहते हैं कि 1992 में इस क्रिकेट क्लब के लिए वही खेल पाता था, जो यहां का निवासी होता था, लेकिन सचिन इस क्लब से खेलने वाले पहले गैर-यॉर्कशायर खिलाड़ी बने। सचिन ने अपनी आत्मकथा में भी इस बारे में लिखा है कि वो साढ़े चार महीने मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। यहां के बड़े बिजनेसमैन और भारत व पाकिस्तान के सैकड़ों क्रिकेटरों को इंग्लिश काउंटी क्लबों में खेलने में मदद करने वाले 67 वर्षीय सोली कहते हैं कि मैं सचिन को तब से जानता हूं जब वह क्रिकेट के भगवान नहीं थे। वह तब ना लिटिल मास्टर थे और ना ही कोई स्टार। वह हमारी डाइनिंग टेबल में

यॉर्कशायर काउंटी के लिए 1992 में पदार्पण मैच खेलने से पहले भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ● फाइल फोटो, एएफपी

हमारे साथ खाना खाते थे। वह भारतीय खाना खाने के लिए हमारे यहां आते थे। मेरी पत्नी और भाभी उनके कपड़े धोती थीं क्योंकि उनको यह सब करना नहीं आता था। जब भी वह फ्री होते थे तो हम उनको किसी की शादी में और सिनेमा देखने के लिए ले जाते थे। उन्हें लीड्स के केंटकी का फ्राइड चिकन पसंद था। सचिन जब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं देखकर हैरान था कि लोग उनके लिए पागल थे। मालूम हो कि सचिन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के तीन साल बार 1992 में यॉर्कशायर के लिए एक सत्र तक क्रिकेट खेला। उन्होंने उस दौरान 46.52 के औसत से 1000 से ज्यादा रन बनाए। उन्होंने सत्र के अंत में डरहम के खिलाफ चार दिवसीय मैच में 96 गेंदों में शतक लगाया था। उन्होंने इसके अलावा सात अर्धशतक भी लगाए थे। उन्होंने लंकाशायर के खिलाफ वनडे मैच में 265 रनों का पीछा करते हुए 107 रनों की धमाकेदार पारी भी खेली थी, लेकिन उनकी टीम चार रन से हार गई। हालांकि, वह 1992 के बाद कभी काउंटी नहीं खेले।

सोली एडम कहते हैं कि उन्हें यॉर्कशायर से खिलाने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े। मैंने क्लब वालों से कई मुलाकात कीं और उनसे बहुत झगड़ा करना पड़ा। अंत में वे माने। फिर मैंने सचिन तेंदुलकर का नाम प्रस्तावित किया। सचिन ने अनुरोध किया था कि सोली भाई मुझे अलग घर देना, लेकिन ड्यूजबरी में ही रहना है। सचिन जब यॉर्कशायर के लिए पहला मैच खेलने गए तो हम लोग साथ में ही गए थे। सचिन ने कहा था कि मुझे शतक बनाना है। पहले उसने 50 रन बनाए, फिर 60, फिर 70, फिर 80 और अंत में 86 रन पर आउट हो गया। उनकी आखिरी रात मुझे याद है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा कि सोली भाई मैं जा रहा हूं, आपके और भाभी के पैर छूने आया हूं।

रोहित ने हर बार पहले से अच्छा प्रदर्शन किया

के श्रीकांत
कलम से

भारत की यह मौजूदा टीम बेहद मजबूत है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसमें ओपनर रोहित शर्मा का योगदान बेहद अहम है। पिछले तीन विश्व कप को देखें तो मुंबई के इस बल्लेबाज ने हर बार पहले से अधिक बेहतर प्रदर्शन किया है। मैं आंकड़ों का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन ये कभी झूठ नहीं बोलते।

रोहित ने अब यह आदत बना ली है कि जब भी वह 50 रन पार करते हैं, 10 में से छह बार इसे शतक में तब्दील कर देते हैं। कई बड़ी टीमों के खिलाफ भारत के दबदबे भरे प्रदर्शन में रोहित का यह प्रदर्शन बेहद अहम रहा है। इसमें कप्तान विराट कोहली की निरंतरता को जोड़ दें तो यह कमाल का शीर्ष क्रम है। इस दायें हाथ के बल्लेबाज रोहित की बल्लेबाजी का एक शानदार पहलू यह भी है कि वह बेहद सहजता से गियर चेंज कर लेते हैं। ऐसे दिन जब वह अच्छी शुरुआत नहीं कर पाते तो वह खुद को क्रीज पर जमने के लिए वक्त देते हैं और उसके बाद उन्मुक्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। वह यहीं पर नहीं रुकते, एक बार शतक पूरा करने के बाद तो वह टॉप गियर में बल्लेबाजी करने लगते हैं।

मेरे ख्याल से जब रोहित 50-60 गेंदें खेल लेते हैं तो काफी खतरनाक हो जाते हैं। इसके बाद इस बल्लेबाज को रोकना मुश्किल हो जाता है। इस दौरान वह जितने भी रन बनाते हैं उनका बहुत मतलब नहीं होता क्योंकि उन जैसा बल्लेबाज अंत तक सारा अंतर खत्म कर देता है। एक विश्व कप में चार शतक लगाना जबर्दस्त प्रदर्शन है। महान कुमार संगकारा के लिए पूरा सम्मान है, लेकिन मौजूदा विश्व कप में बल्लेबाजों के लिए हालात थोड़े ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं। पूरा देश उम्मीद और प्रार्थना कर रहा है कि रोहित की यह शानदार फॉर्म नॉकआउट मुकाबलों में भी जारी रहे। जिस तरह वह बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस बात की उम्मीद ज्यादा ही है कि वह इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे।

श्रीलंका के खिलाफ भारत का मुकाबला औपचारिकता भर है। इससे दोनों टीमों के लिए ही चीजें नहीं बदलेंगी। हालांकि टीम इंडिया सेमीफाइनल से पहले सही संयोजन अपनाने पर काम कर सकती है। जितना हम कोहली को जानते हैं, वह इस बात को सुनिश्चित करने पर जोर देंगे कि टीम इंडिया की लय बिगड़नी नहीं चाहिए। (टीसीएम)

फाइनल की राह आसान करेगी श्रीलंका पर जीत

श्रीलंका से जीतने पर अंक तालिका में नंबर वन बन सकता है भारत सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से नहीं भिड़ना चाहेगी टीम इंडिया

विश्व कप में दैनिक जागरण
अभिषेक त्रिपाठी ● लीड्स

बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला जीतने के बाद भारतीय टीम ने सेमीफाइनल की सीट पक्की कर ली है और इसके बाद उसके खिलाड़ी आराम फरमा रहे हैं। भारतीय टीम ने गुरुवार को अभ्यास नहीं किया, जबकि श्रीलंकाई टीम ने पसीना बहाया। भारतीय टीम बुधवार को ही लीड्स पहुंच गई थी और उसकी तरफ से पहले बताया गया कि गुरुवार को कोई अभ्यास नहीं होगा। हालांकि, बाद में मीडिया मैनेजर की तरफ से संदेशा आया कि टीम इंडिया लीड्स यूनिवर्सिटी के मैदान में वैकल्पिक अभ्यास करेगी। हेडिंग्ले क्रिकेट मैदान में अफगानिस्तान-वेस्टइंडीज मैच होने के कारण टीम वहां अभ्यास नहीं कर सकती थी। हालांकि, उसके कुछ देर बाद ही फिर बताया गया कि टीम अभ्यास नहीं करेगी।

भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले से पहले गुरुवार को ट्रेनिंग छोड़कर लीड्स शहर को घूमने का लुत्फ उठाया। खिलाड़ियों ने इसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं। हार्दिक पांड्या द्वारा शेयर की गई इस तस्वीर में उनके साथ साथी खिलाड़ी महेंद्र सिंह धौनी, मयंक अग्रवाल, रिषभ पंत और जसप्रीत बुमराह ● इंस्टाग्राम

सेमीफाइनल	तारीख	स्थान	टीमें
पहला	09 जुलाई	मैनचेस्टर	नंबर-1 बनाम नंबर-4
दूसरा	11 जुलाई	बर्मिंघम	नंबर-2 बनाम नंबर-3

विश्व कप अंक तालिका

	देश	मैच	जीते	हारे	ड्रॉ	अंक	नेट रनरेट
	ऑस्ट्रेलिया	8	7	1	0	14	1.000
	भारत	8	6	1	1	13	0.811
	इंग्लैंड	9	6	3	0	12	1.152
	न्यूजीलैंड	9	5	3	1	11	0.173
	पाकिस्तान	8	4	3	1	9	-0.792
	श्रीलंका	8	3	3	2	8	-0.934
	बांग्लादेश	8	3	4	1	7	-0.195
	द. अफ्रीका	8	2	5	1	5	-0.080
	वेस्टइंडीज	8	1	6	1	3	-0.335
	अफगानिस्तान	8	0	8	0	0	-1.418

क्योंकि यह मैच टीम के सेमीफाइनल नहीं, बल्कि फाइनल मुकाबले की राह आसान करेगा। भारत के अभी आठ मैचों में 13 अंक हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के इतने ही मैचों में 14 अंक हैं। इनमें से जो भी टीम नंबर वन रहेगी उसे कमजोर न्यूजीलैंड या पाकिस्तान (अगर चमत्कार से सेमीफाइनल में पहुंची) से भिड़ना होगा।

अगर भारत शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ अपने आखिरी लीग मुकाबले में जीत हासिल करता है तो उसके 15 अंकों के साथ नंबर वन के तौर पर सेमीफाइनल में पहुंचने का एक मौका होगा। हालांकि, इसके लिए शनिवार को दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। अंक तालिका में नंबर वन रहने पर भारत की टक्कर संभवतः चौथे नंबर पर रहने वाली न्यूजीलैंड से होगी। पाकिस्तान टीम के पास भी चौथे नंबर की टीम बनकर सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका है, लेकिन उसके लिए ऐसा करना लगभग असंभव सा है। उसे शुक्रवार को बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में कम से कम पहले बल्लेबाजी करते हुए 350 रन बनाने होंगे और 312 रनों की जीत करनी होगी। अंतरराष्ट्रीय वनडे में आज तक किसी ने भी दूसरी टीम पर 300 रनों की जीत हासिल नहीं की है। यही नहीं, बांग्लादेश के पहले बल्लेबाजी करते ही पाकिस्तान की संभावनाएं पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। भारत अंक तालिका में तभी नंबर वन रहेगा, हालांकि यह तभी होगा जब ऑस्ट्रेलिया अपने आखिरी लीग मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से हार जाए। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया दूसरे और इंग्लैंड तीसरे नंबर पर रहेगा। इस स्थिति में भारत को विश्व कप की इन दो खतरनाक टीमों से नहीं भिड़ना होगा। मेजबान इंग्लैंड ने आखिरी दो मैच जीतकर बता दिए हैं कि वह घरेलू मैचों में कितने खतरनाक हैं। सुनील गावस्कर ने दैनिक जागरण से कहा था कि जब भी घरेलू टीम कहीं खेलती है तो परिस्थितियों के साथ मैदानकर्मियों का साथ उसे कहीं ना कहीं मिलता है। गावस्कर का उदाहरण बर्मिंघम में भारत और इंग्लैंड मैच में देखने को भी मिला था। इंग्लिश टीम के लिए उस करो या मरो के मैच में खेलने के लिए ऐसी किनारे की पिच दी गई थी जो उसके ताबड़तोड़ बल्लेबाजों के लिए तो मुफीद थी ही साथ उससे एक तरफ की बाउंड्री 59 मीटर छोटी हो गई थी। अंग्रेज बल्लेबाजों ने उसी को निशाना बनाते हुए भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ 13 छक्के मारे थे। वहीं, अगर पांच बार की विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करें तो यह टीम विश्व कप में कितनी खतरनाक हो जाती है उसका उदाहरण इस टूर्नामेंट में उसका प्रदर्शन है। विश्व कप से पहले इस टीम को खिताब का दावेदार नहीं माना जा रहा था, लेकिन इंग्लैंड पहुंचते ही उसने कहर बरपाना शुरू कर दिया और अभी तक यह टीम सिर्फ एक मुकाबला हारी है। वह भी भारतीय टीम ने उसे हराया था, लेकिन विराट सेना कम से कम सेमीफाइनल में तो इस टीम से नहीं भिड़ना चाहेगी। भारत और न्यूजीलैंड की भिड़ंत इस विश्व कप में अब तक नहीं हुई है क्योंकि दोनों के बीच नॉटिंघम में होने वाला मुकाबला बारिश के कारण धुल गया था।

ऑस्ट्रेलिया नंबर वन रहा तो : अगर ऑस्ट्रेलिया ने अपने आखिरी लीग मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया तो यह टीम 16 अंकों के साथ सीधे नंबर वन हो जाएगी। ऐसी स्थिति में भारत अपना आखिरी मुकाबला जीतने के बावजूद दूसरे नंबर पर रहेगी और उसे बर्मिंघम में दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ना होगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टक्कर चौथे नंबर की टीम से होगी।

कमजोर पहलुओं को दूर करने का समय : दुनिया की नंबर वन भारतीय टीम के लिए श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला सेमीफाइनल की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही उसे इस मैच के जरिये अपनी कमजोरियों को भी दूर करना होगा। भारत का मध्य क्रम अभी भी चिंता का विषय है। विराट एक बार फिर श्रीलंका के खिलाफ यह चेक कर सकते हैं कि सेमीफाइनल में उन्हें किस टीम के साथ उतरना है। भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ पिछले मैच में स्पिनर कुलदीप यादव और मध्य क्रम के बल्लेबाज केदार जाधव की जगह दिनेश कार्तिक और तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को शामिल किया था। शुरुआती मैचों में खेलकर चोट के कारण बाहर होने वाले भुवी ने अच्छी वापसी की, जबकि कार्तिक कुछ खास नहीं कर सके। ऐसे में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ मैच में एक बार फिर यह जांच सकती है कि तड़कते-भड़कते सूरज के नीचे वह तीन तेज गेंदबाज और एक स्पिनर के विकल्प के साथ उतरेगी या दो तेज गेंदबाज और दो स्पिनर का संयोजन ही उसके लिए ठीक होगा क्योंकि इस मुकाबले के बाद उसे सीधे सेमीफाइनल खेलना होगा, जहां पर कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा।

रोहित शर्मा टूर्नामेंट के अंत तक शानदार खेलेंगे

वीवीएस लक्ष्मण
वेरी-वेरी स्पेशल

भारत को इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को मिली हार के बाद तुरंत ही कुछ मामलों में सुधार करना था और यह देखकर अच्छा लगा कि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में इन गलतियों को ठीक किया और सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत के इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 10 ओवरों में लक्ष्य का पीछा करने के इरादे पर काफी सवाल खड़े हुए थे। यह भी आश्चर्य पूर्ण था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा शुरुआती 10 ओवर में मात्र 28 रन ही निकाल पाए थे। जैसा कि पिचें सूखी हो रही हैं और पुरानी मुलायम गेंद को मारना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ देखकर अच्छा लगा कि रोहित ने शानदार प्रदर्शन किया। रोहित अपने शॉट खेलते वक्त आक्रामक थे। उन्होंने अपनी निरंतरता विश्व कप में चौथे शतक के रूप में तब्दील की। मैं आश्वस्त हूं कि वह टूर्नामेंट के अंत तक इस निरंतरता को जारी रखेंगे। इसी समय केएल राहुल को और भी ज्यादा सक्रिय होना होगा। विशेष रूप से बांग्लादेश के खिलाफ जब वह रोहित के जाते ही कुछ देर बाद आउट हो गए। एक सेट बल्लेबाज के तौर पर उन्हें 40 ओवर तक खेलना चाहिए था। रिषभ पंत काफी अनुभव के साथ खेले, जब तीन विकेट गिर गए थे। यह उनकी ऊर्जा और दृष्टिकोण का नतीजा था कि भारत 314 रनों तक पहुंच पाया। यदि कोई टीम इस कम हुए लक्ष्य का सफल पीछा करने के लिए डरा रही थी तो वह बांग्लादेश ही थी क्योंकि उनके पास अनुभवी बल्लेबाज थे। हालांकि भारतीय तेज गेंदबाजों ने अच्छा काम किया। तब भी जब शाकिब ने एक और अच्छी पारी खेली। मैच भारत के हाथों में आ चुका था जब वह हार्दिक की गेंद पर आउट हुए। भारत ने पांच गेंदबाजों के साथ जाकर रिस्क लिया था, लेकिन हार्दिक ने मैदान का इस्तेमाल करके, कटर गेंद डालकर बेहद खूबसूरती के साथ गेंदबाजी की। शब्बीर रहमान और युवा सैफुद्दीन ने कई बार भारतीय टीम को डरा दिया था, लेकिन विराट के पास जसप्रीत बुमराह थे और उन्होंने निराश नहीं किया। भारत ने कुलदीप के स्थान पर भुवनेश्वर को लाकर अच्छा काम किया, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ मैं सातवें बल्लेबाज के रूप में दिनेश की जगह जडेजा को देखना चाहता हूं।

चमत्कार की चाह में उतरेगा पाकिस्तान

अंतिम लीग मुकाबले में आज होगा बांग्लादेश से सामना, पहले बल्लेबाजी करने पर ही बनेगी पाक के लिए गणितीय संभावना

लंदन, प्रेट्र : पूर्व चैंपियन पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में जगह बनाना अब महज गणितीय संभावना है, क्योंकि इसके हिसाब से विश्व कप के अंतिम-चार में प्रवेश करने के लिए उसे शुक्रवार को यहां होने वाले मैच में बांग्लादेश पर असंभव जीत हासिल करनी होगी।

पाक का विश्व कप में अभियान 1992 विश्व कप चरण में टीम के प्रदर्शन के समान दिख रहा था, लेकिन भारत के इंग्लैंड से हारने से उसकी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद को करारा झटका लगा और जब बुधवार को न्यूजीलैंड की टीम मेजबानों से हार गई तो उसके लिए यह उम्मीद बिलकुल क्षीण हो गई। अब यह मामला जोड़-घटाव मात्र रह गया है और ऐसा तभी हो सकता है जब पाक टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करे, क्योंकि अगर पाकिस्तान टॉस हार गया और उसे क्षेत्ररक्षण के लिए कहा जाता है तो पहली गेंद खेलने से पहले ही उसके लिए सेमीफाइनल की उम्मीद खत्म हो जाएगी।

न्यूजीलैंड के इंग्लैंड से 119 रन से हारने के बाद उसके नौ मैचों में 11 अंक हैं, लेकिन इस करारी हार के बावजूद उसका नेट रन रेट पाकिस्तान की तुलना में काफी अधिक है जो प्लस 0.175 है, जबकि पाकिस्तान का नेट रन रेट माइनस 0.792 है।

आठ मैचों में नौ अंक से पांचवें स्थान पर बैठी पाकिस्तानी टीम को अगर न्यूजीलैंड को पछाड़ना है तो उसे टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 350 रन बनाकर बांग्लादेश को 311 रन से हराना होगा या फिर 400 रन का स्कोर खड़ाकर 316 रन से शिकस्त देनी होगी, जो सामान्य हालात में असंभव है।

चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से हारने के बाद पाकिस्तान ने वापसी करते हुए बाबर आजम और हैरिस सोहेल के शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन से दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान को शिकस्त दी। बायें हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी का न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच विकेट झटकने वाला प्रदर्शन भी काफी सकारात्मक रहा जिससे मुहम्मद आमिर की अगुआई वाले गेंदबाजी आक्रमण को पैनापन मिला। वहीं, मौके चूकने वाली बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत प्रदर्शन से घरेलू प्रशंसकों को खुशी का मौका देना चाहेगी जैसा उन्होंने 1999 चरण में किया था। दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार जीत से बांग्लादेश की टीम सातवें स्थान पर है।

टीम ने उन मैचों में अच्छा जच्बा दिखाया है जिसमें उसे हार मिली है और मशरफे मुर्तजा की टीम शुक्रवार को पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी। टीम अपने स्टार ऑलराउंडर शाकिब उल हसन पर काफी निर्भर है जो विश्व कप इतिहास में 10 विकेट झटकने के अलावा 500 रन बनाने वाले एकमात्र क्रिकेटर बन गए हैं। बांग्लादेश ने उनके प्रदर्शन से इस विश्व कप में लगातार 300 रन का आंकड़ा पार किया है। एक तरह से कहा जाए तो इस विश्व कप में बांग्लादेश की टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन को उनके विश्व कप इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वहीं पाकिस्तान के लिए विश्व का सफर इतना खराब नहीं रहा है, लेकिन श्रीलंका के साथ बारिश के कारण रद हुए मुकाबले का उनके अभियान पर खास असर पड़ा। अगर पाक वह मैच जीतती तो उनके 10 अंक होते और 12 अंक लेकर सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका था।

इस विश्व कप में सबसे ज्यादा रन	
पाकिस्तान	
बाबर आजम	378
मुहम्मद हफीज	226
इमाम उल हक	205
बांग्लादेश	
शाकिब अल हसन	542
मुशफिकुर रहीम	351
तमीम इकबाल	227

सबसे ज्यादा विकेट	
पाकिस्तान	
मुहम्मद आमिर	16
शाहीन अफरीदी	10
वहाब रियाज	10
बांग्लादेश	
मुस्तफिजुर रहमान	15
शाकिब अल हसन	11
मुहम्मद सैफुद्दीन	10

अभ्यास सत्र के दौरान फुटबॉल खेलते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज मेहदी हसन मिराज ● एएफपी

36 वनडे मैच हुए हैं अभी तक पाक व बांग्लादेश के बीच। इनमें से पाक ने 31 और बांग्लादेश ने पांच जीते हैं

08 वनडे मैच खेले हैं पाकिस्तान व बांग्लादेश ने तटस्थ स्थल पर एक-दूसरे के खिलाफ हैं

01 वनडे मैच खेला गया है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच इंग्लैंड में। 1999 विश्व कप में खेले गए इस मैच में बांग्लादेश ने 62 रन से जीत हासिल की थी। यह इन दोनों टीमों के बीच विश्व कप में खेला गया एकमात्र मुकाबला है

वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान को 23 रनों से दी शिकस्त, 77 रन बनाने वाले शाई होप बने मैन ऑफ द मैच

बिना जीते अनफिट अफगानियों का सफर समाप्त

अभिषेक त्रिपाठी ● लीड्स

विश्व कप क्या होता है और अंग्रेज खेलों को कितना प्यार करते हैं इसका नजारा गुरुवार को हेडिंग्ले क्रिकेट मैदान में देखने को मिला। वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान की टीमें पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी थीं और सबको लग रहा था कि उनके मैच के दौरान मैदान खाली ही रहेगा, लेकिन 17000 दर्शक क्षमता वाले इस मैदान में करीब 14000 सीटें भरी थीं। यही नहीं, वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के प्रशंसकों की संख्या कम होने और मैच के बोरिंग होने के बावजूद घरेलू प्रशंसकों ने मैदान को भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वेस्टइंडीज की टीम ने भी इन दर्शकों का मनोरंजन करते हुए पहले खेलते हुए 23 चौकों और 12 छक्कों का मुजाहिरा किया। इसकी बदौलत वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 311 रन बनाए। इसमें अफगानिस्तान की घटिया क्षेत्ररक्षण ने भी अहम योगदान निभाया। उन्होंने चार-पांच कैच छोड़े और कई चौके गंवाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 50 ओवर में 288 रन बनाकर पवेलियन लौट गई और 23 रनों से विश्व कप का अपना आखिरी मुकाबला हार गई। अफगानिस्तान की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज इकराम अलीखिल 86 रन बनाकर आउट हुए। उनका विकेट क्रिस गेल ने लिया। वह विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा निजी स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में भारत के सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा जिन्होंने 1992 विश्व कप में 84 रन बनाए थे। अलीखिल ने रहमत शाह के साथ दूसरे विकेट के लिए 133 रनों की साझेदारी की। शाह 62 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वेस्टइंडीज की तरफ से केमार रोच ने दो विकेट झटके।

वहीं, आइसीसी के एक अधिकारी ने कहा कि भारत के मैचों की टिकट महंगी थीं और उसमें मारामारी भी ज्यादा थी क्योंकि यहां पर भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों की तादाद ज्यादा है। यही कारण है कि इंग्लिश प्रशंसकों ने उन मैचों का रुख किया जिनकी टिकट सस्ती हैं। ऐसे में जिन लोगों को अपने देश में विश्व कप का मैच देखना था उन्होंने इंग्लैंड के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, वेस्टइंडीज जैसी टीमों का रुख किया। चलो अब बात करते हैं आज के मैच की। हेडिंग्ले में वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन खुद को यूनिवर्सल बॉस कहने वाले क्रिस गेल (07) के छठे ओवर में ही आउट होने के बाद सभी निराश हो गए क्योंकि यहां पर लोगों को लग रहा था कि वह अच्छा मनोरंजन करेंगे, लेकिन इसके बाद इविन लुइस (58) और शाई होप (77) ने वेस्टइंडीज के लिए बड़े स्कोर का मंच तैयार किया था, लेकिन उसका मध्य क्रम इसका फायदा नहीं उठा पाया। होप ने 92 गेंदों पर छह चौके और दो छक्के लगाए। वहीं, लुइस ने 78 गेंदें खेलीं और छह चौकों के अलावा दो छक्के भी जड़े। इन दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 88 रनों की साझेदारी की। राशिद खान ने लुइस की पारी खत्म की। फिर होप और शिमरोन हेटमायर (39) ने मिलकर एक और साझेदारी की। होप की अपेक्षा हेटमायर तेज खेल रहे थे। उन्होंने 31 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्के लगाए।

गेल को आउट करने वाले जादरान ने हेटमायर को भी आउट किया। फिर नबी ने होप को राशिद के हाथों कैच करा विंडीज का स्कोर चार विकेट पर 192 रन कर दिया। एक समय लग रहा था कि अफगानिस्तान किसी भी सूरत में वेस्टइंडीज को 270-280 के पार नहीं जाने देगा, लेकिन निकोलस पूरन (58) और जेसन होल्डर (45) ने तेजी से रन बनाते हुए टीम का स्कोर 300 के पार पहुंचाया। आखिरी ओवर में चार गेंदों पर दो चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 14 रन बनाने वाले कार्लोस ब्रेथवेट ने भी उम्दा बल्लेबाजी की। पूरन ने 43 गेंदों की अपनी पारी में छह चौके और एक छक्का मारा। होल्डर ने 34 गेंदों का सामना कर एक चौका और चार छक्के मारे। अफगानिस्तान के लिए दौलत जादरान ने दो विकेट लिए। सैयद शिरजाद, मुहम्मद नबी, राशिद खान को एक-एक सफलता मिली। इस मैच के लिए कैरेबियाई टीम में दो बदलाव किए। इविन लुइस और केमार रोच टीम में आए, जबकि सुनील अंब्रीश और शेनॉन गेब्रियल अंतिम-11 से बाहर किया गया। वहीं अफगानिस्तान की टीम में हामिद हसन और शाहिदी की जगह दौलत और शिरजाद की एंट्री हुई।

स्कोर बोर्ड

टॉस : वेस्टइंडीज (बल्लेबाजी)

वेस्टइंडीज **311/6** (50 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
क्रिस गेल का. अलीखिल बो. जादरान	07	18	01	00
इविन लुइस का. नबी बो. राशिद	58	78	06	02
शाई होप का. राशिद बो. नबी	77	92	06	02
हेटमायर का. सब (नूर) बो. जादरान	39	31	03	02
निकोलस पूरन रन आउट (अलीखिल)	58	43	06	01
होल्डर का. जादरान बो. शिरजाद	45	34	01	04
कार्लोस ब्रेथवेट नाबाद	14	04	02	01
फेबियान एलेन नाबाद	00	00	00	00
अतिरिक्त : (लेबा-4, वा-9) 13				
कुल : 50 ओवर में छह विकेट पर 311 रन				

विकेट पतन : 1-21 (क्रिस गेल, 5.3), 2-109 (लुइस, 24.5), 3-174 (हेटमायर, 34.5), 4-192 (होप, 37.4), 5-297 (पूरन, 49.1), 6-297 (होल्डर, 49.2)

गेंदबाजी :
मुजीब उर रहमान 10-0-52-0
दौलत जादरान 9-1-73-2
सैयद शिरजाद 8-0-56-1
गुलबदीन नायब 3-0-18-0
मुहम्मद नबी 10-0-56-1
राशिद खान 10-0-52-1

लीड्स में गुरुवार को अफगानिस्तान के खिलाफ अर्धशतक लगाने के बाद शाई होप ● एएफपी

पूरा देश आपके प्रदर्शन से प्रभावित है। आपका जुनून, कौशल और एकजुटता पूरे मैच के दौरान सराहनीय रहती है। उम्मीद भारतीय टीम इस विश्व कप ट्रॉफी को जीतकर ही घर लौटेगी।
– किरण रिजिजू, खेल मंत्री

एनसीए के मुखिया बनने को तैयार द्रविड़

बेंगलुरु : भारत के पूर्व कप्तान और इंडिया-ए तथा अंडर-19 टीम के कोच राहुल द्रविड़ का राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) का मुखिया बनने का रास्ता साफ हो गया है। द्रविड़ जल्दी ही एनसीए के हेड ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन बना दिए जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) का लक्ष्य एनसीए को भारत के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तब्दील करने का है। द्रविड़ कितने साल तक यहां रहेंगे इस पर अभी चीजें साफी नहीं हुई हैं।

44 साल बाद कोपा अमेरिका के फाइनल में पेरू

फुटबॉल डायरी ▶ चिली को सेमीफाइनल में 3–0 से शिकस्त देकर किया बड़ा उलटफेर

जीत के बाद जश्न मनाते पेरू के खिलाड़ी। एपी

खिताबी मुकाबले में ब्राजील की टीम से होगा सामना

पोर्टो अलेग्रे (ब्राजील), एएफपी : पेरू की फुटबॉल टीम ने कोपा अमेरिका कप के सेमीफाइनल में बड़ा उलटफेर करते हुए लगातार दो बार की गत चैंपियन चिली को 3-0 से शिकस्त देकर 44 साल में पहली बार फाइनल में जगह पक्की की। इससे पहले पेरू की टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल में 1975 में पहुंची थी, जहां उसे जीत हासिल हुई थी।

मुकाबले में एडिसन फ्लोरेस, योशिमार योतुन और पाओलो गुइरेरो के गोल के दम पर पेरू ने चिली को खिताबी हैट्रिक को पूरा करने के सपने को तोड़ दिया। फाइनल में उसका सामना ब्राजील से रविवार को होगा जिसने पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना को हराया था। ब्राजील ने ग्रुप चरण में पेरू को 5-0 से हराया था। चिली 2015 और 2016 में लगातार दो फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर इस टूर्नामेंट का चैंपियन बना था। पिछले दो बार टूर्नामेंटों में फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीमें (अर्जेंटीना और चिली) शनिवार को तीसरे स्थान के मैच के लिए भिड़ेंगी। ग्रुप चरण में ब्राजील से 0-5 से हारने के बाद किसी को पेरू से ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। पेरू के गोलकीपर पेड्रो गलेसी ने इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने एक पेनाल्टी रोकने के साथ कई शानदार बचाव किए। गलेसी ने क्वार्टर फाइनल में भी उरुग्वे के खिलाफ पेनाल्टी शूटआउट में सुपरस्टार स्ट्राइकर लुइस सुआरेज की स्पॉट किक को रोककर टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी।

मैच की शुरुआत पेरू के लिए अच्छी रही। कारिलो ने एक शानदार पास फ्लोरेस को दिया और उन्होंने गोलकीपर बॉक्स पर से अपने बायें पैर से 21वें मिनट में शानदार गोल करके टीम को मैच में 1-0 से आगे कर दिया। इसके बाद 38वें मिनट में योतुन ने टीम की बढ़त को दोगुना कर दिया। चिली के गोलकीपर कारिलो से गेंद को अपने कब्जे में लेने के चक्कर में अपने किले को छोड़कर कॉर्नर तक पहुंच गए जिसका फायदा कारिलो ने उठाया और गेंद सीधा यातुन को पास की। यातुन को कोई गलती किए बिना गेंद को गोल पोस्ट में भेज दिया। पहले हाफ पूरी तरह से पेरू के पक्ष में रहा। दूसरे हाफ में भी पेरू ने अपने किले की अच्छे से रक्षा की, जबकि चिली एक गोल खा बैठा। इंजुरी टाइम (90+1) में गुइरेरो ने पेनाल्टी एरिया के पास से चिली गोलकीपर और एक डिफेंडर को छकाकर टीम की बढ़त 3-0 से मजबूत कर दी। हालांकि, इसके बाद चिली के पास मैच में खाता खोलने का बेहतरीन मौका आया, जब उसे इंजुरी टाइम (90+4वें मिनट) में पेनाल्टी मिली थी।

एडुआर्डो वर्गास ने गेंद पर किक लगाई, लेकिन पेरू के गोलकीपर गलेसी ने इसका बचाव करके चिली टीम को मैच में एक गोल भी नहीं होने दिया। मैच के बाद पेरू के खिलाड़ी यातुन ने कहा, 'ब्राजील को हराना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस खेल में कुछ भी हो सकता है। अब फाइनल मैच होगा और इसे जीतने की हम कोशिश करेंगे। हमने इस टूर्नामेंट कड़ी मेहनत की थी।'

खिताबी मुकाबले में नीदरलैंड्स का सामना अमेरिका से

ल्योन, रायटर : नीदरलैंड्स की टीम ने सेमीफाइनल में स्वीडन को अतिरिक्त समय में 1-0 से हराकर महिला विश्व कप के फाइनल में पहली बार जगह बनाई। निर्धारित समय तक स्कोर 0-0 था, जिससे इस सेमीफाइनल मैच का नतीजा निकालने के लिए अतिरिक्त समय का सहारा लिया गया, जहां नीदरलैंड्स ने बाजी मारी। मैच का एकमात्र गोल जैकी ग्रोएन ने 99वें मिनट में किया। नीदरलैंड्स का फाइनल में मुकाबला टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा तीन बार खिताब जीतने वाली और गत विजेता अमेरिका से रविवार को होगा।

मैनेजर के तौर पर लैंपार्ड की चेल्सी में वापसी

लंदन, आइएएनएस : इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब चेल्सी ने अपने पूर्व मिडफील्डर फ्रैंक लैंपार्ड को तीन साल के लिए अपना कोच नियुक्त कर दिया। लैंपार्ड इस पद पर मौरिजियो सारी का स्थान लेंगे, जिन्होंने जुवेंटस का कोच बनने के लिए पिछले महीने चेल्सी का साथ छोड़ दिया था। लैंपार्ड ने कहा, 'मुख्य मैनेजर के तौर पर चेल्सी लौटकर मुझे खुशी हो रही है। हर कोई क्लब के साथ मेरे प्यार भरे रिश्ते को जानता है। मैंने इस क्लब के साथ बेहतरीन पल बिताए हैं और अब नई भूमिका में मेरा प्रथम लक्ष्य नए सत्र के लिए टीम को तैयार करना है। मैं यहां कठिन मेहनत के लिए आया हूं और क्लब को अपेक्षित सफलता दिलाना चाहता हूं।' लैंपार्ड ने एक खिलाड़ी के तौर पर चेल्सी के साथ 13 साल बिताए हैं। 41 साल के लैंपार्ड ने चेल्सी के लिए कुल 648 मैच खेले। लैंपार्ड ने इंग्लैंड के लिए कुल 106 मैच खेले और 29 गोल किए।

निशिकोरी और ईवांस तीसरे दौर में

मैच के दौरान शॉट खेलते जापान के केई निशिकोरी। एपी

लंदन, एएफपी : जापान के पुरुष टेनिस खिलाड़ी केई निशिकोरी और ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल इवांस ने गुरुवार को साल के तीसरे ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट विंबलडन के तीसरे दौर में जगह बनाई। विश्व के सातवें नंबर के खिलाड़ी निशिकोरी सिंगल्स के दूसरे दौर के मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन के कैमरून नूरी को मात देकर अगले दौर में पहुंच गए। वहीं, इवांस ने जॉर्जिया के निकोलस बासिलशविली को हराकर अपना विजयी क्रम जारी रखा।

निशिकोरी ने नूरी को एक घंटे 48 मिनट तक चले आसान मुकाबले में 6-4, 6-4, 6-0 से हराया। वहीं, ईवांस ने 6-3, 6-2, 7-6 से जीत हासिल करते हुए तीसरे दौर में कदम रखा। पुरुष सिंगल्स वर्ग में अमेरिका के सैम क्वेरी भी दूसरे दौर की बाधा पार करने में सफल रहे। उन्होंने दूसरे दौर के मैच में रूस के आंद्रे रुबलेव को 6-3, 6-2, 6-3 से हराया। जर्मनी के ज्यां लेनार्ड स्ट्रफ भी इस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में पहुंचने में सफल रहे। स्ट्रफ ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज पर 6-4, 6-3, 5-7, 7-6 से जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के जॉन मिलमैन ने भी सर्बिया के लास्लो डजेरे को 6-3, 6-2, 6-1 से मात देकर तीसरे दौर में कदम रखा। पिछले साल फाइनल में पहुंचे केविन पीटरसन ने सर्बिया के जांको टिप्सारेविक पर 6-4, 6-7, 6-1, 6-4 की जीत से अगले दौर में प्रवेश किया।

बार्टी अगले दौर में, गॉफ का जादू बरकरार : विश्व की नंबर एक महिला खिलाड़ी एश्ले बार्टी की सेरेना विलियम्स के बाद एक साल में फ्रेंच ओपन और विंबलडन में जीतने की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनने की उम्मीद गुरुवार को यहां बेल्जियम की एलिसन वान उइतवांक पर दूसरे दौर की जीत से बरकरार रही। सेरेना ने 2015 में यह उपलब्धि हासिल की। 23 साल की बार्टी ने एलिसन वान उइतवांक को 6-1, 6-3 से शिकस्त दी, जिसने 2017 की चैंपियन गर्बाइने मुगुरुजा को हराकर बाहर किया था। अगर बार्टी रोलां गैरां और विंबलडन खिताब जीतने की उपलब्धि हासिल कर लेती हैं तो वह ऐसा करने वाली आठवीं महिला खिलाड़ी बन जाएंगी। वहीं, 2017 अमेरिकी ओपन चैंपियन स्लोन स्टीफंस ने चीन की वांग यफान पर 6-0, 6-2 से शिकस्त दी। अमेरिकी खिलाड़ी कोरी गॉफ ने शानदार पदार्पण जारी रखते हुए तीसरे दौर में पहुंचने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। गॉफ महज 15 साल की हैं और क्वालीफाइंग की बाधा पार करने के बाद मुख्य दौर में पहुंची हैं। 1991 के बाद वह पहली युवा खिलाड़ी हैं जो विंबलडन के तीसरे दौर में पहुंची, उन्होंने पहले दौर में पांच बार की चैंपियन वीनस विलियम्स को हराकर उलटफेर किया था। 28 साल पहले 15 साल की जेनिफर कैप्रियाती सेमीफाइनल तक पहुंची थीं। गॉफ ने 2017 में सेमीफाइनल तक पहुंची स्लोवाकिया की मागडालेना रिबारिकोवा को दूसरे दौर के मैच में 6-3, 6-3 से शिकस्त दी।

टॉमिक को नहीं दी गई पुरस्कार राशि : ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बर्नार्ड टॉमिक को विंबलडन के पहले दौर का मुकाबला महज 58 मिनट में जीत की कोशिश किए बिना गंवाने के आरोप में 57,000 डॉलर (39 लाख रुपये) की इनामी राशि से वंचित कर दिया गया। टॉमिक पर इससे पहले भी मैच के दौरान जीतने की कोशिश नहीं करने के आरोप लग चुके हैं। मंगलवार को विंबलडन में ऑस्ट्रेलिया का यह खिलाड़ी महज 58 मिनट में फ्रांस के जो विल्फ्रेड सोंगा से 2-6, 1-6, 4-6 से हार गया।

विंबलडन

▶ जापानी खिलाड़ी केई ने दूसरे दौर के मैच में नूरी दी मात, डेनियल ने जॉर्जिया के निकोलस को हराया

हिमा ने पोलैंड में जीता स्वर्ण, मुख्यमंत्री सोनोवाल ने दी बधाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : जकार्ता एशियन गेम्स की चार गुणा 400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की फर्राटा धावक हिमा दास ने पोलैंड के पोंजान एथलेटिक्स ग्रां प्रि के 200 मीटर रेस में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। हिमा ने अपनी आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने 200 मीटर की इस रेस में 23.65 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। उनके अलावा भारत की ही वीके विस्माया ने 23.75 सेकेंड का समय निकालकर कांस्य पदक हासिल किया।

हिमा की इस उपलब्धि पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अपने राज्य की इस खिलाड़ी को बधाई दी है। सोनोवाल ने ट्विटर पर लिखा, पोंजान एथलेटिक्स ग्रां प्री-2019 के 200 मीटर में स्वर्ण पदक पर असम की शानदार स्प्रिंट धाविका हिमादास को बधाई। भविष्य के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 213 रन मेरी सर्वश्रेष्ठ पारी : लारा

मुंबई, प्रेट्र : करीब 20 साल पुराना किस्सा है जब ब्रायन लारा को एक बार तो लगा कि उनका दोस्त भांग खाकर आया है जो वेस्टइंडीज की ऑस्ट्रेलिया पर टेस्ट मैच में जीत की भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन उनके दोस्त की बात सही साबित हुई, क्योंकि बायें हाथ के इस बल्लेबाज ने उस मैच में 213 रन की पारी खेली, जिसे वह अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी आंकते हैं। लारा ने इसका रहस्योद्घाटन यहां एक कार्यक्रम के दौरान किया, जहां उन्हें डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय की ओर से विज्ञान में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया।

▶ **डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय ने ब्रायन को दी विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि**

लारा ने अपने करियर में कई सर्वश्रेष्ठ पारियां खेलीं, जिनमें इंग्लैंड के खिलाफ 375 रन और 400 रन की दो बड़ी पारियां भी शामिल हैं। लेकिन, उनके 213 रन की पारी को चुनने के कई कारण हैं। लारा ने कहा कि हमारा स्कोर एक समय चार विकेट पर 36 रन था, जो बाद में चार विकेट पर 375 हो गया। लारा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने पोर्ट ऑफ स्पेन में पहला टेस्ट मैच 312 रन से जीता था। दूसरा टेस्ट किंग्सटन में खेला जाना था। हम जमैका आए जो कप्तान के रूप में मेरा अंतिम टेस्ट मैच था क्योंकि हम विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीम के खिलाफ खेल रहे थे तथा जमैका के लोगों ने हवाई अड्डे और मैदान पर मेरी खिल्ली उड़ाई थी। यह बहुत बुरा था। टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 259 रन बनाए और पहले दिन का खेल समाप्त होने पर हमारा स्कोर चार विकेट पर 36 रन था। मैं अपने कमरे में बैठा था। जमैका का मेरा एक मित्र आया और उसने कहा कि तुम लोग यह टेस्ट मैच जीत रहे हो। जमैका भांग के लिए भी मशहूर है और मैं जानना चाहता था कि उसने कौन सी भांग खाई है क्योंकि लग ही नहीं रहा था कि हम यह मैच जीत जाएंगे। वेस्टइंडीज ने यह मैच 10 विकेट से जीता था।

कोहली व बाकी बल्लेबाजों में काफी अंतर : लारा

मुंबई, प्रेट्र : ब्रायन लारा ने विराट कोहली की तुलना रन मशीन से करते हुए कहा कि जहां तक विभिन्न प्रारूपों में बल्लेबाजी की बात है तो भारतीय कप्तान दुनिया के बाकी खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा आगे है। हालांकि, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर लारा के सर्वकालिक पसंदीदा खिलाड़ियों में शुमार रहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वर्तमान युग में कोहली सर्वश्रेष्ठ हैं। लारा ने कहा कि वह (कोहली) एक (रन) मशीन है। लेकिन माफ करना तेंदुलकर मेरी पसंद बने रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि खेल के सभी प्रारूपों में कोहली और पूरी दुनिया के बीच में काफी बड़ा अंतर है। रोहित शर्मा ने इस विश्व कप में चार शतक जड़े हों, जॉनी बेयरस्टो या कोई और भी हो, लेकिन अगर आप किसी को टी-20, टी-10, या टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहते हो तो आज वह कोहली होंगे।

डॉक्टरेट की उपाधि के साथ ब्रायन लारा। प्रेट्र

विविध

समलैंगिकों की इच्छा, अपना भी हो बच्चा

सर्वे ▶ गोद लेने का मिले अधिकार या मिल जाए किराए की कोख

जागरण विशेष

अजय दुबे, आगरा

भारत ही नहीं दुनियाभर में समलैंगिकों ने अधिकारों को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी और यह अब भी जारी है। भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता हासिल हो चुकी है। समाज भी कहीं अधिक संवेदनशील और जागरूक हुआ है। लेकिन विवाह बंधन में बंधे समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने की इजाजत नहीं है। भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में इसे लेकर यही स्थिति है। गिनती के कुछ देशों में छूट है, कुछ में शर्तों सहित, लेकिन अधिकांश में नहीं है। सरोगेसी (किराए की कोख) को लेकर भी कानूनी बाधाएं हैं।

समलैंगिक दंपती की यह चाहत कि उनका भी अपना एक बच्चा हो, अब खुलकर सामने है, लेकिन इसे लेकर उन्हें लड़ाई लड़ना पड़ रही है। एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा के सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन विभाग (एसपीएम) द्वारा की गई स्टडी के दौरान यह सामने आया कि भारत में भी समलैंगिक दंपती अब बच्चा गोद लेने या सरोगेसी के जरिये बच्चे की इच्छा रखते हैं। एसएन के एसपीएम विभाग द्वारा समलैंगिक (एमएसएम) के स्वास्थ्य और जिंदगी के प्रति उनकी सोच को लेकर दो वर्ष तक स्टडी की। इसी वर्ष जून में पूरे हुई इस अध्ययन के दौरान समलैंगिकों ने तमाम पहलू साझा किए।

स्टडी से जुड़े डॉक्टर खान इकबाल अकील ने बताया कि 2018 में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलने के बाद से इस समुदाय की सोच में बड़ा बदलाव हुआ है। समलैंगिक चाहते हैं कि उनके प्रति समाज का नजरिया बदले। इसके लिए जरूरी है कि समलैंगिकों को परिवार के साथ जीने का अधिकार मिले। ये तभी संभव है कि वे बच्चा गोद ले सकें या किराए की कोख से अपने बच्चे को जन्म दे सकें।

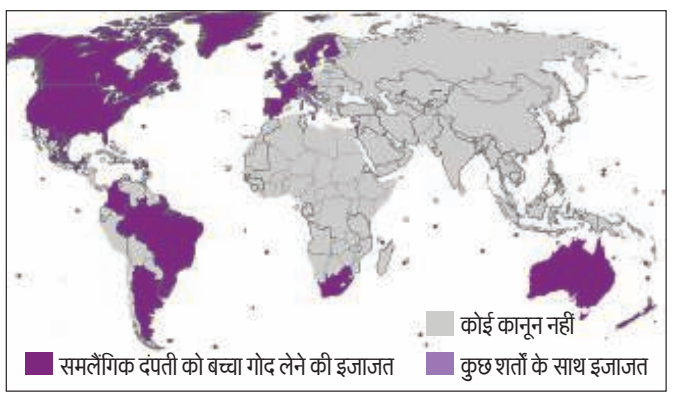

10 से 12 जुलाई तक कुआलालंपुर, मलेशिया में पांचवीं इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑन पब्लिक हेल्थ 2019 का आयोजन हो रहा है। एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा के एसपीएम विभागाध्यक्ष डॉ. एसके मिश्रा के निर्देशन में डॉ. शैलेंद्र चौधरी के नेतृत्व की गई इस स्टडी को प्रस्तुत किया जाएगा। किराए की कोख (सरोगेसी) के लिए जो कानून है, उसके तहत समलैंगिक और सिंगल मेल पैरेंट्स सरोगेसी नहीं करा सकते हैं। सिर्फ सिंगल फीमेल पैरेंट्स ही सरोगेसी करा सकते हैं। समलैंगिक तो बच्चे भी गोद नहीं ले सकते हैं। इधर, मई में हुए वैश्विक सर्वे में अनेक देशों ने समलैंगिकों को ऐसी छूट देने के विरोध में वोट दिया।

प्रतीकात्मक तस्वीर

समलैंगिक किराए की कोख के लिए संपर्क कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनका भी बच्चा हो। मगर उनके लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।
– डॉ. जयदीप मल्होत्रा अध्यक्ष, इंडियन सोसायटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन (आइसीएआर)

समलैंगिक चाहते हैं कि समाज में उनके प्रति सोच बदले। इसके लिए उन्हें भी बच्चे साथ रखने का अधिकार मिले।
– डॉ. शैलेंद्र चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीएम डिपार्टमेंट एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

मध्य प्रदेश के बागली वासियों ने दिया कालीसिंध नदी को नवजीवन

जनता ने खुद किया गहरीकरण, सहेजी विरासत तो जी उठी मृत नदी

विनय बोथरा, देवास

देवास, मध्य प्रदेश के बागली इलाके में कालीसिंध नदी कभी सदानीरा हुआ करती थी। लेकिन लगातार उपेक्षा का शिकार होकर यह पूरी तरह सूख गई। प्रवाह क्षेत्र ऊबड़-खाबड़ बंजर में तब्दील हो गया। ऐसे में जनता ने खुद बीड़ा उठाया और नदी को सहेजना शुरू किया। आज नदी में भरपूर पानी है। मानसून अभी पूरी तरह सक्रिय भी नहीं हुआ है कि नदी की रंगत बदल गई है।

जल संरक्षण

प्रशासन व जनप्रतिनिधियों की लगातार अनदेखी के चलते कालीसिंध पूरी तरह सूख गई थी। इसमें करीब पांच से 10 फीट तक गाद जमा हो गई थी। इधर, बागली नगर सहित आसपास के गांवों में जलसंकट गहरा चुका था। जनता ने कई बार शासन को अवगत भी कराया, लेकिन पिछले 20 सालों की उपेक्षा ने नदी को तबाह कर दिया।

कालीसिंध नदी की दुर्दशा को देख बागली के युवा लामबंद हुए और 23 जनवरी को उद्गम स्थल बरझाई में नदी की सफाई कर इसे पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। चुनाव के कारण काम कुछ समय तक रुका, लेकिन चुनाव के बाद मात्र 10 दिन में ही 2200 ट्रॉली गाद नदी से निकाल बाहर कर दी। इस काम को पूरा करने के लिए लोगों ने चंदा भी किया और दो लाख रुपये जोड़े।

अब क्षेत्रीय जनता रणजीत बांध पर गेट लगाने की जुगत में है ताकि वर्षा जल को रोका जा सके। लोगों का कहना है कि अब सरकार के भरोसे नहीं बैठेंगे, स्वयं के खर्च पर गेट लगाकर अपने बलबूते जल संग्रहण भी करेंगे।

अब तक करीब एक किलोमीटर तक के प्रवाह क्षेत्र को गहरा किया जा चुका है। पहली बरसात में ही इस हिस्से में पांच से छह फीट तक पानी भर गया है। गहरी हो चुकी कालीसिंध में अब बरसात के बाद चार महीने से भी ज्यादा समय तक पानी भरा रह सकता है। वहीं, अब रणजीत बांध में 50 लाख लीटर अतिरिक्त पानी जमा हो सकेगा। यह जल संग्रहण नगर के कुओं, ट्यूबवेल और तालाबों के जलस्तर को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगा।

गहरीकरण के बाद बागली की कालीसिंध नदी हो गई है लबालब। नई दुनिया

चाह लें तो सबकुछ संभव...

नदी के दिन बहुरे तो अब क्षेत्रीयजन कालीसिंध उत्सव मनाने की तैयारी में हैं। कालीसिंध नदी के किनारे पौधारोपण भी किया जाएगा। नदी किनारे अब सुबह-शाम अच्छी चहल-पहल रहने लगी है। पानी से लबालब नदी को देख लोग इतने गदगद हैं कि उनके लिए यह दृश्य किसी सौंदर्य से कम नहीं है। लिहाजा, इस दृश्य को सहेजने के लिए फोटो प्रतियोगिता भी आयोजित करने की योजना है।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

नेलांग घाटी में हिमवीरों ने कैमरे में कैद किया हिम तेंदुआ

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी

गंगोत्री नेशनल पार्क हिम तेंदुआ के लिए मुफीद साबित हो रहा है। गंगोत्री नेशनल पार्क में हाल में हिम तेंदुआ के कई वीडियो सामने आए हैं। इसी सप्ताह नेलांग घाटी में नागा के पास भारत तिब्बत पुलिस सीमा के जवानों (हिमवीरों) ने भी हिम तेंदुआ को वीडियो में कैद किया है। पार्क के कैमरा ट्रैप में भी नर हिम तेंदुआ, मादा हिम तेंदुआ और शवक भी नजर आए हैं। पार्क में हिम तेंदुआ की बढ़ती मौजूदगी से पार्क के अधिकारी और वन्यजीव प्रेमी खुश हैं।

गंगोत्री नेशनल पार्क में हिम तेंदुआ, अरगली भेड़, भरल, भूरा भालू, सेराव, लाल लोमड़ी, कस्तुरी मृग, हिमालयी थार आदि वन्य जीव हैं। हिमालयी मोनाल, पहाड़ी राजालाल, हिमालयी गिद्ध, हिमालयी कुक्कट, हिमालयी तित्तर समेत कई पक्षी यहां प्रवास करते हैं। कुछ समय से यहां हिम तेंदुआ की मौजूदगी बढ़ी है। हिम तेंदुआ सिर्फ गंगोत्री नेशनल पार्क और वन्यजीव संस्थान के कैमरा ट्रैप में ही नहीं, बल्कि पर्यटकों और आइटीबीपी, सेना, सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों ने भी हिम तेंदुआ का दीदार किया हैं।

गंगोत्री नेशनल पार्क के उन निदेशक एनबी शर्मा बताते हैं कि गंगोत्री नेशनल पार्क हिम तेंदुआ के लिए काफी मुफीद है। यहां वन्य जीवों की अच्छी संख्या है। पार्क व वन्य जीव संस्थान की ओर से करीब तीन सौ कैमरा ट्रैप लगाए गए थे। कई कैमरों में हिम तेंदुआ की गतिविधियां कैद हुई हैं। इसी सप्ताह पार्क के नेलांग घाटी में सड़क पर ही हिम तेंदुआ पहुंचा। वहां मौजूद आइटीबीपी के जवानों ने हिम तेंदुआ की वीडियो बनाए।

करीब दो मिनट के दो वीडियो नागा चौकी के पास हाल में ही तैयार किए गए बीआरओ के पुल को पार करते हुए है। वे कहते हैं कि यहां वन्यजीवों का जो संतुलन है वह काफी अच्छा है। हिम तेंदुआ के लिए पार्क में पर्याप्त भोजन मिल पाता है। पार्क के लिए यह बात सुखद है कि यहां स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र है।

▶ **नेलांग घाटी में नागा चौकी के नजदीक आइटीबीप जवानों ने बनाया वीडियो**

▶ **हिम तेंदुओं की बढ़ती संख्या से अधिकारी और वन्यजीव प्रेमी खुश**

गंगोत्री नेशनल पार्क में वन विभाग के कैमरा ट्रैप पर कैद हुई हिम तेंदुए की तस्वीर।

भविष्य बदरी मंदिर के नवनिर्माण के लिए हुआ भूमि पूजन

संवाद सूत्र, जोशीमठ (चमोली) : श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने सुभांई गांव में भगवान भविष्य बदरी के नए मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इसके लिए गुरुवार को भूमि पूजन किया गया। उम्मीद है कि जल्द ही भविष्य बदरी को भव्य मंदिर अस्तित्व में आ जाएगा। सुभांई गांव में समुद्रतल से 2744 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भगवान भविष्य बदरी मंदिर को आद्य शंकराचार्य का स्थापित किया माना जाता है। लेकिन, अब यहां पर जल्द नए मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसके लिए मूलरूप से लखनऊ के रहने वाले और वर्तमान में अमेरिका के टेक्सास शहर निवासी सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक पंकज कुमार आगे आए हैं।

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर में मौसम गर्म रहेगा। हिमाचल प्रदेश के दिन के तापमान में गिरावट आएंगी। कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होगी। दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी हरियाणा और पंजाब में तापमान में गिरावट के साथ कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होगी। शेष भागों का मौसम काफी गर्म रहेगा।

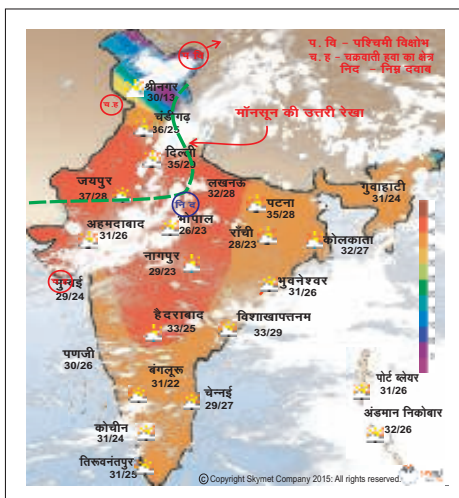

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	30/24/व	अहमदाबाद	35/27/व
कोलकाता	32/27/व	बड़ौदा	31/25/व
चेन्नई	41/30/व	नागपुर	31/24/व
हैदराबाद	34/25/आंबा	इन्दौर	36/24/व
बंगलूरु	32/22/व	राँची	31/26/व
त्रिवेन्द्रम	32/25/व	पटना	34/26/व
गुवाहाटी	29/24/व	जमशेदपुर	33/27/आंबा
गंगटोक	15/10/आंबा	पुणे	24/22/व

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 5 जुलाई 2019
आजकल
14
www.jagran.com

बीबीसी के पहले टीवी न्यूज बुलेटिन का प्रसारण हुआ

1954 में आज ही ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन (बीबीसी) ने अपने पहले टीवी न्यूज बुलेटिन का प्रसारण किया। 20 मिनट लंबे इस प्रसारण में प्रस्तुतकर्ता रिचर्ड बेकर ने देश-विदेश की प्रमुख घटनाओं का सारांश बताया। बीबीसी दुनिया की सबसे पुरानी प्रसारण कंपनी है।

व्यस्क कोशिका से जन्मी पहली स्तनपायी जीव डॉली भेड़

1996 में आज ही स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में पहली बार एक व्यस्क कोशिका से स्तनपायी जीव के क्लोन ने जन्म लिया। यह एक भेड़ थी, जिसे डॉली नाम दिया गया। इसे सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक से बनाया गया था। 14 फरवरी, 2003 को उसका निधन हो गया।

दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट रिटेलर कंपनी अमेजन का गठन हुआ

1994 में आज ही अमेरिकी तकनीकी उद्यमी और निवेशक जेफ बेजोस ने अमेजन कंपनी का गठन किया। वर्तमान में यह कंपनी मुनाफे और बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेलर कंपनी है। इसकी शुरुआत ऑनलाइन बुकस्टोर के तौर पर हुई थी। धीरे-धीरे कंपनी ने संगीत, सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, फर्नीचर, खाद्य पदार्थ सहित खिलौने भी बेचने शुरू किए। किंडल, फायर टैबलेट, इको जैसे अमेजन के कई उत्पाद आज दुनिया के लोकप्रिय उत्पादों में शुमार हैं। इसके संस्थापक जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं।

इधर-उधर की

मुर्गे की बांग बनी राष्ट्रीय बहस

पेरिस, एजेंसी : फ्रांस का खूबसूरत ओलरिन द्वीप इस समय एक मुर्गे को लेकर सुर्खियों में है। मुर्गे की बांग को लेकर शुरू हुई अदालती लड़ाई राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ चुकी है। दरअसल, यहां की एक महिला ने मुर्गा पाल रखा है। उसकी सुबह की बांग से तंग आकर एक बुजुर्ग दंपती ने अदालत में गुहार लगा दी। इनका आरोप है कि रोजाना मुर्गे की आवाज से इनकी नींद खराब हो जाती है। इससे औरों को भी परेशानी होती है। अब यह अदालती लड़ाई राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ चुकी है। चूंकि मुर्गा फ्रांस के राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है लिहाजा कुछ लोग इस मामले में मुर्गा और उसके मालकिन के साथ खड़े हो गए हैं। मालकिन की दलील है कि वे अपने मुर्गे को शेड में रखती हैं और उसकी लाइट बुझा देती हैं। जिससे अंधेरे के चलते वह बांग न दे सके। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस खबर पर प्रतिक्रिया देने वाले भी दो धड़ों में बंट चुके हैं।

स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है 5जी नेटवर्क !

- रहन-सहन का तौर-तरीकों में आ सकता है नाटकीय बदलाव
- विकिरण के संपर्क में आने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की है आशंका

5जी नेटवर्क शुरू होने पर बढ़ेगी मोबाइल टावरों की संख्या। प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, आइएएनएस : इंटरनेट की दुनिया में सबसे तेज 4जी नेटवर्क के बाद अब 5जी यानी पांचवीं पीढ़ी के नेटवर्क के प्रसार की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। दुनिया भर में इंटरनेट की बढ़ती मांग के कारण 4जी नेटवर्क अब ओवरलोडिंग का शिकार हो रहा है। इससे निपटने के लिए 5जी को लाया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि 5जी के आने से हमारे रहन-सहन का तौर-तरीकों में नाटकीय बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, इस नेटवर्क का प्रसार होने के बाद रेडियोफ्रीक्वेंसी (आरएफ) विकिरण के संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों के बारे में चिंता भी जताई जा रही है।

5जी नेटवर्क के शुरू होने पर जाहिर सी बात है मोबाइल टावरों की संख्या बढ़ेगी और आरएफ सिग्नल की ताकत बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में विकिरण से स्वास्थ्य खराब होने की आशंका भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित सुरक्षा के मानकों का पालन होता रहेगा तब तक आरएफ से डरने की जरूरत नहीं है।

बढ़ता है शरीर का ताप : विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी आरएफ सिग्नलों के संपर्क में आने की आशंकाओं को कम किया है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, आरएफ के परिक्षेत्र में आने से शरीर का ताप बढ़ता है और तापमान में मामूली वृद्धि लोगों के स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करती है।

भ्रम पैदा करता है विकिरण शब्द : फोर्टिस अस्पताल, नोएडा में कार्डियक सर्जरी विभाग के अतिरिक्त निदेशक वैभव मिश्रा ने कहा 'रेडिएशन यानी विकिरण शब्द भ्रम साथ-साथ भय और गलतफहमी भी पैदा करता है।' उन्होंने कहा कि विकिरण दो प्रकार के होते हैं-आयनीकृत और गैर-आयनीकृत। मोबाइल उपकरणों से निकलने वाला विकिरण गैर-आयनीकृत होता है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि आयनीकृत विकिरण से सावधान रहने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए सूर्य द्वारा उत्सर्जित पराबैंगनी किरणें (यूवी) प्रकृति में आयनीकरण का कारण बन सकती हैं। मिश्रा ने कहा कि इससे हमारी कोशिकाओं को काफी नुकसान पहुंच सकता है। दरअसल विकिरण का सवाल इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 5जी की गति 4जी के मुकाबले कई ज्यादा होगी और इसके लिए तीव्र विकिरण की भी आवश्यकता होती है। लेकिन अभी तक किसी भी वैश्विक अध्ययन में इस विकिरण से मानव शरीर पर नकारात्मक प्रभावों के तथ्य सामने नहीं आए हैं। जिसके आधार पर माना जा रहा है कि 5जी लोगों के शरीर प्रभावित नहीं करेगा।

नई दिल्ली में इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिट के तरुण साहनी ने बताया कि ईसीजी पेसमेकर, अल्ट्रासाउंड जैसे कई उपकरणों में अल्ट्रासाउंड के लिए उच्च स्तर की रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा स्मार्टफोन में इनका उपयोग होता है। लेकिन लोगों से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों के बारे अभी तक पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाए हैं। हालांकि, उन्होंने आगाह किया है कि यदि किसी भी वस्तु ज्यादा उपयोग किया जाता है तो इससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर जरूर पड़ता है। भले ही वह छोटा बड़ा क्यों न हो।

फिल्म रिव्यू

एकतरफा प्यार की घिसी-पिटी कहानी

हमें तुमसे प्यार कितना

निर्देशन : ललित मोहन
प्रमुख कलाकार : करणवीर बोहरा, प्रिया बनर्जी, समीर कोचर
अवधि : 1 घंटा 31 मिनट

एकतरफा प्यार और प्यार को पाने की चाहत में सिरफिरे और जुनूनी प्रेमी की कहानी बॉलीवुड में कोई नई नहीं है। 'डर' और 'दरार' जैसी फिल्में इस विषय पर बन चुकी हैं। कहानी एक एक्सीडेंट के साथ शुरू होती है और फिर अतीत में जाती है। अनन्या (प्रिया बनर्जी) की बुक लॉन्च पर ध्रुव (करणवीर बोहरा) लेखिका का ऑटोग्राफ पाकर इतना दीवाना हो जाता है कि अनन्या के घर के सामने एक कैफे खोल लेता है। अनन्या कॉलेज में प्रोफेसर हैं। वह स्टूडेंट्स को कहानियां लिखना सिखाती हैं। ध्रुव भी उनका स्टूडेंट बन जाता है। अनन्या को रणवीर (समीर कोचर) से प्यार है। दोनों शादी करने वाले हैं। ऐसे में एकतरफा प्यार में पागल ध्रुव अपने आसपास काल्पनिक दुनिया रचने लगता है।

ललित मोहन द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी में कोई नयापन नहीं है। राहुल पटेल, नंदन और ललित मोहन के कमजोर स्क्रीनप्ले के चलते आगे की कहानी का अंदाजा आसानी से लग जाता है। ध्रुव पहले अनन्या से कहां मिला, एक मुलाकात में प्यार कैसे हो गया, इसकी गहराई में लेखक नहीं गए हैं। खून से खत लिखने वाला दृश्य आज के जमाने में फिट नहीं बैठता। इस रोमांटिक थ्रिलर में थ्रिल की कमी है।

करणवीर बोहरा की यह पहली बॉलीवुड फिल्म है। टीवी पर उनका अभिनय पसंद किया जाता रहा है, लेकिन इस फिल्म में जुनूनी प्रेमी के किरादर में वह प्रभावशाली नहीं लगे हैं। प्रिया बनर्जी और समीर कोचर भी अपने अभिनय से छाप नहीं छोड़ पाए हैं। गेस्ट अपीयरेंस में जूही चावला सहज लगी हैं। अमर मोहिले का बैकग्राउंड स्कोर खास नहीं है। फिल्म के गाने थोड़ा सुकून देते हैं। वर्ष 1981 में रिलीज फिल्म 'कुदरत' के सुपरहिट गाने 'हमें तुमसे प्यार कितना...' को सोनू निगम की आवाज में रीक्रिएट किया गया है, जो सुनने में अच्छा लगता है। सिनेमैटोग्राफर संतोष थुंडियाल ने हिमाचल की खूबसूरती को गानों में दिखाने की कोशिश की है।

प्रियंका सिंह

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

फोन का 'फिंगरप्रिंट' बना रही हैं कंपनियां

ट्रैकिंग ▶ गुपचुप तरीके से कई वेबसाइट और एप जुटा रहे हैं यूजर का डाटा

न्यूयॉर्क टाइम्स से

बहुत छोटी-छोटी जानकारियां लेकर तैयार होता है यूजर का प्रोफाइल

डाटा के जरिये कंपनियां यह पता कर सकती हैं कि लोग एप का कैसे इस्तेमाल करते हैं। प्रतीकात्मक

वाशिंगटन : बात अगर डिजिटल प्राइवेसी की हो तो एक बात तय है कि कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है। एक ओर बड़ी टेक कंपनियां डाटा की हिफाजत में लगी हैं, तो दूसरी ओर सैकड़ों कंपनियां इसमें सेंध लगाने की कोशिश में जुटी हैं। दोनों पक्षों के बीच 'तू डाल-डाल, मैं पात-पात' का खेल चलता रहता है। डाटा में सेंध लगाने की एक नई कोशिश का नाम है 'फिंगरप्रिंटिंग'। कुछ कंपनियां यूजर के फोन और कंप्यूटर सिस्टम का फिंगरप्रिंट तैयार करके यूजर की गतिविधियों को पहचानती हैं। जैसे किसी इंसान के फिंगरप्रिंट यानी अंगुलियों के निशान से उसकी पहचान आसानी से हो सकती है। ऐसे ही यह डिजिटल फिंगरप्रिंट भी किसी यूजर की पहचान बताने में सक्षम होता है। इसकी मदद से कुछ एप और वेबसाइट यूजर की गतिविधियों को ट्रैक करती हैं और उसके हिसाब से विज्ञापन देती हैं। इस डिजिटल फिंगरप्रिंट को अन्य कंपनियों को भी बेचा जा सकता है। फिलहाल यह बहुत खतरनाक तो नहीं है, लेकिन चिंता की बात जरूर है।

निजता पर सख्त हैं बड़ी कंपनियां : पिछले कुछ वर्षों के दौरान एपल और मोजिला जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने यूजर्स की निजता की दिशा में कड़े कदम उठाए हैं। इनके वेब ब्राउजर में ट्रैकिंग को रोकने की सुविधा दी गई है। इन कदमों के चलते विज्ञापन कंपनियों के लिए वेब से जुड़ी हमारी गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल होता जा रहा है। इस सख्ती ने ही अब इन कंपनियों को दूसरा रास्ता अपनाने को प्रेरित किया है। इसी दूसरे रास्ते का नाम है 'फिंगरप्रिंटिंग'।

मजबूरी है कुछ डाटा देना : आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो वह आपके कंप्यूटर या फोन के बारे में कुछ जानकारियां लेती है। इसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी और अन्य कॉन्फिगरेशन से जुड़े डाटा शामिल रहते हैं। वेबसाइट को सुचारू ढंग से चलने के लिए इन डाटा की जरूरत पड़ती है। इसी तरह फोन पर पहली बार कोई एप चलाने के लिए भी उसे कुछ जानकारियों की जरूरत पड़ती है। इनमें आपके एंड्रॉयड का वर्जन और हार्डवेयर से संबंधित अन्य जानकारियां शामिल रहती हैं।

कैसे काम करती है फिंगरप्रिंटिंग? : फिंगरप्रिंटिंग इसी मजबूरी में अपने लिए जगह तलाशती है। वह उन्हीं डाटा को इकट्ठा करती है जो किसी एप या वेबसाइट के सही से काम करने के लिए जरूरी होते हैं। इसमें आपके सिस्टम के स्क्रीन रेजोल्यूशन, ऑपरेटिंग सिस्टम और मॉडल से जुड़ा डाटा लिया जाता है। इसी डाटा की मदद से कंपनियां इस बात पर निगाह रखती हैं कि आप वेब और एप का कैसे इस्तेमाल करते हैं। लंबे समय तक अगर किसी यूजर के फोन से इस तरह का डाटा जुटाया जाए, तो वह यूजर की आदतों और गतिविधियों के बारे में बहुत कुछ बताता है। इन डाटा को जुटाकर कंपनियां यूजर का एक पूरा प्रोफाइल बना लेती हैं, जिससे यूजर की पहचान तैयार हो जाती है। शिंगटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में इस प्रोफाइल को यूजर की पहचान के मामले में 99 फीसद तक कारगर पाया है।

हृदय रोगों ने निजात दिला सकता है यह बैक्टीरिया

लंदन, आइएएनएस : मनुष्यों की आंत में पाया जाने वाला अक्करमेंसिया म्यूसिनीफिला नामक बैक्टीरिया का पाश्चुरीकरण कर उपयोग करने से हृदय रोगों के उपचार में मदद मिल सकती है। ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने अध्ययन कर यह दावा किया है। यह अध्ययन 'नेचर मेडिसिन' में प्रकाशित हुआ है।

लोवेन यूनिवर्सिटी के शोधार्थियों की टीम ने इस अध्ययन के परीक्षण के लिए 42 प्रतिभागियों को नामांकित किया और 32 लोगों ने परीक्षण को पूरा किया। शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों को अक्करमेंसिया दिया, इन सभी में डायबिटीज टाइप 2 और मेटाबोलिक सिंड्रोम के लक्षण देखे गए थे, जिसका मतलब है कि इनमें दिल की बीमारियों से संबंधित जोखिम के कारक मौजूद थे। अध्ययन के लिए शोधर्ताओं ने प्रतिभागियों को दो समूहों में बांटा। पहले समूह ने एक जीवित बैक्टीरिया लिया और दूसरे समूह ने पाश्चुरीकृत बैक्टीरिया लिया। साथ ही इन दोनों समूहों के सदस्यों में अपने खान-पान और शारीरिक गतिविधियों में परिवर्तन करने के लिए भी कहा गया। इन्हें अक्करमेंसिया न्यूट्रीशनल सप्लीमेंट के तौर पर तीन महीने तक सेवन के लिए दिया गया।

अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि जीवित और पाश्चुरीकृत बैक्टीरिया लेने वाले समूहों में कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। पाश्चुरीकृत बैक्टीरिया ने प्रतिभागियों में डायबिटीज 2 और दिल की बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम कर दिया। इससे लिवर के स्वास्थ्य में भी सुधार देखा गया, प्रतिभागियों के शारीरिक वजन में भी गिरावट देखी गई।

शोध अनुसंधान

सुबह जल्दी जागने से कम होता है कैंसर का खतरा

सुबह जल्दी जागने वाली महिलाओं में अन्य की तुलना में स्तन कैंसर का खतरा कम रहता है। ताजा अध्ययन में यह बात सामने आई है। वैज्ञानिकों ने दो अध्ययनों यूके बायोबैंक स्टडी और ब्रेस्ट कैंसर एसोसिएशन कंसोर्टियम स्टडी में शामिल चार लाख से ज्यादा महिलाओं के डाटा का विश्लेषण किया। इसमें पाया गया कि सुबह जल्दी जागने वाली महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा कम रहता है। इसी तरह नींद की अवधि और अनिद्रा से भी स्तन कैंसर पर प्रभाव देखा गया। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि सात-आठ घंटे से ज्यादा सयम तक सोते रहने से भी स्तन कैंसर का खतरा अपेक्षाकृत बढ़ जाता है। - प्रेट्र

दिल पर भारी पड़ता है बैठकर टीवी देखते रहना

यह बात कई शोध में सामने आई है कि बैठे रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ताजा शोध में यह पाया गया है कि बैठे रहकर आप क्या करते हैं, इससे भी असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर बैठे-बैठे काम करने से दिल को उतना खतरा नहीं है, जितना खतरा बैठकर टीवी देखते रहने से है। जर्नल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में प्रकाशित शोध में कहा गया है कि आप क्या करते हुए समय बिताते हैं, इसका दिल पर बहुत असर पड़ता है। वैज्ञानिकों ने 3,592 लोगों पर करीब 8.5 साल तक अध्ययन किया। इस दौरान यह भी देखा गया कि लोग व्यायाम में कितना समय बिताते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि व्यायाम करने से बैठे रहकर दिल को होने वाला नुकसान कम करने में मदद मिलती है। - प्रेट्र

आजादी का जश्न

बेलारूस की राजधानी मिंस्क में आजादी के पर्व पर भव्य मिल्ट्री परेड के बाद आतिशबाजी करके जश्न मनाया गया। इस दिन देश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस ऐतिहासिक दिन की याद में पूरे देश में उत्सव होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा आतिशबाजी का प्रदर्शन इसका मुख्य आकर्षण है। रायटर

रंगों ने बदल दी रंगत

रंगों का जीवन में खास महत्व है। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया की राजधानी लापेज के चुआ हुमा में घर की दीवारों पर बने भित्ती चित्रों को निहारती महिला। इस कला के जरिए पूरे शहर की रंगत ही बदल गई है। इन देशों में जहां गरीबी और मानवाधिकारों की लड़ाई के संघर्ष का लंबा इतिहास है, वहीं अब रंगों की बदौलत समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। यहां गलियों और घरों की दीवारों पर बनाए गए चित्र प्रेरणा का काम करते हैं। रायटर

स्क्रीन शॉट

अर्जुन कपूर के साथ संबंधों पर बेबाक होकर बोलीं मलाइका

अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा की जोड़ी इन दिनों सुर्खियों में छाई रहती है। दोनों ने अपने प्रेम-संबंधों को सार्वजनिक तौर पर भले ही स्वीकार न किया हो, लेकिन दोनों अक्सर पार्टियों, सार्वजनिक समारोहों में साथ नजर आते हैं। यह स्टार जोड़ी निजी जिंदगी में खुश दिखती है, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया जाता है। बीते दिनों मलाइका ने सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा की थी, जिसमें वह अर्जुन के जन्मदिन पर उनके हाथ में हाथ डाले नजर आ रही थीं। अब उन्होंने अपने आपसी संबंधों पर खुलकर बात की है। अर्जुन उनसे उम्र में करीब 11 साल छोटे हैं। मलाइका का कहना है कि उम्र उनके रिश्तों में आड़े नहीं आती है। अर्जुन उन्हें समझते हैं। वह उनके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। इसी से सभी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। उम्र में फासले को लेकर मलाइका का कहना है कि उम्र में अंतर होने से उनके संबंधों पर फर्क नहीं पड़ता। उनके मुताबिक, उम्र के आधार रिश्तों को जज करना ठीक नहीं है। किसी महिला को कम उम्र शख्स से प्यार क्यों नहीं मिल सकता? जबकि पुरुषों के मामले में इस पर बात नहीं होती। अगर कोई इंसान उन्हें खुश रखता है तो वह उनके साथ क्यों नहीं हो सकतीं। यह कैसे किसी और के लिए हानिकारक है। गौरतलब है कि पिछले साल प्रियंका चोपड़ा द्वारा अपने से दस साल छोटे अमेरिकी सिंगर निक जोनास से शादी करने पर भी उन्हें काफी ट्रोल किया गया था।

'बारोट हाउस' में मंजरी फड़नीस के साथ होंगे अमित साध

इन दिनों डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए फिल्में खूब बन रही हैं और पसंद भी की जा रही हैं। खबर है कि अभिनेता अमित साध ऐसी ही सस्पेंस ड्रामा फिल्म 'बारोट हाउस' में मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। अमित साध को पिछली बार अक्षय कुमार की फिल्म 'गोल्ड' में देखा गया था, अब वे वेब प्लेटफॉर्म जी5 की इस फिल्म में मंजरी फड़नीस के साथ नजर आएंगे। खबर है कि

यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। अमित साध का कहना है, 'बारोट हाउस जिस सच्ची घटना पर बनी है, जब मैंने उसके बारे में जाना, तो उसने मुझ पर बहुत प्रभाव डाला। मेरा किरदार काफी उलझे हुए शख्स का है और इसमें भावनाओं के अनेक रंग भी दिखाई देंगे। इस तरह की भूमिका मैंने इसके पहले कभी किसी फिल्म में नहीं की है। फिल्म की कहानी काफी प्रभावशाली है और इसमें दर्शकों की उत्सुकता अंत तक बनी रहती है। संजीव के झा द्वारा लिखी गई इस फिल्म में अमित साध और मंजरी फड़नीस की मुख्य भूमिकाओं के अलावा बाल कलाकारों की भी उपस्थिति है। वे हैं - आर्यन मेंघजी, कियारा सोनी और किशा अरोड़ा आदि।' अमित साध ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग दमन के एक छोटे से तटवर्ती शहर में की गई है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की रिलीज 7 अगस्त को संभावित है।

हिमांशु शर्मा से अलग हुईं स्वरा भास्कर!

अभिनेत्री स्वरा भास्कर अदायगी के अलावा अपनी बेबाक राय की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। उन्होंने हमेशा अपनी निजी जिंदगी पर भी खुलकर बात की है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया था कि वह राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता स्क्रीन राइटर हिमांशु शर्मा के साथ रिलेशनशिप में हैं। अब करीब पांच साल रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों के बीच अलगाव होने की खबरें हैं। दोनों की मुलाकात 'रांझणा' फिल्म के दौरान हुई थी। 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी थीं। फिल्म 'वीरे दी वेडिंग' की सफलता के बाद वे दोनों यूरोप में छुट्टियां मनाने भी साथ गए थे। दोनों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर उन दोनों में मतभेद हो गए थे। जिसके चलते आखिरकार दोनों आपसी सहमति से एक-दूसरे से अलग हो गए हैं। हालांकि दोनों की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है।

अध्ययन

एप्लाइड एर्गोनॉमिक्स जर्नल में प्रकाशित हुए अध्ययन में शोधार्थियों ने दिया सुझाव, बस्तों का भार बच्चे के कुल भार का 20 फीसद से ज्यादा ना हो

बच्चों के लिए बस्तों से बेहतर हैं ट्रॉली बैग

- स्पेन के शोधकर्ताओं ने अध्ययन के आधार पर निकाला निष्कर्ष
- पारंपरिक बस्तों से बच्चों के विकास पर पड़ता है असर
- कंधे और पीठ दर्द से परेशान रहते हैं बच्चे

अभिभावकों के लिए भी चिंता का विषय है बस्तों का बढ़ता बोझ। प्रतीकात्मक

मैड्रिड, आइएएनएस : स्कूल बैग का बढ़ता बोझ अभिभावकों के लिए चिंता का विषय रहा है। भारी बस्तों की वजह से बच्चों के कंधों पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है और बच्चों को दर्द से परेशान रहते हैं। कई अध्ययन यह भी बताते हैं कि इससे बच्चों की लंबाई पर भी फर्क पड़ सकता है। बस्तों के बोझ से निजात पाने के लिए स्पेन के शोधकर्ताओं ने अध्ययन कर सुझाव दिया है कि यदि पारंपरिक बस्तों की जगह बच्चों को ट्रॉली बैग दिया जाए तो समस्या बहुत हद तक कम हो सकती है।

एप्लाइड एर्गोनॉमिक्स जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में यह भी सुझाव दिया गया है कि बच्चों के बस्तों का भार उनके कुल भार का 20 फीसद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही बात ट्रॉली बैग पर भी लागू होती है। इससे उनके शरीर पर असर पड़ सकता है।

अक्सर यह देखने में आता है कि बैगपैक यानी पारंपरिक बस्तों से बच्चों के शारीरिक विकास पर असर पड़ता है। भारी बस्तों के कारण कई बच्चों की कमर झुक जाती है और वह ठीक से चल भी नहीं पाते। शोधकर्ताओं का दावा है कि ट्रॉली बैग का प्रयोग करने पर ये समस्याएं नहीं आती हैं। ग्रेनेडा और लिवरपूल जॉन मूरस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस अध्ययन के लिए स्पेन के 49 प्राथमिक स्कूल बच्चों का आकलन कर दावा किया है कि बस्ते के मुकाबले ट्रॉली बैग उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है।

शोधकर्ताओं ने बताया कि स्पेन में 40 प्रतिशत से अधिक बच्चे ट्रॉली बैग का प्रयोग करते हैं, लेकिन ज्यादातर पारंपरिक बस्तों को लेकर ही स्कूल जाते हैं। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने बच्चों के कुल भार का 10, 15 और 20 फीसद भार वाले ट्रॉली बैग और पारंपरिक बस्ते तैयार किए और उन्हें बच्चों को उपयोग के लिए दिया। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं पाया कि जो बच्चे पारंपरिक बस्तों का प्रयोग कर रहे है थे उनकी चाल, शरीर की गतिविधियां ट्रॉली बैग का प्रयोग करने वाले बच्चे के मुकाबले भिन्न थीं।

शोधकर्ताओं ने पाया कि उनकी कमर और घुटनों में पारंपरिक बस्तों का सबसे ज्यादा असर देखा गया। भार के कारण बच्चों के कूल्हे और सीने में दर्द की शिकायत देखी गई। वहीं, जिन बच्चों ने ट्रॉली बैग का प्रयोग किया वे न सिर्फ आसानी से स्कूल जा पाए बल्कि उनके शरीर की गतिविधियों पर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा।